असंशोधित

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

25 फरवरी, 2021

सप्तदश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 25 फरवरी, 2021 ई0
द्वितीय सत्र — 06 फाल्गुन, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होंगे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कल जो सदन में की गयी असंसदीय टिप्पणी की बात थी उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है । मैं अभी भी मांग करता हूँ सरकार से कि ऐसे गैर संसदीय टिप्पणी करने पर उनको सरकार से बर्खास्त करने की मांग करता हूँ और आपसे आग्रह है कि इस समस्या का संज्ञान लिया जाय । महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और कल भी उन्होंने विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ असंसदीय बात की । वे ऊंचे मंत्री पद पर हैं इसलिए हम मानते हैं कि यह पूरे सदन का अपमान है, यह केवल एक माननीय विधायक का अपमान नहीं है । इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इन बातों का संज्ञान लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज भी हम सभी दलीय नेताओं के साथ बैठे हैं । हम एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि इस सदन को चलाने में सभी माननीय सदस्यों के द्वारा जो मेहनत की जाती है और बिहार की जनता की जो अपेक्षा है जिसकी जिम्मेवारी हम सभी सदस्यों पर है उन सदस्यों को अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करने में हमारे सभी वरीय सदस्य सहयोग करें । अपने नये सदस्य काफी उत्साहित हैं और बहुत ही शालीनता के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें मैं बधाई भी देता हूँ । उनके मन के अंदर सकारात्मक भाव बने इसलिए सदन को चलाने में सबलोग सहयोग करें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कल भी बहुत विस्तार से आपने भी कहा, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने भी अपनी बात रखी लेकिन माननीय मंत्री जी बैठे-बैठे ऐसी टिप्पणी करते हैं । महोदय, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल भी सरकार के अंग हैं, लेकिन ये लोग विरोधी पार्टी मान लेते हैं सदन के अंदर और ऐसी-ऐसी टिप्पणी करते हैं तो कुछ आगे नहीं हो इसलिए आपसे आग्रह है, संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह है कि यदि सरकार सदन चलाना चाहती है तो ठीक है, हमलोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी बतावें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार की तरफ से कल भी बातों को रखा था कि कल कुछ ऐसी बातें हो गयीं जिससे माननीय सदस्य और सी0पी0आइ0एम0एल0 के नेता

श्री महबूब आलम जी की भावना आहत हुई । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और हमने कल भी कहा कि सरकार की मंशा सदन का जो सम्मान है और अलग-अलग हम सभी जो विधायक हैं, हम सबका मान बराबर है और सब जनता का मैनडेट लेकर, जनता का आदेश लेकर ही यहां पहुंचते हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किसी भी माननीय सदस्य का अपमान करने की मंशा सरकार की न है और न ही कभी भविष्य में होगी, यह हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, जहां तक कल की बात है अभी भी माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी आसन से अनुरोध कर रहे थे कि इस बात को संज्ञान में लिया जाय । आप खुद महबूब जी महसूस कर सकते हैं कि आसन या सदन इससे अधिक आपकी बातों का संज्ञान क्या ले सकता है ? हमलोग तो तीन बार बैठ चुके हैं और अध्यक्ष जी ने, आसन ने बड़ी कृपा की है कि इस मुद्दे पर पहल करने की भरपूर कोशिश है और हम समझते हैं कि सकारात्मक माहौल में बातचीत भी हुई है । हम सरकार की तरफ से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि न किसी विधायक की, न किसी दल की और सदन तो सर्वोपरि है । इसके सम्मान पर किसी भी हाल में सरकार किसी भी सूरत में बट्टा नहीं लगने देगी और किसी सदस्य को कभी अपमानित होने की स्थिति सदन में नहीं आयेगी। अभी प्रश्नोत्तर काल है अध्यक्ष महोदय और हमने देखा है कि अल्पसूचित प्रश्न जितने हैं या जो तारांकित प्रश्न हैं अधिकांश माननीय सदस्य जो विरोधी दल के हैं उन्हीं के हैं । सरकार हमेशा मानती है कि आपके जो प्रश्न होते हैं वे सरकार के सहयोग के लिए ही होते हैं, जनता की समस्या के निराकरण के लिए होते हैं और सरकार भी खुले दिल से, खुली मंशा से उन समस्याओं का निदान करना चाहती है क्योंकि सरकार जनहित की समस्याओं का निदान करना ही अपना कर्त्तव्य समझती है । अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमलोग सरकार की तरफ से सभी माननीय सदस्यों से पूरे सदन से आग्रह करते हैं कि सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित चलाने में अपने-अपने तरफ से सहयोग करें, चलने दें तभी आपका भी मकसद पूरा होगा, सरकार का भी मकसद पूरा होगा, सदन का भी मकसद पूरा होगा और जनहित के काम होंगे । यही हमारी विनती है, प्रार्थना है ।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य बैठ जाएं, ध्यान से सुनें । बताइये ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सदन की परंपरा रही है और हमलोग भी चाहते हैं कि हम जनता के सकारात्मक प्रश्नों को लेकर आयें । यह सरकार और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात को रख रहे हैं, सरकार की तरफ से रख रहे हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ । मैं विगत दो टर्म से विधायक रहा हूँ । हमारे पिता दिलकेश्वर राम पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और 1985-90 के कार्यकाल में हमने देखा था कि कर्पूरी ठाकुर जी जो हमारे

प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे और हम अपने पिता जी की जुबान से सुने हैं कि जब चन्द्रशेखर सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब कर्पूरी ठाकुर जी का वक्तव्य आता था तो चन्द्रशेखर बाबू निदेश देते थे सभी माननीय मंत्रियों को कि आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है और उस जिम्मेवारी में आप विपक्ष से भी सकारात्मक सुझाव लें और सरकार को चलाएं ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा ।

श्री राजेश कुमार : इसलिए अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सब भी आपके ही अंग हैं, लेकिन कई बार सम्मानित मंत्री महोदय टीका-टिप्पणी में आते हैं, अब ऐसा नहीं होगा इसी उम्मीद से बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : बहुत खुशी है, सबका बहुत सकारात्मक भाव है ।

''सबसे रश्मो राह रखिये,
दिल में बुलंदियों की चाह रखिये ।
भटक न जाइये जनहित के मुद्दों से,
इसलिए खुद पर निगाह रखिये ।''

माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नोत्तरकाल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

टर्न-2/हेमंत-राहुल/25.02.2021

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के लिए इस सदन में उपयोगी और जरूरी बातें लिखी हुई हैं, सामने ही लिखा हुआ है कि भाषण स्वतंत्रता का अर्थ आत्म नियंत्रण है, यह सब पर लागू होना चाहिए । विनय और संयम संसदीय भाषा के गुण हैं, इसको हम सब लोग अपने-अपने पर लागू कर लेंगे तो सदन सुचारू रूप से चलेगा ।

अध्यक्ष: अब अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे । श्री सुधाकर सिंह ।

## प्रश्नोत्तर-काल

## अल्पसूचित प्रश्न-10 (श्री सुधाकर सिंह)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: एक मिनट रुकिए मंत्री जी ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा उनकी भावना बहुत उत्कृष्ट है । विनय और संयम की जहां तक बात है अभी भी यह साबित हो रहा है कि कल भी संसदीय कार्य मंत्री जी ने और ग्रामीण विकास मंत्री जी ने खेद भी व्यक्त किया,

उनको यह भी अहसास हुआ कि गलत आचरण किया गया और इसके बावजूद आज भी हो रहा है । लेकिन आज भी विनय और संयम का परिचय देकर के जो माननीय मंत्री जी हैं, वह खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं, महोदय ।

अध्यक्षः ठीक है महबूब साहब, आप सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ें, बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । यह सही है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत 16 अरब 92 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति की गयी थी, परंतु प्रक्रियात्मक कारणों एवं ससमय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण परिकल्पित स्वरूप में मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत योजना को लागू नहीं किया जा सका । महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांकः 08.09.2020 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद संख्या-21 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से प्राप्त 439.05 करोड़ 4 अरब 39 करोड़ 5 लाख रुपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की 2 हजार 927 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किया जाना है । महोदय, अभी तक योजना के अंतर्गत चयनित 2023 पैक्सों को प्रति पैक्स 50 परसेंट ऋण और 50 परसेंट अनुदान के रूप में इसकी दर से कुल 3 अरब 3 करोड़ 45 लाख रुपये जिलों को उपलब्ध करा दिए गए हैं । चयनित पैक्सो द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से कृषि यंत्रों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है ।

श्री सुधाकर सिंहः अध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल से एन0सी0डी0सी0 से पैसा मिला हुआ है और एक साल बाद सरकार योजना लागू करने की बात कह रही है, पिछले एक साल से जो लोन लिया गया है उस पर जो ब्याज लगा है उस ब्याज की भरपाई, जिस अधिकारी के दोष से अभी तक यह यंत्र स्थापित नहीं किया गया सालभर के भीतर, किन लोगों से की जाएगी जो एक साल से पैसा रखे हुए हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्षः ऐसा कैसे होगा दो-दो सप्लीमेंट्री कैसे पूछ सकते हैं ? आप बैठ जाइए, उनका पहले होने दीजिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य अगर जानना चाहते हैं तो डिटेल मैं दे दूं, एक साल पहले जो वैश्विक महामारी आई है उसको हम लोग जानते हैं, उसके कारण सारी परेशानियां हुई हैं और उसके कारण ही यह योजना भी प्रभावित हुई है । महोदय, मंत्रिपरिषद्

द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आलोक में योजना कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 2325, दिनांक- 17.09.2020 में निर्गत किया गया । महोदय, इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों के क्रय, संचालन, अनुश्रवण आदि से लाभुकों को अवगत कराने हेतु ज्ञापांक-5350, दिनांक-24.09.2020 द्वारा कार्यान्वयन एवं अनुदेश निर्गत किया गया था । योजनांतर्गत राशि की निकासी हेतु विभागीय ज्ञापांक संख्या-115, दिनांक- 22.09.2020 द्वारा स्वीकृत आदेश निर्गत किया गया । सभी जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिलास्तरीय समन्वय समिति के चयन की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से चयनित 2023 पैक्सों के लिए प्रति पैक्स 15 लाख रुपये की दर से 303.45 करोड़ रुपये का आवंटन आदेश संख्या-नि0आ0, दिनांक 24.09.2020 को निर्गत करते हुए सभी जिलों को राशि उपलब्ध करा दी गई है । कोविड-19 महामारी बिहार विधान सभा एवं पैक्स, निर्वाचन के कारण, निर्वाचन भी आया है बीच में और पैक्स का निर्वाचन भी चला है, इसके कारण भी परेशानी आई है, इसके कारण योजना कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है । योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से किया जाना है, जैम पोर्टल पर कृषि यंत्रों के क्रय की प्रक्रिया, व्यावहारिक प्रशिक्षण दिनांक 01.12.2020, 04.12.2020, 18.01.2021, 19.01.2021, 04.02.2021 एवं 05.02.2021 को आयोजित किया गया, प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया । दिनांक 04.02.2021 से जैम पोर्टल पर निविदा की प्रक्रिया प्रारम्भ है, जो 8 मार्च, 2021 तक निर्धारित है । महोदय, जो अभी चल रहा है अब वह पूरा हो जाएगा । मैं समझता हूं कि अब माननीय सदस्य संतुष्ट हो गए होंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है, माननीय सदस्य, आपने इतना बड़ा जवाब दिया, अब सुन लीजिए । माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न का जवाब ऑनलाईन नहीं आया है, आप ऑनलाईन जवाब डाल दें ताकि पूरक प्रश्न हो, समय कम है, ज्यादा से ज्यादा सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकें ये ध्यान में रखें । अब श्री अजीत शर्मा जी ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए और दूसरे सदस्यों का होने दीजिए 20 मिनट का समय है । श्री अजीत शर्मा जी । माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इनकी जगह पर श्री आनन्द शंकर जी प्रश्न पूछेंगे ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न-11 (श्री अजीत शर्मा)</u>

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, (क) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

पेयजल हेतु अनुमान्य सीमा पार्ट पर विलियन 10 पी0पी0बी0, एक किलोग्राम प्रति लीटर से अधिक आर्सेनिक युक्त पानी का उपयोग लम्बे

समय तक पेयजल के रूप में करने पर मनुष्य में चर्मरोग, कैंसर आदि होने की संभावना रहती है ।

(ख) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य में 14 जिलों...

अध्यक्ष: माननीय मंत्री उत्तर संलग्न है ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री: 14 जिलों यथा पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया तथा लखीसराय में आर्सेनिक की मात्रा पेयजल में अनुमान्य सीमा से अधिक पाई गई है एवं इन जिलों में लगभग 7,55,103 घर प्रभावित हैं । मुजफ्फरपुर जिला आर्सेनिक प्रभावित नहीं है ।

(ग) हर घर नल जल योजना अंतर्गत आर्सेनिक प्रभावित कुल 4,742 वार्डों में से 3,664 वार्डों में जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर घर में नल के माध्यम से की जा रही है । शेष कार्य प्रगति में है, जिसे मार्च, 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष: श्री समीर कुमार महासेठ । माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री आनन्द शंकर सिंह: सर, पूरक है । जिन-जिन वार्डों में आर्सेनिक युक्त पेयजल है वहां कौन सा संयंत्र लगाया गया है जिससे कि उनको आर्सेनिक मुक्त जल मिले ?

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री: आप जहां प्रश्न किए हैं उसके जवाब में मैंने एकदम स्पष्ट बताया है कि मुजफ्फरपुर जिला आर्सेनिक प्रभावित है ही नहीं ।

श्री आनन्द शंकर सिंह: सर, इसमें मुजफ्फरपुर जिले की ही नहीं, पूरे बिहार के 18 जिलों की बात है.

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप अलग से प्रश्न कर लें ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री: आप अलग से प्रश्न कर लें, आपका जवाब आएगा ।

अध्यक्ष: आप बैठ जाइए, आनन्द जी । चलिए समीर कुमार महासेठ जी । मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया बैठे-बैठे न बोलें ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न-12 (श्री समीर कुमार महासेठ)</u>

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, पटना नगर निगम में गीले एवं सूखे कचरे का पृथक-पृथक रूप में संग्रहण किया जा रहा है । गीले कचरे के प्रसंस्करण हेतु 325 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो कम्पोस्टिंग प्लांट कार्यरत है, इसी प्रकार सूखे कचरे के प्रसंस्करण हेतु 5 मीट्रिक

टन की क्षमता का एम0आर0एफ0 सुविधा उपलब्ध है तथा एक और एम0आर0एफ0 मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है, इसके अतिरिक्त 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण का प्लांट सी0आई0पी0ई0टी0 (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नॉलोजी) के सहयोग से स्थापित है, जहां तक पटना स्थित रामचक बैरिया में कचरे के प्रसंस्करण का प्रश्न है वहां पर भी बायोमाइलिंग पद्धति से सूखे कचरे के प्रसंस्करण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है । इसके अतिरिक्त राज्य के 81 नगर निकायों में सूखे कचरे के प्रसंस्करण हेतु एक-एक मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट स्थापित है एवं गीले कचरे के प्रसंस्करण हेतु 118 नगर निकायों में बायो कंपोस्टिंग प्लांट कार्यरत हैं, शेष नगर निकायों में आवश्यकता के अनुरूप तरल एवं ठोस अपशिष्टों के निपटारे हेतु प्रसंस्करण प्लांट का निर्माण 7 निश्चय-2 के अंतर्गत किया जाएगा।

टर्न-3 एवं 4/राजेश-मुकुल-संगीता/25.02.2021

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा है लेकिन कहीं भी कचरा प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा है । मेरा आग्रह है कि सारे जगहों पर कचरा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कराने का आप वचन दें और केवल समय सीमा बता दें, मूल्य भी कितना लगता है, वह बता दें क्योंकि इससे तरह-तरह की बीमारियां होती हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: देखिए, हमारी सरकार सभी शहरों में आत्म निर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत ये कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तैयारी कर रही है और सभी शहरों में इसको लगाना है और लगायेंगे भी । इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हम इसे करेंगे ।

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 320 (श्री विजय कुमार मंडल)</u>

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग । उत्तर संलग्न है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, हम बोल ही देते हैं ।

1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- नगर पंचायत कौवाथ एवं कोचस में सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु विभाग में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आलोक में लोक वित्त समिति को प्रस्ताव

भेजा जा चुका है । लोक वित्त समिति से स्वीकृति मिलने के उपरांत शीघ्र ही विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी ।

3- उपरोक्त खंडों में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है, यह एक वित्तीय प्रक्रिया है यह वित्तीय प्रक्रिया पूरी जैसे ही होगी उसको निर्माण कार्य के लिए आदेश चला जायेगा ।

श्री विजय कुमार मंडल: अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी ?

अध्यक्ष: जिनका प्रश्न है पहले उनको पूरक पूछने दीजिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: लोक वित्त समिति से इसको पारित होने दीजिए उसको हम तुरंत करेंगे, हम तो बैठक में आपको बताये ही थे ।

श्री विजय कुमार मंडल: समय निर्धारित किया जाय ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अब तो जो विलंब हुआ है उसके लिए हम लोग खुद प्रयास में लगे हुए हैं । राशि पूर्व से भी दी हुई है लोक वित्त समिति से करके उसको करवा देते हैं।

श्री शकील अहमद खॉं: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है एम0एस0पी0 के सवाल पर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर, उसको बाइपास मत कीजिए ।

अध्यक्ष: आप कहां चले गये, अब हम आगे बढ़ गये । बैठिये ।

श्री शकील अहमद खॉं: अध्यक्ष महोदय, नहीं । इसमें है उसमें मेरा पूरक सवाल.....

अध्यक्ष: आप वरीय सदस्य हैं । बैठिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 321 (श्री अरूण शंकर प्रसाद)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग । माननीय श्री अरूण शंकर प्रसाद जी उत्तर संलग्न है ।

(व्यवधान)

डॉ॰ रामप्रीत पासवान, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पंचायती राज विभाग से है, इसे पंचायती राज विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग से अब नहीं हो सकता है इसलिए कि यह जो प्रश्नांकित मिनी पेयजल है, उसको पी0एच0ई0डी0 ने लगाया था, इसलिए उसका

उत्तर पी0एच0ई0डी0 को देना चाहिए कि उसकी क्या स्थिति है । पंचायती राज में अगर वे ट्रांसफर किये हैं तो उसके बारे में बताएं कि किस पत्रांक, दिनांक से प्रश्नांकित मिनी पेयजल को ट्रांसफर किया है विभाग को या फिर अगले दिन इसको रखा जाय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

डॉ॰ रामप्रीत पासवान, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह पहले मिनी जलापूर्ति योजना थी यह बासोपट्टी प्रखंड के कटैया महथौर का । यह वर्ष 2012-13 में 25 लाख रुपये की लागत से जलापूर्ति योजना शुरू की गई थी लेकिन यह योजना बाद में बंद हो गई और जब यह नयी स्कीम चालू हुई तो उसके तहत वह पंचायती राज विभाग में चला गया । मैं माननीय सदस्य को इसका पत्रांक, दिनांक के साथ भेज दूंगा ।

अध्यक्षा: ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 322 (श्रीमती अरूणा देवी)</u>

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम, 2020 के आलोक में विभागीय पत्रांक-1713, दिनांक-14.05.2020, पत्रांक-1769, दिनांक-20.05.2020 एवं पत्रांक-4180, दिनांक-18.12.2020 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों से नये नगर निकायों के गठन, पूर्व से गठित नगर निकायों का उत्क्रमण एवं नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार के संबंध में समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी नवादा से प्राप्त प्रस्ताव में नगर पंचायत पकरीवरावाँ के गठन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, फलस्वरूप उक्त नगर पंचायत के गठन पर विचार नहीं किया गया है । भविष्य में जिला पदाधिकारी नवादा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विचार किया जा सकेगा ।

श्रीमती अरूणा देवी: अध्यक्ष महोदय, वहां पुलिस अनुमंडल भी है और जनसंख्या 30 हजार के लगभग है और वहां से छोटे-छोटे जगहों पर बन गया है और मेरे यहां पकरीवरावाँ में नहीं बना है। हम जाते हैं तो पूरी जनता घेरती है और वहां घुसने नहीं देती है । हम तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को लिखकर भी दिये थे और मिले भी थे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 323 (श्री विनय कुमार)</u>

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्रीः महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वर्तमान स्थिति यह है कि गया जिले के गुरूआ प्रखंड में प्रथम वर्गीय पशु अस्पताल गुरूआ किराये के भवन में संचालित है तथा पशु अस्पताल हेतु जमीन उपलब्ध है । भवन निर्माण विभाग को पशु अस्पताल भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई है । भवन निर्माण विभाग से वर्तमान प्रगति प्राप्त कर भवन पूर्ण करने की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री विनय कुमारः महोदय, यह बता रहे हैं कि भवन निर्माण विभाग को हम लोग राशि उपलब्ध करा दिये हैं और मुझे यह पता है कि लगभग वह 12 वर्ष पहले टेंडर हुआ है और वह अर्द्धनिर्मित भवन है और वहां पर डोर लेवल तक काम करके आज तक वह भवन अर्द्धनिर्मित है और वह सरकारी हमारा जो अस्पताल है वह निजी भवन में चल रहा है जिससे राजस्व की भी क्षति हो रही है और लोगों को वहां पर परेशानी हो रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर पदाधिकारी जो दोषी हैं या जो हमारे संवेदक दोषी हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं और वह भवन बनना चाहिए या नहीं ? यह कह देने से नहीं चलेगा महोदय ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्रीः महोदय, निश्चित तौर पर हमने पैसा उपलब्ध करा दिया है और बहुत जल्द से जल्द मैं इस पर जांच करवाकर शीघ्र ही काम कराने की कोशिश करूंगा ।

श्री विनय कुमारः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक डेट बताएं । जब 12 वर्षों में वह काम नहीं हुआ तो कब बनेगा, 2 एकड़ लगभग वहां पर जमीन है, वह डोर लेवल तक बना है, वह जांच का विषय है और 12 वर्षों से हमारा अस्पताल एक निजी भवन में चल रहा है, यह जनहित का मामला है महोदय ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्रीः महोदय, जमीन की मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुकूल वहां पर जिस समय हम लोगों ने भवन निर्माण विभाग को पेमेंट किया, उस समय तक जमीन की एलीगेशन की वजह से वह रुका पड़ा था, उसके बाद थोड़ा कॉस्ट बढ़ने के कारण, उस पर काम हम लोग बहुत जल्द ही चालू करवायेंगे, दोबारा डी0पी0आर0 में लाकर ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बता दिया जाय ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हम बहुत जल्द से जल्द करा देंगे ।

अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइये । पूरक प्रश्न आपका ये पूछ लिये हैं, अब आप बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न में साफ तौर पर पूछा है कि 20 सालों तक अगर जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी मंत्रालय ने, 12 साल टेंडर हुए हुआ तो जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर वहां भवन का निर्माण नहीं करा पाई है तो उनका सवाल है कि क्या अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी ? कोई समय सीमा बता दी जाय और आपने जो आवंटन/टेंडर के लिए जो पैसा ट्रांसफर किया भवन निर्माण विभाग को, वह कब किया महोदय और उसकी अभी हकीकत क्या है ?

श्री मुकेश सहनी, मंत्री: महोदय, हमने पैसा उपलब्ध करा दिया है और बहुत जल्द ही मैं इस पर जांच करके और इस वित्तीय वर्ष में.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप जानकारी विभाग से लेकर पत्र भेज दीजिएगा ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री: महोदय, इसकी जानकारी मैं सदस्य महोदय को उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, तब तो इस प्रश्न को स्थगित किया जाय, जब तक इसकी जानकारी नहीं आये ? प्रश्न पूछने का मतलब तो यही होता है...

(व्यवधान)

श्री मुकेश सहनी, मंत्री: महोदय, भवन निर्माण विभाग को हमने पैसा अलॉट किया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: आपने पैसा अलॉट कब कराया ?

श्री मुकेश सहनी, मंत्री: महोदय, कब कराया, उसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, संतोषजनक जवाब नहीं होने के कारण इस प्रश्न को स्थगित किया जाय । कार्रवाई के मामले में भी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जायेगी, इस पर भी नहीं बता रहे हैं, आप कार्रवाई करना चाहेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न इन्होंने किया है कि पशु अस्पताल के भवन का निर्माण करने का विचार रखती है या नहीं, तो मंत्री जी ने कह दिया कि हम विचार रखते हैं, हम देख लेते हैं, सकारात्मक जवाब दिये हैं और आपको विशेष जानकारी है, तो फिर प्रश्न करेंगे या मिल लेंगे, तो जवाब मिल जायेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, तब तो सप्लीमेंट्री प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाएगा ?

अध्यक्ष : जो प्रश्न किया गया है, उसका जवाब दिया है उन्होंने ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 324 (श्री कुंदन कुमार )

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, बेगूसराय के प्रतिवेदनानुसार जिले के कुल सात विधान सभा क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर नहीं बल्कि अंचल कार्यालय/भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय के लिए जिले में कुल 59 सरकारी अमीन का पद स्वीकृत है । बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 5 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध बेगूसराय अंचल में एक अमीन पदस्थापित है । अमीन की कमी के कारण भू-मापी एवं विवाद के निपटारे एवं अन्य विशेष परिस्थिति में बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित संविदा अमीन से कार्य कराया जाता है । राज्य के सभी जिलों में अमीन के कुल स्वीकृत पद 1881 के विरूद्ध 1767 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक-420(4), दिनांक 14.11.2019 द्वारा अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को भेजी गई है । बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा कुल 1767 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग की कार्रवाई की जा चुकी है । मुख्य परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त अनुशंसा सूची प्राप्त होते ही अमीन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करायी जायेगी ।

श्री कुंदन कुमार: महोदय, समय बता दिया जाये कब तक ? क्योंकि यह सबसे बड़ी परेशानी है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : सभी लोग गौर से सुनिए । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा संविदा आधारित कुल 534 पदों पर अमीन का नियोजन किया जा रहा है । उक्त पदों पर नियोजन हेतु दिनांक 25 से 27 फरवरी तक चयनित अभ्यथियों का शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्यक्रम निर्धारित है । प्रमाण पत्रों का सत्यापन के उपरांत नियोजित संविदा अमीन को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तत्पश्चात् इन नियोजित कर्मियों से भू-सर्वेक्षण कार्यों के अतिरिक्त अंचल कार्यालयों में राजस्व एवं भूमि मापी आदि कार्य भी कराया जायेगा । इस प्रकार अंचल कार्यालय में राजस्व एवं भूमि मापी आदि कार्यों हेतु अलग से संविदा के आधार पर अमीन के नियोजन की आवश्यकता नहीं है । मैं बहुत जल्द मार्च के अंदर आपको अमीन भेज रहा हूं ।

अध्यक्ष : इतना सकारात्मक जवाब है । अब क्या प्रश्न है ?

श्री कुमार सर्वजीतः महोदय, इसी सदन में आप मंत्री थे । वर्ष 2015-16 में यही प्रश्न का जवाब मिला था कि पूरे बिहार में अमीन की कमी है, एक अमीन जो है 2-2, 3-3 जिला देखता है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वह तो समय भी बता दिए हैं ।

श्री कुमार सर्वजीतः महोदय, वर्ष 2015-16 में आपका जवाब आया था इसी सदन में कि हम अमीन की बहाली कर रहे हैं उसके बाद 5 साल बाद भी महोदय, आज माननीय मंत्री जी के द्वारा वही जवाब दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष : पूरक क्या पूछना है, यह बताइये आप ।

श्री कुमार सर्वजीतः महोदय, तो हम जानना चाहते हैं कि 5 साल में जब आपने नहीं किया, तो कब तक कर देंगे ?

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे विधान सभा के माननीय सदस्यों की पीड़ा मैं समझ रहा हूं, मैं भी विधायक हूं, तब मंत्री हूं, आपकी पीड़ा मार्च में समाप्त कर दी जाएगी ।

अध्यक्ष : बोलिए, जवाब तो स्वागतयोग्य है ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्या -325 (सुश्री श्रेयसी सिंह )</u>

अध्यक्षः माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि जमुई जिला में किसानों से क्रय किए गए धान की प्राप्ति रसीद दी जाती है, साथ ही समिति द्वारा संधारित क्रय-सह-भुगतान पंजी में किसानों से क्रय धान की मात्रा भुगतेय न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि अंकित रहती है,

जिसपर संबंधित किसानों के हस्ताक्षर के उपरान्त ही उनके बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि जमुई जिला में यह रसीद पक्की नहीं काटी जा रही है, जिस कारण से जब किसान अपने भुगतान के लिए वापस पैक्स के पास या व्यापार मंडल के पास जाते हैं तो उन्हें उनके सही एमाउंट की राशि नहीं दी जाती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप वरीय सदस्य हैं, वह अभी पूरक पूछ रहे हैं आप बीच में खड़े हो गये, आप बैठिये । आपको समझना पड़ेगा, आपसे लोग सीखेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, धान क्रय की मात्रा और भुगतये न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि अंकित रहती है उसपर । जिसपर संबंधित किसानों के हस्ताक्षर के उपरान्त ही उनके बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के द्वारा वह राशि जाती है । यदि माननीय सदस्या को कोई स्पेशिफिक जानकारी हो कि इस समिति ने ऐसा किया या फिर पूरे जिले में ऐसा हुआ है तो हम उसकी रिपोर्ट अलग से उनको दे सकते हैं, उसकी जांच करवा सकते हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्य, जवाब दे रहे हैं मंत्री, उसके बाद कहें ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: स्पेशिफिक कहें कि किसी प्रखंड में किसी पैक्स और व्यापार मंडल के द्वारा ऐसा हुआ है तो आप स्पेशिफिक बोलें तो हम उसका जांच करवा देंगे ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, खासतौर से जमुई जिला के ....

अध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य जो प्रश्न करते हैं उनको दो से तीन पूरक पूछने का है अधिकार है । आप धैर्य रखें, उनका पूरक हो जाये तभी उठें । बोलिए ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध है कि इसकी जांच करवा दें और यदि जमुई जिला में ऐसा हो रहा है तो यह सही नहीं है और जिस रसीद की बात की जा रही है उसपर सिर्फ किसान का हस्ताक्षर होता है लेकिन वह कोई पक्की रसीद नहीं होती है । जिस कारण से जब वे लोग अपने भुगतान के लिए जाते हैं, तो वाद-विवाद में उनको सही रकम नहीं मिलती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि अगर स्पेशिफिक कहें तो हम जांच करवा देंगे, पूरे जमुई जिला में करवा दें ? चलिए, जमुई जिला में जांच करवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री आलोक कुमार मेहता: माननीय सदस्य, श्रेयसी जी का सवाल बिल्कुल वाजिब है । सरकार ने नियम बना रखा है कि धान प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर उनको भुगतान किया जाएगा ऑन लाइन । धान प्राप्ति किस दिन और किस समय हुई, जबतक इसके बारे में पक्का ब्यौरा नहीं दिया जायेगा तो कोई कैसे कह सकता है कि 48वें घंटे में उसका पेमेंट हो गया और पूरे बिहार की सच्चाई यह है कि 90 परसेंट, 95 परसेंट ऑफ केसेज में भुगतान 48 घंटे के अंदर नहीं होता है । इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि माननीय सदस्य का जो सवाल है, वह बहुत वाजिब सवाल है और उसको गंभीरता से देखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि किसान जिन लोगों ने अपना धान पैक्स के पास रखा लेकिन वह आज भी असुरक्षित है कि वह धान लिया जायेगा कि नहीं जायेगा क्योंकि वह रिसिप्ट ही बिल्कुल कच्चा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी देख लें इसको, पूरे बिहार का मामला है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, इनके सुझाव को हमलोगों ने, सरकार ने, स्वीकार किया है, संवेदनाओं के साथ यह सरकार काम करती है और आप जो कह रहे हैं, कहीं की जानकारी भी दे दें, तो हम उसकी भी जांच करवा देंगे, वैसे सरकार का निदेश है कि 48 घंटे के अंदर उसका दाम दे दें, कहीं बाकी है तो किसान निश्चिन्त रहें, बिहार राज्य के किसान निश्चिन्त रहें, उनका एक पैसा कहीं नहीं जायेगा, उसका पूरा भुगतान करवा देंगे ।

टर्न-5/सत्येन्द्र/25-02-21

तारांकित प्रश्न संख्या- 326(श्री विजय शंकर दूबे)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक 1375 दिनांक 18-08-20 के द्वारा खरीफ 2020 में अतिवृष्टि के फलस्वरूप आयी बाढ़ से 33 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति हेतु सिवान जिला के 18 प्रखंडों के 263 पंचायतों

के प्रभावित किसानों का ऑनलाईन आवेदन दिनांकः 02-12-2020 से 23-12-2020 तक प्राप्त कर प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान का वितरण किया जा रहा है । उक्त प्रतिवेदन में महाराजगंज नगर पंचायत का 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति शून्य प्रतिवेदित किया गया है । महोदय डी0बी0डी0 पोर्टल पर महारजगंज नगर पंचायत को कृषि इनपुट अनुदान में शामिल नहीं किया गया है ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल से दीगर जवाब मंत्री जी ने कलक्टर के पत्र को पढ़ा, होमवर्क मंत्री जी ने ठीक से नहीं किया है । मैं महाराजगंज नगर पंचायत की बात कर रहा हूॅ । उक्त नगर पंचायत के 6 राजस्व ग्राम का पार्टिकुलर मेंशन किया है सवाल में, उस राजस्व ग्राम के किसानों का इनपुट लाभ नहीं दिया गया है, यह मैंने सवाल पूछा है । पंचायतों को दे दिया है आपने, यह मुझे मालूम है । महाराजगंज प्रखंड के और पंचायत शामिल हैं, लेकिन नगर पंचायत, महाराजगंज के 6 राजस्व ग्राम तो पंचायत में शामिल हो नहीं सकते तो वहां के किसानों का क्या कसूर है कि आप वहां किसानों का कृषि इनपुट का लाभ नहीं देंगे, ये मैं सरकार से जानना चाहता हूॅ । महोदय, एक बात और मैं सदन को और आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूॅ कि सरकार किस प्रकार, यही नहीं अन्य सवालों में भ्रामक जवाब दे रही है, राज्य के 22 नगर पंचायत की मेरे पास सूची है और यह सरकार की सूची है, इसे मैं विभाग से निकाला हूॅ । 22 नगर पंचायत जब शामिल हैं कृषि इनपुट की सूची में तो महाराजगंज नगर पंचायत को आपने शामिल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ और आगे शामिल करने में क्या आपत्ति है ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, इनपुट के लिए जो प्रतिवेदित पंचायतें हैं, गांव हैं उसमें 33 प्रतिशत क्षति या उससे अधिक ऐसे में जो प्रतिवेदित पंचायतें हैं, गांव हैं तो यह तो प्रतिवेदित ही नहीं है नगर पंचायत में और अगर प्रतिवेदित नहीं है तो कैसे उनका इनपुट में उनका नाम जायेगा और कैसे उनको इसका भुगतान होगा इसलिए ..

श्री मेवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठें । जिनका प्रश्न है उनको पूरक पूछने दें, आप कैसे उठ गये ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : इसलिए वह प्रतिवेदित ही नहीं था और इसी कारण से उसका भुगतान नहीं हुआ ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, फिर मैं कह रहा हूॅ, माननीय मंत्री जी रटा-रटाया जवाब दे रहे हैं, कलेक्टर का जवाब हो या कृषि पदाधिकारी का जवाब हो, ये भ्रामक जवाब है । उसको शामिल करने के लिए अनेक बार महोदय धरना हुआ किसानों का और प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी से लिखित अनुरोध किया कि ये नगर पंचायत के 6

राजस्व ग्राम को शामिल किया जाए दिनांक 16-12-2020 को पत्रांक-27 के द्वारा, कैसे प्रतिवेदित नहीं है, इसको कैसे आप इंकार कर सकते हैं ? इसलिए महोदय, सरकार यहां बैठी है केवल अधिकारियों के जवाब पढ़ने के लिए नहीं, सरकार को व्यापक दृष्टिकोण रखने होंगे और सरकार जनहित के मुद्दे को, एक तरफ आप कहते हैं कि विपक्ष के माननीय सदस्य सरकार के अंग हैं और विपक्ष के माननीय सदस्य सवाल पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं...

अध्यक्ष : आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं आसन से एक सवाल करना चाहता हूॅ । आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, इसलिए आप इस प्रश्न को स्थगित करिये और मेरे पास जो पेपर उपलब्ध है उसे मैं आसन के हवाले कर देता हूॅ, इसे आप देखें, सदन की कमिटी बनायें और जांच करायें । क्यों नगर पंचायत के इस 6 गांव को वंचित किया जा रहा है लगातार वर्षों-वर्षों से । वह नगर पंचायत है, मेरे पास सूची है कि 22 नगर पंचायत नवगछिया नगर पंचायत से लेकर अप टू नरकटियागंज नगर पंचायत तक के, 22 नगर पंचायत को सरकार ने इसमें शामिल कर लिया है तो फिर महाराजगंज नगर पंचायत को शामिल करने में क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शहरी क्षेत्र के किसान कृषि इनपुट अनुदान में शामिल है या नहीं और जब शामिल है तो इनके क्राईटेरिया में 33 प्रतिशत पूरा नहीं हुआ है जिसके कारण नहीं मिला है, यही है न ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : यही है ।

अध्यक्ष : अब आपका इस पर क्या पूरक है...?

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने जो प्रतिवेदित किया है उसके अनुसार खाता खेसरा जमीन टोटल 1880...

अध्यक्ष : इसको पहले ये दिखवा लेंगे जो आपके पास है, आप कागज दे दें ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो कह रहा हूॅ कि इसकी जांच कराने की जरूरत है...

अध्यक्ष : ठीक है, आप दिखवा लें, माननीय मंत्री जी ।

श्री मेवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अभी इनका खत्म नहीं हुआ है, आप वरीय लोग हैं, अब हो गया, इनका लास्ट है तीसरा पूरक हो गया ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करें आप । इस प्रश्न को स्थगित करने में और इसकी जांच कराने में क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष : वह जांच करवाकर के बतला देंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 327( श्री कुमार शैलेन्द्र)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । समाहर्ता, भागलुपर के प्रतिवेदन अनुसार भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर अंचल में दो राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं ।

(व्यवधान)

सम्प्रति बिहपुर सहित जिला के सभी अंचलों में राजस्व संबंधी कार्य ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है । मो0 बदेर आलम, राजस्व कर्मचारी द्वारा निजी व्यक्तियों से कार्य कराने का मामला प्रकाश में नहीं आया है । राजस्व कर्मचारी के 4353 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है । बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक स्तर पर परीक्षा की चयनित अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा दिनांक 25-12-2020 को सम्पन्न हो गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री का जवाब होने दीजिये तो फिर बात करते हैं ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : बिहार कर्मचारी चयन आयोग से सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा की सूची प्राप्त होते ही नियमित नियुक्ति की करवाई की जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपने आसन पर जाकर अपनी बात को रखें । आप अपने आसन पर जायें, आपको अवसर दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

अपने आसन पर जाकर अपनी बात को रखेंगे, तभी हम सुनेंगे । आपलोग अपने आसन पर जायें ।

(व्यवधान)

आप वरीय सदस्य हैं, आसन पर जाइए और आसन पर जाकर अपनी बात कहें । हमने कहा है कि वह जांच कर के बता देंगे । आप तो वरीय सदस्य हैं, आपसे लोग सीखते हैं।

(व्यवधान)

वह तो कह दिये कि 33 प्रतिशत आपके क्राइटेरिया में नहीं आया है इसलिए वह उसमें सम्मिलित नहीं है । उन्होंने बताया कि सभी शहरी क्षेत्र के किसान को भी इनपुट अनुदान

मिल रहा है लेकिन आपके क्राइटेरिया में नहीं आया है और आप कह रहे हैं कि क्राइटेरिया में है तो वही तो हम आपको कह रहे हैं । वह कागज उपलब्ध करा दें वे जांच करवा लेंगे।

(व्यवधान जारी)

टर्न-6/पुलकित-सुरज/ 25.02.2021

अध्यक्ष : जब आसन बोल रहा है तो उसके बाद आप लोग अब सुनिए ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, पूरे सबूत के साथ माननीय सदस्य ने सदन के सामने अपने प्रश्न को रखा है और आसन से अगर निदेश होता है कि इसकी जांच करा ली जाय तो माननीय मंत्री को खड़े हो कर कहना चाहिए कि मैं जांच कराऊंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । चलिए, अब स्थान ग्रहण करिये । स्थान ग्रहण करें, तब मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य आसन पर जाएं, हम जवाब दे रहे हैं । आप इतने पुराने सदस्य हैं और आप वेल में खड़े होते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइए, शांति से सुनें ।

(इस अवसर पर कांग्रेस के माननीय सदस्यगण वेल से अपने अपने स्थान पर चले गये)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शांत रहें, हम जवाब दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे जी सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं । वर्षों से उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है और उत्तर को भ्रामक, भ्रामक कई बार उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था । आप हमसे बड़े हैं, आपकी बात को भी मैंने सुना और ग्रहण कर लिया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शांति बनाए रखिये । वरीय लोगों की बात को सुनिए, यह सीखने का अवसर है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : सुनिए, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं इस बात को कि सरकार का काम सिर्फ उत्तर देना नहीं है, बल्कि प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य को संतुष्ट करना भी होता है और हम भी थे जब विपक्ष में तो ऐसा किया करते थे और पूछते थे कि हमें संतुष्ट करिये तो संतुष्ट होते थे । आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहिये हम किससे जांच करवा दें, सदन की समिति से करा दें । अध्यक्ष महोदय, आपको मंजूर है तो सदन की समिति से जांच करवा दी जाय ।

अध्यक्ष : आपको वह कागज उपलब्ध कराते हैं, अपने स्तर से जांच करके आप बता दें । बैठ जाइये।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी तैयार हैं सदन की कमेटी से जांच कराने के लिए तो सदन की कमेटी से जांच होनी चाहिए । इसमें हमको नहीं लगता कि आसन को कोई तकलीफ होनी चाहिए । मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है, महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इतने लोगों की आवाज को कैसे सुन पाएगा आसन ? बैठ जाइए पहले सब लोग ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य.....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, तो हमलोग यह मान कर चलें कि इस प्रश्न का जो उत्तर है उससे हमलोग संतुष्ट नहीं हैं, उसके लिए सदन की जो कमेटी है उससे जांच होगी और आप चाह रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है ।

अध्यक्ष : आपकी भावनाओं को...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, मंत्री जी जब तैयार हैं तो महोदय जांच होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष बैठ जाएं । आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं लेकिन जो व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था के अनुसार अभी माननीय सदस्य ने कहा कि उनको जिला कृषि पदाधिकारी पे रिपोर्ट दी है और इनको रिपोर्ट कलेक्टर से आयी है तो इसे वरीय लोग जांच लें, संतुष्टि नहीं होती है और अगर असत्य पाया जाएगा, तब सदन की कमेटी उसको देख लेगी ।

चलिए, श्री कुमार शैलेन्द्र ।

श्री कुमार शैलेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है और यह मेरे बिहपुर विधान सभा का मामला है, वहां महोदय छः हलका है लेकिन कर्मचारी केवल दो ही है और दो कर्मचारी अपने निजी सहायक के रूप में दस लोगों को रखते हैं । माननीय मंत्री जी, ने कहा कि उन कर्मचारी का प्रमाण नहीं है तो मैं प्रमाण हूँ और वे कर्मचारी जो हैं अपने निजी घर अन्नपूर्णा भवन में अंचल कार्यालय होते हुए भी वह प्रखंड कार्यालय के पीछे में अंचल का कार्य चला रहे हैं । महोदय, वे अवैध वसूली करते हैं । महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी, न्याय के साथ विकास करना चाहते हैं लेकिन ऐसे ही कुछ कर्मचारी के चलते सरकार बदनाम होती है । मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप तुरंत वहां पर छः हलका में, छः कर्मचारी देकर आप वहां पर जो अवैध वसूली हो रही है, उसको रोकना चाहते हैं ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री, सभी माननीय सदस्य गंभीरता से सुनें, क्योंकि सभी की भावनाओं से जुड़ा हुआ यह पूरे बिहार का मामला है ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि हमारे....

अध्यक्षः आपका जवाब माननीय मंत्री जी, उस समय नहीं सुन सके इसलिए एक बार फिर पढ़ दीजिये।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः आंशिक स्वीकारात्मक है ।

समाहर्ता, भागलपुर के प्रतिवेदन अनुसार भागलपुर जिला के अंतर्गत बिहपुर अंचल में कुल दो राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं । सम्प्रति बिहपुर अंचल सहित जिला के सभी अंचलों में राजस्व संबंधी कार्य प्रायः ऑनलाईन माध्यम से किये जा रहे हैं । मो0 बदेर आलम राजस्व कर्मचारी द्वारा निजी व्यक्तियों से कार्य कराने का मामला प्रकाश में नहीं आया है । राजस्व कर्मचारी 4353 पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है । बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक स्तर पर परीक्षा में चयनित अभ्यार्थियों की मुख्य परीक्षा 25.12.2020 को संपन्न की गयी है । बिहार कर्मचारी चयन आयोग से सफल अभ्यार्थियों की अनुशंसा सूची प्राप्त होते ही नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया की जायेगी ।

श्री कुमार शैलेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, वहां अन्नपूर्णा भवन में अंचल चल रहा है, महोदय । क्या माननीय मंत्री अंचल रहते हुए जो अन्नपूर्णा भवन से वह अंचल कार्यालय में भवन को चलाना चाहते हैं ? महोदय जो अवैध वसूली करता है वह अन्नपूर्णा भवन में होती है, लोग वहां बुलाये जाते हैं इसलिए हम माननीय मंत्री महोदय से चाहते हैं कि आप जो है वो अन्नपूर्णा भवन से अंचल कार्यालय आये महोदय ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री । शांति से सुनेंगे तभी ना । शांति से सुनें ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है । ये पूरे बिहार के अंतर्गत मौखिक रूप में मुझे जानकारी मिली है और प्रमंडलीय बैठक में जब मैं गया हूँ । जहां-जहां गड़बड़ियां पायी गई हैं, वहां मैंने निलंबित भी किया है । मैंने अपने मुजफ्फरपुर कमिश्नरी में हमारे औराई के ही राजस्व कर्मचारी रवि भूषण सहाय को मैंने निलंबित किया है । इमामगंज के सी0ओ0 पर कार्रवाई की गयी है और छपरा प्रमंडलीय बैठक में मैंने उस गांव के डाटा ऑपरेटर को भी निलंबित किया है और मैं अपने माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं आप भी लिखित मुझे दें और आप कोई एविडेन्स दें, मैं उचित कार्रवाई करके न्याय दूंगा, आपको ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, पूरक पूछें, सिर्फ सारगर्भित पूछें, समय बर्बाद कम हो, लास्ट है ।

श्री राजू कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूँ कि जब तक कर्मचारी की बहाली नहीं होती है । यह सर्वविदित है कि कर्मचारी के दलालों द्वारा वसूली होती है, तब तक एक रोस्टर तैयार करके प्रखंड में कम से कम सी0ओ0 एक रोस्टर तैयार कर दें और एक प्रखंड में तीन-चार ही कर्मचारी हैं तो कम से कम किस दिन किस पंचायत में उपलब्ध रहेंगे उस दिन का रोस्टर तैयार करवा देना चाहते हैं, पूरे बिहार में ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रक्रिया को लागू किया है और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जून तक नए कर्मचारी वहां चले जायेंगे और रोस्टर के अनुसार पंचायत में बैठने की तैयारी भी चल रही है ।

श्री राजू कुमार सिंह: महोदय, नहीं-नहीं उससे पहले ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: मैंने तैयार कर दिया है पूरे बिहार के अंदर और प्रमंडलीय बैठकों में मैंने क्लीयर कर दिया है कि रोस्टर के अनुसार पंचायत में लोग बैठेंगे और जून तक नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी । पूरक पूछना है ?

श्री अवध विहारी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूँ । पूरे बिहार में जो राजस्व में पदस्थापित कर्मचारी हैं या उसके सर्किल इंस्पेक्टर हैं, वह प्रखंड अंचल में नहीं बैठ करके, न आपने पंचायत सरकार भवन भी बनाया है इसलिए बनाये हैं कि उसी में बैठकर के विकास के और राजस्व के काम होंगे, नियरेस्ट प्वाइंट पर जो लाभुक हैं उसका लाभ उठायेंगे ।

(क्रमशः)

टर्न-7/मधुप/25.02.2021

..क्रमशः...

श्री अवध बिहारी चौधरी : लेकिन ये सभी कर्मचारी और सर्किल इंस्पेक्टर अंचल में न जाकर निजी जगहों पर बैठते हैं और इतना ही नहीं, वे दलाल रखे हैं, वे दलाल से काम कराते हैं, भारी धांधली है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात की भी आप जॉच करायेंगे कि वे नाजायज तरीके से म्यूटेशन में, अन्य कार्यों में, जमाबंदी सुधार में नाजायज पैसे बिचौलिया को रखकर वसूलने का काम करते हैं ? यह पूरे सदन का मामला है और सभी क्षेत्रों का मामला है ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जायं । माननीय मंत्री ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है और इन्होंने जो कहा है, मेरे संज्ञान में जहॉ-जहॉ का मामला आया है, मैंने कार्रवाई भी की है और माननीय सदस्यों से

आग्रह भी करता हूँ, सहयोग भी चाहता हूँ कि ऐसी कोई जानकारी हो तो आप लिखित मुझे दें और उसके अलावे जहाँ-जहाँ हमारी सरकारी जमीन है या भवन हैं, वहाँ लोग बैठते हैं, जहाँ पंचायत सरकार भवन की बात आपने कही है, भवन निर्माण विभाग के द्वारा या पंचायती राज विभाग के द्वारा हमें भवन चार्ज में जब आ जायेगा तो हमारे नियमित कर्मचारी जब नये लोग जायेंगे तो उसमें बैठकर काम करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, पूरे बिहार का मामला है । आप सिस्टम डेवलप करके इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए जो व्यवस्था बनायें, सदन को भी अवगत करा देंगे ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : सारे सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, हो जायेगा ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी माननीय कृषि मंत्री जी जवाब देने में कुछ गलती कर देते थे, बगल में प्रमोद कुमार जी हैं, वह अपने आप को मतिहारी का कहते हैं, हैं मोतिहारी के लेकिन मतिहारी कहते हैं, वही गड़बड़ करवाते रहते थे....

अध्यक्ष : बैठ जाइये । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

एक आवश्यक सूचना । बैठ जाइये सबलोग ।

माननीय सदस्यगण, कल दिनांक- 24 फरवरी, 2021 को सभा सचिवालय के कर्मी द्वारा मोन्ट ब्लैक कम्पनी निर्मित एक कलम अध्यक्षीय कार्यालय को प्राप्त हुई, जो कार्यालय में रक्षित है । जिन माननीय सदस्य की वह कलम हो, वे अध्यक्षीय कार्यालय में आकर प्राप्त कर लेंगे ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

(व्यवधान)

बहुत माननीय सदस्यों का बहुत-सा शून्यकाल है, होने दें । बैठ जायं ।

श्री विद्या सागर केशरी ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् के प्रतिष्ठित दवा व्यवसायी स्व0 पवन केडिया की निर्मम हत्या 28 दिसम्बर, 2020 को शाम के 07.30 बजे दूकान से घर आने के क्रम में कर दी गयी जिसका फारबिसगंज थाना में कांड संख्या 1035/20 दर्ज है । लगभग दो माह बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई । अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी की माँग सदन से करता हूँ ।

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2008 से ही अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं अवर न्यायाधीश के रिक्त पदों पर अतिशीघ्र न्यायाधीशों की पदस्थापना करावें ।

अध्यक्ष : ज्यादा से ज्यादा सदस्य शून्यकाल पढ़ सकें इसलिए थोड़ा समय बचाने का प्रयास करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल सूता मिल लिक्विडेशन में चला गया है । इसकी 35 एकड़ जमीन है । लीज के लिये जमीन का मूल्य अत्यधिक रखा गया है जिसके कारण कोई व्यक्ति लीज लेने हेतु नहीं आ रहा है ।

अतः जमीन का मूल्य आसपास की जमीन के आधार पर रखा जाय ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, जिले की विभिन्न समस्याओं पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की मासिक बैठक होती है परन्तु जनप्रतिनिधियों के सम्मिलित नहीं किये जाने से वास्तविक समस्याएं सामने नहीं आती हैं ।

अतः जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की होनेवाली मासिक बैठक में जनप्रतिनिधियों, संबंधित डी0एस0पी0, अनुमंडलाधिकारी को सम्मिलित करने की माँग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनायें रखें । सदन के अंदर आपस में बातचीत न करें । माननीय सदस्य की सूचना को सुनें ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया के चालीस किलोमीटर क्षेत्र में फैले पाँच सौ साल से ज्यादा पुरानी पवित्र पचास फीट चौड़ी नदी का भू-माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है।

अतः मैं सरकार से प्राचीन नदी का संरक्षण संवर्धन करने तथा अतिक्रमण में संलिप्त भू-माफियाओं पर कार्रवाई करने की माँग करता हूँ ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, राजकीय धनवन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को बिना किसी के कारण स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना सं0-839 दिनांक-29.08.03 द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है ।

अत: विभाग अपने स्तर से जॉच कर उक्त कर्मियों को पुन: बहाल कराने की मॉग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार मंडल : महोदय, रोहतास जिला के दिनारा प्रखण्ड अन्तर्गत विसी कला पंचायत के ग्राम- कोईरीयॉ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जिसका भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से मरीजों का प्राथमिक इलाज नहीं होता है, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाकर डॉक्टर एवं नर्स की प्रतिनियुक्ति करावें ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत डाल्टेनगंज-पटना पथ, रामाबांध से बाईपास होते हुए वाहनों के परिचालन से शहर में यातायात बाधित होने की समस्या बनी रहती है। यातायात अत्यधिक होने के कारण ग्राम-चतरा से NH-02 भाया हजारी कर्मा पथ निर्माण होने से झारखण्ड की ओर से आने वाली वाहनों को सुविधा होगी एवं जाम की समस्या से निजात मिलेगी ।

अत: जनहित में यातायात की समस्या को देखते हुए उक्त पथ का निर्माण जल्द कराया जाए ।

श्री चेतन आनंद : महोदय, मैं 'छोटा जिला, त्वरित विकास' के तर्ज पर स्थानीय जनता की चिर-प्रतीक्षित मॉग, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकड़ी दयाल और ढाका अनुमंडल को मिलाकर 'ढाका' को जिला बनाने के लिए राज्य सरकार से पुरजोर मॉग करता हूँ ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, सीतामढ़ी जिला अपराधियों का शरण स्थली बन गया है । 24.02.2021 को मेजरगंज प्रखण्ड के कुँवारी मदन गॉव में शराब माफिया के घर छापेमारी में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद एवं चौकीदार घायल हो गया है । शहीद के परिवार को 50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी दिया जाय, दोषी पर त्वरित कार्रवाई हो ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के लखौरा निवासी दारोगा दिनेश राम की सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज में शराब कारोबारियों ने गोली मारकर हत्या कल कर दी ।

हम सरकार से मॉग करते हैं कि इस हृदय-विदारक एवं जघन्य अपराध में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी, 50 लाख मुआवजा एवं एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अगले माननीय सदस्य को भी बोलने का मौका दें ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगॉव नगर पंचायत क्षेत्र में प्रस्तावित सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु अबतक भूमि उपलब्ध नहीं करवाया गया है ।

अत: सरकार से उक्त प्रस्तावित सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करवाने की मॉग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, पुनपुन नदी (हमीदनगर बराज) से जहानाबाद नहर निर्माण और फल्गु नदी में मंडई बियर एवं नहर निर्माण का पूरा न होना, अकाल की मार झेलते जहानाबाद के किसानों के साथ अन्याय है । सरकार से इन दोनों योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने की अपील करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के सहार प्रखंड के कोसियर गॉव की पुलिया वर्षो से ध्वस्त है, जिससे एकवारी होकर सहार जाने में अगल-बगल के 10 गॉवों के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ।

अत: लोकहित में ध्वस्त पुलिया का सरकार तत्काल निर्माण करावे ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के लखौरा निवासी दारोगा दिनेश राम का सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज में शराब माफियाओं ने गोली मारकर हत्या कर दी ।

हम सरकार से मॉग करते हैं कि शहीद दारोगा के परिवार को 50 लाख रू0 मुआवजा एवं परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी एवं अपराधी पर स्पीडी ट्रायल कर यथाशीघ्र सजा दिलावें ।

टर्न-8/अभिनीत/अंजली/25.02.2021

श्री अरूण सिंह: काराकाट विधान सभा अन्तर्गत बिक्रमगंज प्रखंड का बी0आर0सी0 भवन जिसका निर्माण कार्य कन्या मध्य विद्यालय बिक्रमगंज में कराया जा रहा था, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ । इस बी0आर0सी0 से जुड़े कार्य अन्यत्र भवन में चल रहे हैं ।

अत: मैं मांग करता हूं कि बी0आर0सी0 भवन का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाय ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड में कन्या विवाह योजना के 1985 आवेदन स्वीकृति के पश्चात् भुगतान हेतु लंबित हैं । 2013 के बाद आवंटन के अभाव में राशि लंबित होने से लाभुकों में आक्रोश व्याप्त है । शीघ्र आवंटन एवं भुगतान कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्रः भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड में बमकाली मंदिर से बिहपुर थाना के बीच में सड़क पर जलजमाव से लोगों का जन-जीवन नारकीय हो गया है । सड़क पर सालों भर पानी जमा रहता है और यह सड़क प्रखंड मुख्यालय का मुख्य सड़क है ।

अतः इसे शीघ्र ठीक कराने हेतु सरकार से अविलंब जल निकासी करवाने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमारः समस्तीपुर जिलान्तर्गत विथान प्रखंड के उजान गांव की छात्राएं एवं अभिभावकों के परीक्षा से लौटने के दरम्यान सागी मोड़ पर दुघर्टना में दो छात्राएं, दो अभिभावकों की मौत हुई है तथा 6 घायल हैं ।

मैं सरकार से पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवानः पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड के गायघाट उच्च विद्यालय खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण जनहित में महत्वपूर्ण है । प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए आठ किलोमीटर के अन्दर दूसरा कोई स्टेडियम नहीं है जिससे खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा को विकसित कर सकें । मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्टेडियम का निर्माण करावें जिससे खेल को बढ़ावा मिले ।

श्री जय प्रकाश यादवः अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के चकरदहामील चौक से रेवाहीपथराहा तक वर्षों पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग से निर्मित सड़क बेहद खराब स्थिति में है ।

अतः सड़क के संकरा होने के चलते आवागमन में आमजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है । वर्णित सड़क की मरम्मत्ति एवं चौड़ीकरण की मांग सदन से करता हूं ।

श्री संजय सरावगीः दरंभगा शहर के मध्य मुख्य सड़क एल0एन0 मिश्रा पथ के किनारे कई स्थानों पर पशुओं का वध कर खुलेआम मांस की बिक्री की जाती है, जिससे विशेष समुदाय के लोगों की भावना आहत होती है, साथ ही स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अविलंब रोक लगाकर कार्रवाई की जाय ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ताः सारण जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के पंचायत करीगा के ग्राम- बीनटोलिया के रितुजीत कुमार, पिता कृष्ण कुमार चौधरी की हत्या गोली मारकर दिनांक- 03.01.2021 को कर दी गई है, जिसका मुफसिल थाना कांड संख्या-6/21 है । उक्त कांड संख्या के अभियुक्तों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है ।

श्री सुधाकर सिंहः कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंडान्तर्गत जमुरना ग्राम में दुर्गावती नदी पर पुल नहीं होने से आम जनता को नदी पार करने में काफी कठिनाई होती है, जमुरना ग्राम के पास दुर्गावती नदी पर 4X21.75 लम्बा पुल का निर्माण करावें ।

श्रीमति प्रतिमा कुमारी: वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर प्रखंड, पंचायत- रामपुर रत्नाकर, मीरपुर पतार, ग्राम-सरसई और रानी पोखर के महादलित समाज के 35-40 परिवारों को आज तक बासगीत पर्चा निर्गत नहीं किया गया है । सभी भूमिहीन महादलित परिवारों को भूमि आवंटित करने तथा पुनर्वास की व्यवस्था की जाय ।

श्री अजय कुमार सिंह: जमालपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत धरहरा प्रखंड के बंगलवा पंचायत में दलित टोला गोपालीचक तथा ग्राम-सतधरवा को जाने वाली सड़क के निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शून्यकाल में तात्कालिक लोकहित के प्रश्नों को प्राथमिकता दें ताकि जरूरत पड़ने पर गंभीरता से माननीय मंत्री भी ले सकें । इसलिए वरीय लोग, नये लोग सब लोकहित के तात्कालिक समस्याओं को ही उठावें ।

अब शून्यकाल समाप्त हुआ । अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जायेंगे ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, एक सूचना है शून्यकाल का जरा सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष: मेरे कार्यालय कक्ष में आकर संबंधित विषय पर बात कर लेंगे ।

(व्यवधान)

अब सब क्यों उठ गये बैठिए, महबूब आलम जी उठे हुए ही हैं पहले से ।

श्री महबूब आलम: कल एक ध्यानाकर्षण प्रश्न के जवाब में मंत्री द्वारा मेरे तथा मेरी पार्टी के खिलाफ...

अध्यक्ष: चलिए, माननीय सदस्य श्री शम्भू नाथ यादव अपनी सूचना को पढ़ें । यह विषय अब समाप्त हो गया । माननीय सदस्य श्री शम्भू नाथ यादव अपनी सूचना को पढ़ें ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र: माननीय सदस्य जब कुछ कह रहे हैं तो इन्हें आपके संरक्षण की आवश्यकता है ।

(इस अवसर पर भा0क0पा0 (माले) के सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बार-बार, वो बोल रहे हैं और मैंने सुन लिया, हमने नियमन दे दिया, हमारे कक्ष में आकर मिल लीजिएगा, महबूब जी । आपकी सूचना अमान्य कर दी गयी है, मेरे कक्ष में आकर मिल लीजिएगा ।

अब ध्यानाकर्षण सूचना माननीय सदस्य शम्भू नाथ यादव जी का है, आप अपनी सूचना पढ़ें । आपका नाम तीन बार पुकार चुके हैं, हम आगे बढ़ेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री शम्भू नाथ यादव, राम विशुन सिंह एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री शम्भू नाथ यादवः अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के ब्रहमपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाला जनेश्वर मिश्रा पुल का निर्माण हुआ है । बक्सर-पटना फोरलेन से जनेश्वर मिश्रा...

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य सूचना पढ़ रहे हैं और आपलोग वेल में खड़े होकर बोल रहे हैं, यह क्या है? बैठ जाइये, माननीय सदस्य सूचना पढ़ रहे हैं इनका सम्मान कीजिए । पढ़िये ।

श्री शम्भू नाथ यादवः पुल तक रोड बनाने के लिए जिस जमीन का सर्वेक्षण कराया गया है, उसमें रैयती जमीन को भू-अर्जन करने में 100 प्रतिशत खर्च करना होगा...

(व्यवधान)

अध्यक्षः महबूब जी, हमारे कार्यालय में आकर मिल लेंगे । हम सुनेंगे आपकी बात बैठिए, हम तो आपलोगों के ही हित में सोचते हैं ।

श्री शम्भू नाथ यादवः जबकि ब्रह्मपुर चौरास्ता से आगे फोरलेन से कटकर निमेज बलुआ घाट भाया शिवपुर दियर जुनेवी होते हुए पुल तक रोड बनाने में भू-अर्जन 40 प्रतिशत होगा या फिर फोरलेन के गरहथा मोड़ से गायघाट भाया गोकुल जलाशय के किनारे से पुल तक रोड बनाने में 30 प्रतिशत भू-अर्जन करना होगा ।

अतएव, बक्सर-पटना फोरलेन से जनेश्वर मिश्रा पुल तक सड़क बनाने के लिए उक्त दो विकल्पों पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

टर्न-9/आजाद/25.02.2021

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश .....

( व्यवधान )

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट । पहले आपलोग अपने आसन पर जायं, माननीय नेता, प्रतिपक्ष बोलेंगे । देखिए एक सिस्टम से व्यवस्था को चलाइए, नेता प्रतिपक्ष या सदन नेता बोलें तो थोड़ा सम्मान के साथ आपलोग अपना स्थान ग्रहण कर लें । एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, उनकी बात सुनें वे क्या बोल रहे हैं । आप अपने स्थान पर जायं ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भा0क0प0(माले) के माननीय सदस्यगण वेल से अपनी-अपनी सीट पर चले गये)

एक आग्रह करेंगे सभी माननीय सदस्यों से कि नेता प्रतिपक्ष या सदन नेता बोलें तो शांति से आपलोग उनकी बात सुनें कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण ....

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपलोग बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण समय-समय पर मिलता रहता है लेकिन एक अति-महत्वपूर्ण विषय है और यह कोई पक्ष, विपक्ष और सत्ता पक्ष का सवाल नहीं है, यह हम सब जनप्रतिनिधियों का सवाल है । इस लोकतंत्र के मंदिर में जब जनता अपने सवाल को रखती है तो हमलोगों को भी महोदय, सम्मान मिलना चाहिए । महोदय, अभी कल जो घटना हुई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाय वह कम है और आपके भी संज्ञान में यह मसला आया है । हमलोग तो चाहेंगे उस अधिकारी पर और हमें जो सूचना मिली है महोदय, वह जो अधिकारी हैं, जिन्होंने इनको धक्का दिया, वह एक-दो बार नहीं, इससे पहले भी मेरे आवास पर आ कर, जो लोग मिलने आते थे...

अध्यक्ष: घटना क्या है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जो धक्का-मुक्की की गई है...

अध्यक्ष: एक मिनट, घटना क्या है ?

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, जब परिसर में मीडिया को बाइट देने के समय में....

अध्यक्ष : कहां पर दे रहे थे बाइट ?

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, परिसर में ।

अध्यक्ष : प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर, पोर्टिको के अंदर या पोर्टिको के बाहर ?

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, पोर्टिको के बाहर । महोदय, एक सुरक्षाकर्मी ने मीडिया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, धक्का-मुक्की की, बस इतना ही तो सूचना है । महोदय, मैं सुरक्षाकर्मी पर एक्शन लेने के लिए मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : इसको हम संज्ञान में लेकर देख लेते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण मिला, उसके लिए धन्यवाद महोदय, लेकिन जो अधिकारी ने धक्का-मुक्की की, उसने पहले भी हमारे आवास पर आकर, सूचना दे रहा हूँ महोदय । महोदय, हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, अगर जनता जनप्रतिनिधि से मिलने आयेगी तो जनता को भगाया जायेगा । यह उस पदाधिकारी का

आदतन व्यवहार है । हमारे आवास पर भी आ कर के, बाहर जो पेट्रोलिंग होती है पुलिस की, जो जनता हमसे मिलने आते हैं उनको भगाने का काम किया...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : यह तो अति महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आपको भी हम अपने कार्यालय में बुलाते हैं और उस फूटेज को देख लेते हैं कि क्या मामला है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, इन अधिकारियों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि कोई जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं ।

अध्यक्ष : जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने का मैंने निर्देश दे दिया है । आपको जानकारी हो कि माननीय सदस्य लाखों लोगों के विश्वास को जीत कर आते हैं, इनके आचरण और व्यवहार से बिहार का और क्षेत्र का परिचय होता है । सदन की गरिमा बढ़ती है और लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता बरकरार होती है । हम सबको जो दिशा-निर्देश और जो नियम बनाया गया है, तय किया गया है, उसका पालन हम सब करेंगे । उसके बाद उस नियम के विरुद्ध कोई बाधक बनेंगे तो उस पर विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई करेंगे ।

श्री जनक सिंह : अभी जो बात हुई है, जनप्रतिनिधियों का अनादर नहीं हो रहा है लेकिन हमारा भी धर्म है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक जगह वर्णित किया गया है कि राजा और अमात्य दोनों मिलकर राज चलाते हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि का भी धर्म होता है कि हम अपने अमात्य यानी जो भी हमारे सरकारी पदाधिकारी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए, इसलिए दोनों का सम्मान होना चाहिए ।

अध्यक्ष : वह हो गया, सभी सहमत हैं ।

(व्यवधान)

हो गया । अब बैठ जाइए । सबके लिए बोले हैं, एक के लिए नहीं बोले हैं। माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को जोड़ने वाला जनेश्वर मिश्रा पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइए, आप क्यों खड़े हैं, माननीय मंत्री बोल रहे हैं । माननीय सदस्य, बैठिए । आपलोग सदन के अन्दर नियम का पालन नहीं करेंगे तो कैसे अपेक्षा रखते हैं कि

बाहर में लोग नियम का पालन करेंगे । आप भी बैठ जाइए माननीय सदस्य । अब बोलिए माननीय मंत्री जी ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, उक्त पुल के बिहार राज्य की सीमा में पहुँच पथ निर्माण के लिए पथ प्रमंडल, बक्सर एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अभियंताओं ने संयुक्त भ्रमण करके प्रारंभिक प्रतिवेदन समर्पित किया है । इस प्रतिवेदन की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई और उसके उपरान्त पथ के महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इसमें बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा सभी विकल्पों का गहराई से अध्ययन करके विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाए । तद्नुसार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा डी0पी0आर0 बनाने की कार्रवाई की जा रही है । डी0पी0आर0 बनाने के क्रम में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव पर सकारात्मक विचार किया जाएगा ।

श्री शम्भू नाथ यादव : महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सरकार का धन बचाने का विषय है । सरकार ने जिस रूट को तय किया है.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देखकर बोलिए ।

श्री शम्भू नाथ यादव : महोदय, पुल निर्माण निगम ने जिस रूट को तय किया है, पूरे जनेश्वर मिश्रा पुल से लेकर के फोर लेन तक 14 कि0मी0 भू-अर्जन करना है .....

अध्यक्ष : दो स्टेट को जोड़ने का भी है ।

श्री शम्भू नाथ यादव : जी महोदय । महोदय, पहले तो मैं बता दूं, बहुत दर्द होता है । अधिकारी लोग जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से कोई सुझाव नहीं लेते हैं । हमलोग रात-दिन वहां मेहनत करते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं .....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए न ।

श्री शम्भू नाथ यादव : पूरक मेरा यह है महोदय कि 14 कि0मी0 भू-अर्जन करने में 70-80 करोड़ रू0 खर्च है और मैं जो बता रहा हूँ, जिस रोड से गोकुल जलाशय होते हुए उस रूट में 14 कि0मी0 में मात्र 30 से 35 करोड़ रू0 ही भू-अर्जन करने में खर्च है महोदय । यह सरकार का धन बचत की बात है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । आप प्रश्न किये हैं तो उनकी बात सुनिए ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की संवेदना का हमलोग सम्मान करते हैं लेकिन जिस बसावट की या जिस रूट या एलाईनमेंट की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, वह सघन बस्ती से होकर जाने वाला है । हमलोग एन0एच0 84 से इसको ले रहे हैं जनेश्वर मिश्रा पुल तक, उसमें फोरलेन से लेने की योजना है । यानी फोरलेन से आराम से भविष्य में भी इसको विस्तार कर सकते हैं और जिस बसावट की वो चिन्ता कर रहे हैं, वह सघन बस्तियों

से होकर गुजरने वाला है और उसमें हम कभी भी विस्तार नहीं कर पायेंगे । लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने जो विषय दिया है, उसको हमलोगों ने विभाग में कल ही पूरा इनका डिजाइन देखा है, प्रजेंटेशन देखा है । माननीय सदस्य इसमें जो भी लोग हैं, उन सभी के साथ हमलोग विभाग में बैठ करके फिर से इसकी समीक्षा कर लेंगे ।

श्री शम्भू नाथ यादव : अध्यक्ष महोदय, ....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है । सीधे पूरक पूछिए ।

श्री शम्भू नाथ यादव : पूरक मेरा यह है महोदय कि जिस बात पर अधिकारी लोग इनको गुमराह कर रहे हैं, उस बात पर मेरा चैलेंज है, मैं जो रूट बता रहा हूँ, उसका भविष्य 100 साल है । कहीं गांव से यह छू नहीं रहा है ....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसको दिखवा लें, जनहित का मामला है, इसको दिखवा लें ।

श्री शम्भू नाथ यादव : महोदय, अधिकारी लोग जो रूट दिये हैं .....

अध्यक्ष : दिखवा लेते हैं, आप एक अलग से डिटेल्स लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजिए ।

श्री शम्भू नाथ यादव : इसकी जॉच करवायी जाय महोदय ।

अध्यक्ष : दिखवा लीजिए और जॉच करवा लीजिए ।

श्री शम्भू नाथ यादव : महोदय, मैं इस बात के लिए चैलेंज देता हूँ, महोदय, मैं इसके लिए विधायकी से भी रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ ।

अध्यक्ष : क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जॉच करवा लेंगे । ऐसा नहीं करें ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : माननीय सदस्य को इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं थी महोदय ।

अध्यक्ष : ऐसा नहीं करें, इसको दिखवा लेंगे । नेता प्रतिपक्ष भी पथ निर्माण मंत्री रहे हैं । आपको समझायेंगे और जॉच करवायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय मंत्री जी इसका एक बार एलाइनमेंट देख लें, डी0पी0आर0 बन रहा होगा । कोशिश यह की जाय कि भविष्य में कनजेक्शन ट्राफिक को देखते हुए जो बेहतर विकल्प है, उसपर आप निर्णय लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल जी, आप अपनी सूचना को पढ़ें ।

टर्न-10/यानपति-धिरेन्द्र/25.02.2021

सर्वश्री पवन कुमार जायसवाल, लाल बाबू प्रसाद एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, ''पंचायती राज विभाग के पत्रांक-14, दिनांक-16.06.2020 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए टायड-अनटायड मद में 5018 करोड़ रुपये त्रिस्तरीय पंचायतों क्रमशः ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् को 70:20:10 के अनुपात में स्वीकृतोपरान्त 09 माह पूर्व भेज दिया गया है । नई व्यवस्था में मुखिया-पंचायत सचिव, प्रमुख-बी0डी0ओ0, अध्यक्ष जिला परिषद्-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का डोंगल बनाने एवं पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से मजदूरों, दूकानदारों आदि के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित किये जाने तथा सभी योजनाओं का प्राक्कलन, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति साइट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है, जिस कारण पूर्वी चम्पारण सहित राज्य के सभी जिलों में पन्द्रहवें वित्त की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्च नहीं हो पा रही है जबकि राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है ।

अतएव, 31 मार्च, 2021 तक पंचायती राज संस्थाओं को पुरानी प्रक्रिया के तहत 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च किये जाने का आदेश निर्गत करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पंचायती राज ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, समय चाहिये ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम सदन के माध्यम से आग्रह करेंगे कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना किसी भी समय जारी हो सकती है तो माननीय मंत्री जी कल के डेट में इसको रख दें, सरकार का जवाब आ जाय, माननीय मंत्री जी से मेरी यह व्यक्तिगत मांग है ।

अध्यक्ष: अगली तिथि में ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री, निर्वाचन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006, बिहार निर्वाचन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2012, बिहार निर्वाचन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(ए)(2) के तहत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के वार्षिक प्रदिवेदनों की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए)(2) के तहत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग); कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत बिहार राज्य पथ विकास निगम के वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल के बाद)

टर्न-11/शंभु/25.02.21/

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे । माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श के लिए दिनांक 24 एवं 25 फरवरी को तिथि निर्धारित थी । कल 24 फरवरी, 2021 को अंतराल के बाद सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी । इसलिए आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर होगा । वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए कुल 2 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :

| | | |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | - | 37 मिनट |
| भारतीय जनता पार्टी | - | 37 मिनट |
| जनता दल युनाइटेड | - | 22 मिनट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | - | 09 मिनट |
| सी0पी0आइ0एम0एल0 | - | 06 मिनट |
| ऑल इंडिया मजलिसे-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | - | 02 मिनट |
| हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा | - | 02 मिनट |
| विकासशील इंसान पार्टी | - | 02 मिनट |
| सी0पी0आइ0एम0 | - | 01 मिनट |
| सी0पी0आइ0 | - | 01 मिनट |
| लोक जनशक्ति पार्टी | - | 01 मिनट |

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल, अपना पक्ष रखें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं प्रस्ताव करूँगा कि आपने समय सीमा सभी दलों का बताने का काम किया, लेकिन यह बजट सत्र है और बजट पर जब वाद-विवाद हो रहा है तो पार्टी का जो स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से सबको समय मिलना चाहिए । महोदय, आपने भारतीय जनता पार्टी और आर0जे0डी0 का 37-37 मिनट दिया । हमलोगों ने जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद किया तो राष्ट्रीय जनता दल को 74 मिनट मिला था तो हमलोग अपनी बात महत्वपूर्ण सत्र है, महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद हो रहा है तो 74 मिनट से कम हमलोग नहीं बोलेंगे और जितनी जो पार्टी बोली

थी उनको उतना ही समय मिलना चाहिए । उस समय भी सरकार के उत्तर में जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, महामहिम के अभिभाषण को लेकर तो समय अवधि का विस्तार किया गया था । भले ही आप चाहें तो समय अवधि हमलोग जो हैं 6 बजे तक, 7 बजे तक बैठेंगे, समय अवधि विस्तार किया जाय, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरणी का सामान्य विमर्श के लिए दिनांक 1 एवं 2 मार्च के लिए तिथि निर्धारित थी । 1 मार्च के अंतराल के बाद सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी । 2 मार्च, 2017 को वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्य विमर्श और सरकार के उत्तर में भी उस समय राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल युनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम समय दिया गया था 40 मिनट का, 35 मिनट का, 26 मिनट का, इंडियन नेशनल कांग्रेस 13 मिनट का और इस तरह की परंपरा पहले भी रही है।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, बहुत बार ऐसा हुआ है कि समय अवधि बढ़ायी गयी है । परंपरा तो रही है तभी तो मुख्यमंत्री जी को भी समयावधि बढ़ाया गया ।

अध्यक्ष : आप शुरू तो कीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम चाहेंगे महोदय, सरकार के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी या किसी भी दल के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

अध्यक्ष : श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल अपना पक्ष रखें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि जो समयावधि है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

अध्यक्ष : गागर में सागर भर दें नेता प्रतिपक्ष ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मुख्यमंत्री जी तो कहते रहते हैं कि जो समक्ष है उसको सामने लाइये, सामने बात रखिये । हमलोग तो चाहेंगे कि समय पर आप पहले तय कर दीजिये उसके बाद ही बहस कराया जाय और समय अवधि के विस्तार का प्रस्ताव लाया जाय, शुरू करने के बाद तो यही चलता रहेगा । यहां तो कहीं न कहीं से काम करने का है, यानी सत्तापक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपनी बात सरकार के समक्ष रख सकें । महोदय, इसमें सब लोगों की राय है कि समय का विस्तार हो, इसे बढ़ाना चाहिए । हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं है । मुख्यमंत्री को या सरकार को जो उत्तर देना है, भाषण देना है हमलोग इंतजार करेंगे, हमलोग बैठेंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अभी तो आपने आय-व्ययक पर विमर्श तत्काल प्रारंभ कराने के लिए और माननीय नेता प्रतिपक्ष को आपने पुकारा है । यह परंपरा भी रही है कि जो निर्धारित समय होता है उसपर माननीय सदस्यगण बोलते हैं और बोलते-बोलते निर्धारित समय जब

शेष नहीं बचने की स्थिति आती है और ऐसा होता है कि किसी और सदस्यों को बोलना है तो उस समय-समय को बढ़ाया जाता है तो इसमें किसको एतराज होगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, इसपर हम सिर्फ यह अनुरोध नहीं किये हैं माननीय मंत्री जी कि केवल मेरा ही समय बढ़ाया जाय हम तो कह रहे हैं कि जिसका जितना स्ट्रेंथ है जो बना हुआ है उसी हिसाब से चलना चाहिए । इसमें तो समय जो है सबको मिलना चाहिए, सबको इक्वल राइट है । यह तो हमारा अधिकार है, हम तो चाहेंगे कि हमारे अधिकार का हनन नहीं हो ।

अध्यक्ष : 37 मिनट आपका है, 37 मिनट कम है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हमारा तो 76 मिनट बनता है ।

अध्यक्ष : आप 37 मिनट में ही....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : समय अवधि तो बढ़ाया जाता रहा है, कई बार बढ़ाया गया है ।

अध्यक्ष : आपके अनुभव और परिपक्वता से लोग लाभान्वित होंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आसन पर थे तो आपने कई बार बढ़ाने का काम किया है और आज परंपरा का हवाला दे रहे हैं । परंपरा रही है तभी तो आपने अवधि भी बढ़ाई है । उसी परंपरा का हवाला हम दे रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हम जब अध्यक्ष थे तब आप मंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी थे और उस समय भी यही परंपरा थी सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी कि जब निर्धारित समय शेष नहीं बचने की स्थिति आती है उस समय सदन की सहमति से बढ़ाया जाता है और उसमें सरकार को क्यों एतराज होगा ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, निर्धारित की ही तो बात कर रहे हैं जब हमारा 74 मिनट बनता है और जब अध्यक्ष ।

अध्यक्ष : आप शुरू करें न ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम चाहते हैं कि आप पहले ही तय कर दें ताकि उसी हिसाब से जो बोलने वाले लोग हैं उनकी तैयारी रहेगी ।

अध्यक्ष : आप शुरू करें, गागर में सागर भरें । समय का हम ध्यान रखेंगे । आप शुरू करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : चलिए ठीक है, लेकिन चौधरी जी, जब हमलोग आपके साथ थे तो सबलोगों को छूट थी अपनी बात रखने का, लेकिन अभी क्या मजबूरी है वह आप ही बेहतर बता सकते हैं कि छूट क्यों नहीं मिल रही है लोगों को अपनी पूरी बात रखने का । अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलने का मौका मिला और हमलोग चाहेंगे कि अपनी

पूरी बात सरकार के सामने और आपके सामने रखें । सभी पार्टी है लगभग 10 पार्टियां हैं या उससे भी एकाध ज्यादा है, लगभग 243 सदस्य हैं । हमने पहले भी कहा कि एक बिहार की बेहतरी के लिए हम सब लोग यहां हैं । एक पॉजिटिव वे में सकारात्मक रूप से अपनी बात को रखनी चाहिए और बातों को सुनना चाहिए । कई बार हमने अभिभाषण पर जब वाद-विवाद हुआ तो हमलोगों ने कई आंकड़े भी पेश किये । एक बिहार का जो परसेप्शन बनाया गया था, प्रोपगेंडा जो बनाया गया था, जंगलराज का विकास नहीं हुआ । यह भी जो सरकार बार-बार ढिंढोरा पीटती रही है कि हमने बजट का आकार क्या था और हमने क्या कर दिया तो हमलोग तो महोदय इतना कहना चाहते हैं कि हमलोगों को तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो ज्ञान है और जिन तथ्यों को हमने समक्ष रखा है सरकार उसका भी उत्तर नहीं दे पाती है, चाहे बेरोजगारी का हो, लॉ एंड आर्डर का हो, किसानों का मुद्दा हो, स्वयं सहायता समूह का मामला हो या अन्य विषयों का मामला हो सरकार जो है कहीं भी जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो पारदर्शिता होनी चाहिए वह दिखायी नहीं देती है । हम धन्यवाद देना चाहते हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार को यू0पी0ए0-1 की सरकार को कि हमलोगों को सूचना का अधिकार दिया गया था कि हम सब लोगों को भी पता चले कि सरकार में विभागों में क्या होता रहा है वह सूचना का अधिकार के मामले में हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार कई बात को छिपाती है, बताती नहीं है । हमेशा ठगने का काम करती है इसीलिए हम कह रहे हैं कि सूचना का अधिकार का जो इंडेक्स है उसमें बिहार सबसे फिसड्डी है, मात्र 8 परसेंट ही है । जो सवाल पूछे जाते हैं सूचना के अधिकार में उसका जवाब केवल 8 परसेंट ही मिलता है, 100 फीसदी नहीं मिल पाता है, केवल 8 फीसदी मिलता है । ये कई बार फर्जी आंकड़े भी हमलोगों के सामने आया ।

क्रमशः

टर्न-12/हेमंत-राहुल/25.02.2021

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः (क्रमशः) महोदय, जब अलग-अलग विभागों से चर्चा चलती है तब फर्जी आंकड़े भी हम लोगों के सामने आए और जब वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, शायराना अंदाज था, हम लोगों को अच्छा लगा, सुशील मोदी जी से इनका गला थोड़ा साफ है तो थोड़ा ठीक लग रहा था । महोदय, हम तो इतना कहना चाहते हैं कि ये किसकी वाहवाही कर रहे थे, यहां वीरेन्द्र जी भी हैं, श्रवण जी भी हैं, चौधरी जी भी हैं, सात निश्चय कब बनाया गया था ? 2015 के चुनाव में साझा एजेंडा था हम लोगों का, महागठबंधन का एजेंडा था, सात निश्चय का । ये बात अलग है कि हम लोगों के रहने पर ये सारी सात निश्चय की योजनाओं की शुरुआत कर दी गई लेकिन हमारे

हटने के बाद उसमें भ्रष्टाचार का खेल होने लग गया । महोदय, इस चुनाव में हम लोगों ने देखा कि एन0डी0ए0 में भाजपा का अलग मेनिफेस्टो आता है, जदयू का अलग मेनिफेस्टो आता है और दलों का अलग-अलग मेनिफेस्टो आता है । जब बजट ये पेश कर रहे थे तब सात निश्चय-1 पूरा ही नहीं हुआ तो सात निश्चय-2 शुरू हो गया । क्या स्थिति है उन योजनाओं की, यह अगर सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने कलेजे पर हाथ रखकर बोलेंगे तो जो सच्चाई है वह सामने आ जाएगी, किसी से छिपी नहीं है । बीजेपी के जो लोग हैं उनका क्या एजेंडा है, वही लोग थे जो सात निश्चय का विरोध कर रहे थे, पूछिए वीरेन्द्र जी से, विजय जी से पूछिए । महोदय, भाजपा का सब लोग विरोध कर रहे थे और आज जब बजट भाषण पढ़ रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि कुछ नया है, वही पुराना पिटारा, झूठ का पुलिंदा, पूरे तरीके से सरकार ने पढ़ने का काम किया है । महोदय, हम लोग बार-बार कहते रहे हैं कि दो कैटेगिरी है, एक गवर्नेंस की और एक मिस गवर्नेंस की । नीतीश जी के राज में, डबल इंजन के राज में यहां न मिस गवर्नेंस है, न गवर्नेंस है, यहां कोई गवर्नेंस है ही नहीं, देयर इज नो गवर्नेंस, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है । महोदय, हम लोग सवाल पूछते हैं उसका कोई जवाब ठीक से नहीं मिलता है, उसका कोई समाधान नहीं होता है । महोदय, हम लोग ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एजेंसी के डेटा के अनुसार बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्ट राज्य है, जहां 75 परसेंट लोगों का बिना घूस दिए काम नहीं होता है । महोदय, यह हमारा आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एजेंसी का और जहां तक बात की जाय कि सीतामढ़ी में क्या हुआ यह हम सब लोगों ने देखा है । शराबबंदी की योजना क्या चल रही है, यह हम सब लोगों ने देखी है । यहां तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अब तो किसी की भी हत्या हो जाती है । पहले सुनत थे क्रिमिनल का एनकांउटर होता है, आजकल दारोगा जी का एनकांउटर हो रहा है और इससे शराबबंदी की हकीकत खुल गई लेकिन सरकार कोई गंभीर नहीं है । महोदय, आप भी यहां हैं, कार्रवाई चल रही है, आप देख रहे हैं कि सरकार में कोई गंभीरता नहीं है । हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इस बजट में पुलिस को बेहतर कैसे किया जाय, पुलिस को मॉर्डन कैसे बनाया जाय, पुलिस जिस जीप में घूमती है उसको लोग धकियाते है तब चलती है, क्या स्पीड रहती है, वह चलती कम धूआं ज्यादा फेंकती है। क्रिमिनल लोग आते हैं स्कॉर्पियो में ए0के0-47 के साथ और यहां सम्मान के लिए जब राइफल चलाई जाती है तो उसमें से गोली ही नहीं निकलती है । इस पर तो हम लोगों ने कुछ चर्चा नहीं की । कैसे हम बेहतर बनाएंगे, कई पद रिक्त/खाली हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे हमने एक उदारहण दिया कि लॉ एण्ड ऑर्डर को लेकर हमने आंकड़ा भी पेश

किया था, सही मायने में 1990 से लेकर 2005 तक का आंकड़ा पेश किया गया और 2005 से लेकर 2018 तक 13 साल इनका जो रिकॉर्ड रहा है वह पेश किया एन0सी0आर0बी0 का, इसमें साफ तौर पर दर्शाता है कि 101 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है । महोदय, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम एक कहानी सुनाना चाहेंगे । महोदय, जो चोर होता है वह बहुत ही होशियार होता है । एक गांव में भैंस चोरी हो गई, तो चोर ने सबसे पहले क्या किया कि भैंस की जो घंटी थी उसको निकाला और वे चोर तीन-चार लोग थे, घंटी निकालकर के एक चोर पश्चिम दिशा में भागने लगा और कुछ चोर भैंस को पूर्व दिशा में लेकर के चले गए, गांव वाले घंटी सुनते-सुनते पश्चिम दिशा में चले गए । हम यह कहना चाहते हैं कि इससे गांव वाले को क्या मिला, हाथ में घंटा । भैंस चोर लेकर भाग गया, तो भैंस का मतलब क्या है, महोदय सही शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेहतर कृषि व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी ट्रांस्पोर्टेशन की व्यवस्था और घंटी क्या है- हिंदू, मुसलमान । मोहनजोदाड़ो के टाइम का, हडप्पा के टाइम का जिक्र किया जाता है । इतिहास से हम लोगों को सीखना है और वर्तमान में उसका कार्यान्वयन करना है । महोदय, हमारा यह कहना है कि जनसरोकार से हम लोगों का लेना-देना है । महोदय, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमलोग घंटी की चिंता न करें भैंस की चिंता करें और उस पर चर्चा करें लेकिन यहां घंटी पर चर्चा की जाती है । महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे कि बड़े ही महत्वपूर्ण बजट का जो आकार रखा गया है । बजट में क्या रखा गया ? कुल बजट जो 2021-22 का वह 2 लाख 18 हजार करोड़ है । कुछ सदस्य जिनको जानकारी नहीं है वह टेबल पर ताली मार रहे हैं तो इनकी कोई गलती नहीं है, यह घंटी के फेरा में रह गये, इनकी कहां गलती है । लेकिन असल में सरकार की जो चोरी है, आंकड़ों के साथ जो होशियारी है, वह हम लोगों ने पकड़ी । अब जिक्र अगर हम लोग करें महोदय, पिछले वित्तीय वर्ष का अभी का तो अप्रील से चलेगा और अप्रील तक तो 2020-21 वाला चलेगा। पिछली बार का जो बजट था वह 2 लाख 11 हजार करोड़ का था और अब का है 2 लाख 18 हजार । हम एक आंकड़ा पेश करना चाहते हैं मीडिया के साथी भी यहां सुन रहे हैं । छपता है कि इतना आकार बढ़ गया । थोड़ा हम आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे कि जो हककीत है वह भी रखी जाय ताकि जनता, आप और हम सब लोग सही से मूल्यांकन कर सकें और यह मूल्यांकन जो होगा वह बिहार की बेहतरी के लिए होगा कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वह सही हाथों में हमारा बिहार है कि नहीं है ? मीडिया तो अपना काम करता है लेकिन लाठी-डंडा तो हम लोगों ने इन पर कभी नहीं बरसवाया । लेकिन आज यह भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है, लाठी-डंडा बरसाया जाता है । आंकड़ा हम रखना चाहते हैं,

यह आंकड़ा कोई अपना नहीं है, इन्हीं का जो बजट है सुशील मोदी जी द्वारा जो 2020-21 का बजट पेश किया गया, इसी बजट से हमने यह सारा निकाला है और हम लोगों ने देखा है । महोदय, इस बजट में, 1990 में जब लालू जी को सत्ता मिली, उस समय जनता दल हुआ करता था, उस समय सत्ता मिली तो बिहार का कुल अप्रोक्स बजट था वह 3 हजार करोड़ का था, महोदय, 2005 में वह 24 हजार करोड़ हो गया । 90 में कितना ? 3 हजार करोड़ और 2005 में 24 हजार करोड़ यानी कितना बढ़ा ? 8 गुना बढ़ा । अब 2005 का जो बजट था वह 24 हजार करोड़ । 2020-21 का 2 लाख 11 हजार करोड़ यानी कितना बढ़ा ? 8 गुना । गुना तो उतना ही बढ़ा है, तो किस बात का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने आकार बदल दिया । हमको क्या मिला था और हमने 8 गुना बढ़ाया और वही चीज चलती आ रही है । नहीं समझ आ रहा है तो भारत सरकार का बजट भी आपके सामने रख देते हैं । महोदय, 2005 में बिहार का बजट 24 हजार करोड़ था और भारत सरकार का बजट 4 लाख 53 हजार करोड़ था । आज 2021 है, बिहार का बजट 2 लाख 18 हजार करोड़ है और भारत सरकार का 35 लाख करोड़ । यानी भारत सरकार का कितना बढ़ा, 8 गुना । अब हम जानना चाहते है कि यह जो सत्ता में बैठकर वाहवाही लूटते हैं कि हमने इतना आकार बढ़ा दिया, हमने भी उतना ही बढ़ाया, उसी तेजी से बढ़ाया, उसी तेजी से भारत सरकार का बढ़ा । लेकिन हम फिर से धन्यवाद मनमोहन सिंह जी का करेंगे कि वह जब फाइनेंन्स मिनिस्टर थे ।

(क्रमशः)

टर्न-13 एवं 14/ राजेश-मुकुल-संगीता

क्रमशः

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः महोदय, उदारीकरण जो आया, उसके बाद जो है देश को फायदा हुआ, राज्य को फायदा हुआ, उदारीकरण के बाद और ज्यादातर तो हम लोग असर जो उदारीकरण का जो हुआ वर्ष-1991, 1992 और 1993 में, उसका फायदा तो 2000 के बाद से मिलना शुरू हुआ । अब एक और आंकड़ा महोदय अगर हम रखें, कम्पेयर हम कर रहे हैं लालू जी के राज का और नीतीश जी के राज का । वर्ष 2005-06 में स्टीमेटेड जो बजट था, वह लगभग 24000 करोड़, सरकार का कर एवं गैर कर राजस्व जो रेवेन्यू अमाउंट था, वह 4083 था महोदय, यानी स्टेट रेवेन्यू का 20.36 परसेंट और उसमें जो सेंट्रल का जो ग्रांट होता है, जो शेयर होता है, वह 57.58 परसेंट । यह 2005-06 का है यानी राजस्व का

जो शेयर था 24,000 करोड़ में से, वह 4,083 था यानी 20 परसेंट होता है और 57 परसेंट जो बाकी का बचा हुआ वह सेंट्रल का जो ग्रांट होता है वह था । 2021 और 2022 में महोदय, जो हमारा स्टीमेटेड है, 21 जो इन्होंने पेश किया है वित्त मंत्री जी ने 2 लाख 18 हजार और सेंट्रल का उसमें महोदय जो शेयर है एक लाख 45 हजार 711 और राज्य का रेवेन्यू अमाउंट जो है वर्ष 2021-22 में 40,553 यानी राज्य का 18.57 और सेंट्रल का 66. 74, हम यह कहना चाहते हैं कि वर्ष 2005-06 में राज्य का रेवेन्यू जो था बजट में, जो शेयर था वह 20.36 था, वर्ष 2005-06 में जब ये सत्ता में आये, जब हम लोगों ने दिया, जो हमारा आखिरी कार्यकाल था और 2021-22 में राज्य का जो शेयर हो जाता है 18.57 यानी मेरे कहने का, इन आंकड़ों को रखने का यह मतलब है महोदय कि विगत 15 वर्षों में राज्य के अपने रिसोर्स से प्राप्त राजस्व में लगभग 2 फीसदी की कमी आई है । अपना क्या है, हमारे समय में 2 परसेंट ज्यादा था, आप में तो घट गया 2 परसेंट और महोदय हम यह कहना चाहते हैं और वह भी तब जब सेंट्रल टैक्स में जो है अमाउन्ट, अगर आप देखियेगा सेंट्रल का महोदय, तो इस बार जो मिला है एक लाख 45 हजार 711.81 यानी जो सेंट्रल टैक्स 10 परसेंट हम लोगों से ज्यादा बढ़ा है ।

अध्यक्ष: आप आसन की ओर देखें और बोलते रहें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के 10 परसेंट जो है बढ़ाया गया, सेंट्रल का यानी सेंट्रल ने इन्क्रीज किया 10 परसेंट, हम लोगों को वह छूट नहीं मिला, हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होता था, हम लोग लगातार इस चीज का जिक्र करते रहे और अभी जो इनका खुद का रेवेन्यू जो है, जो बजट का जो खुद का इनका रिसोर्स है, वह 2 परसेंट माइनस में आ गया । महोदय, और एक बात जान लीजिए लालू जी जब सरकार में थे तब हमारा रेवेन्यू 2 परसेंट ज्यादा था, तब की तब जब हम लोगों ने जल कर में मल्लाह भाइयों के लिए माफ किया था, पासी भाइयों के लिए ताड़ी में टैक्स माफ किया था और यह भी जान लीजिए उस समय पेट्रोल-डीजल का क्या टैक्स होता था, आज देख लीजिए टैक्स कितना है और आप कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बजट का आकार बढ़ाया, आज बता दीजिए कोई चीज में माफी हो रही है बल्कि तब कच्ची तेल की कीमतों का महोदय .....

(व्यवधान)

ऐसे नहीं चलेगा, अरे आप क्या बोलियेगा । आप बैठिये न, बैठिये, पहले ध्यान से सुन लीजिए ।

अध्यक्षः बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, सच कड़वा होता है ।

अध्यक्षः नेता प्रतिपक्ष, आप इधर-उधर मत देखिये, आप आसन की ओर देखिये और बोलते रहिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, हमने न किसी का नाम लिया, न कुछ कहा, हम तो आप ही के तरफ देख रहे हैं ।

अध्यक्षः आप बोलते रहें, आपका समय कीमती है, आप बोलते रहें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः महोदय, कीमती तो है लेकिन जिम्मेवारी भी है और लोगों की उम्मीद भी है कि हम लोग सही बात रखेंगे । अब हम एक और आंकड़ा देना चाहेंगे । अध्यक्ष महोदय, एक आंकड़ा हम देना चाहेंगे वर्ष 2020-21 का टोटल एक्सपेंडिचर जो है, स्टीमेटेड जो था वह 2 लाख 11 हजार था । अगर हम आपको बतायें सही मायने में महोदय, तो पिछला बजट में 2 लाख 11 हजार करोड़, अभी पिछला बजट का अप्रील में खत्म हो जायेगा यानी 1 महीने में वह राशि खत्म हो जायेगा ? आपने 2 लाख 11 हजार करोड़ में केवल 70 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किये और हमको जो सूचना है कि इसी 23 तारीख को लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं 23 तारीख तक का, केवल 70 हजार रुपये ही खर्च हुआ महोदय, यानी आप यह बताइये कि बजट का...

अध्यक्षः नेता प्रतिपक्ष, 70 हजार करोड़ रुपये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः 70 हजार करोड़ वही बोल रहे हैं । महोदय, तो आप समझिए कि 33 परसेंट पिछले बजट का अब तक खर्च ही नहीं हो पा रहा है । अब यह बताइये, महोदय जो 70 हजार करोड़ रुपया 1 साल में नहीं खत्म कर पाये, वह 1 लाख 43 हजार करोड़ रुपया जो बचता है वह क्या होगा, क्या 1 महीना में खत्म कर देंगे ? मार्च पिछे से बोल रहे हैं, हम यह बताना चाहेंगे कि अधिकारियों में एक बड़ी चर्चा है महोदय, मार्च के महीने का एक फेमस नया नाम है मार्च लूट, मार्च लूट, अधिकारियों से पूछियेगा वे

जानकारी दे देंगे आपको, होना चाहिए मार्च लूट के नाम से, तब आप समझिए कि एक लाख 43 हजार करोड़ रुपया बचा ही हुआ है, वह एक महीना में खर्च हो जायेगा, जब एक साल में 70 हजार करोड़ नहीं खर्च हुआ तो अब ये सूचना जो है, अब हम एक एग्जाम्ल ही दे देते हैं, डिपार्टमेंटवाइज एक्सपेंडिचर का, मेरे पास सूची है । ठीक है महोदय, एक तो होता है एक्सपेंडिचर, एस्टेब्लिशमेंट जिसका अमाउंट फिक्स रहता है, वह पैसा जाता रहता है, एक होता है नेट पेमेंट महोदय, एक होता है स्कीम की योजना में, उसमें कम-ज्यादा होता रहता है, अब अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हम लोग ले लें, तो आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें जो खर्चा हुआ महोदय, 179 करोड़ और स्कीम पर जो खर्चा हुआ महोदय टोटल जो स्कीम का है वह 665 करोड़ नेट पेमेंट महोदय, यानी जो अब तक हुआ है, वह 281 करोड़ रुपये हुआ है यानी 562 करोड़ का अभी खर्च ही नहीं किया गया है । यह हकीकत है महोदय, ऐसे-ऐसे सारे डिपार्टमेंट के हैं । अब यह खर्च क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, यह तो नेता सदन जो हैं मुख्यमंत्री जी, बतायें कि इसमें क्या मैटर है, मार्च लूट क्या है, यह भी मुख्यमंत्री जी बतायें विस्तार रूप से, यह सदन को जानने का अधिकार है, हम लोगों को पता रहना चाहिए महोदय । अब क्या हो रहा है महोदय, अब तो हम नहीं कहना चाहते हैं लेकिन आप देखियेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडैक्स, अब इसमें हम कुछ-कुछ बतायेंगे कि हम लोगों के समय में कितना सौतेला व्यवहार होता था । पहले हम यह बता दें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडैक्स जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है, को देखें तो पाते हैं कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी की सरकार के कार्यकाल में बिहार का स्थान 32वां स्थान पर था और आज 2020 में वह 36वां स्थान पर है महोदय । विभाजन से पहले बिहार का कर्ज 28 हजार करोड़ था, विभाजन से पहले जो कि विभाजन के बाद 41 हजार करोड़ हो गया, तब केन्द्र सरकार ने मोरेटोरियम जो होता है, मदद जो होती है, वह भी नहीं किया गया है महोदय और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, केन्द्र में तब आप लोगों की ही सरकार थी महोदय । अब यह बताइये बिहार जब बंटने से पहले 28 हजार करोड़ का था, बिहार जब बंट गया, तो झारखंड का भी जो बोझ था, वह भी हम लोगों पर लाद दिया गया, टोटल होता है 41 हजार करोड़ का महोदय, यह स्थिति थी उस समय, कितना बिहार को जो है नीचा दिखाने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार करने का काम किया गया

और नीतीश कुमार जी महोदय केंद्र में मंत्री थे, अटल जी बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उनका हम मान-सम्मान करते हैं, हम और हमारे पिता सब लोग मान सम्मान करते हैं, आज उनकी कमी हम सब लोगों को खल रही है । महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन नीतीश जी ने किस प्रकार से अपने को सत्ता में लाने के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल किया, दबाव पॉलिटिक्स किया, यह किसी से छुपा नहीं है । इसी गांधी मैदान में सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाली मेरी माता, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थीं, आंचल फैलाकर अटल जी के सामने जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की लेकिन नीतीश जी साथ एयरपोर्ट जाते-जाते रिफ्यूज करवा दिए, तो हम तो यही कहना चाहते हैं तब भी राबड़ी जी की सरकार के समय लगभग 5 प्रतिशत विकास दर था महोदय, 5 प्रतिशत विकास दर था, जबकि भारत सरकार का उस समय विकास दर अप्रोक्सीमेटली 6.6 था, नेशनल जब 6.6 था, तो हमारा 5 था, इतना बोझ, इतना सौतेला व्यवहार के बाद भी । सौतेला व्यवहार इससे भी पता चलता है महोदय, सेंट्रल जो टैक्सेशन का शेयर राबड़ी जी के कार्यकाल में कम कर दिया गया महोदय, अब हम उदाहरण देंगे, कैसे कम किया, आंकड़ों पर । आंध्रप्रदेश को महोदय उस समय सेंट्रल टैक्सेशन में 3,507 करोड़, वर्ष 1998-2000 में एडीशनल सेंट्रल असिस्टेंस मिला, वहीं बिहार को देखिए, आंध्रा को 3,507 और बिहार को केवल 306, 2003 में आंध्रा को 9,790 और वहीं बिहार को मात्र सेंट्रल ग्रांट मिला 4047 महोदय और आगे देखिएगा तो आंध्र प्रदेश को नेट लोन में भी जो है 6902 करोड़ मिला, वहीं बिहार को 2849 करोड़ ही मिला महोदय । अब आप देखिएगा, परकैपिटा सेंट्रल असिस्टेंस में भी वर्ष 2000 से 2001 में आंध्र प्रदेश को परकैपिटा असिस्टेंस में रूपये 626 मिला, वहीं बिहार को 276 मिला, जबकि तब उस समय झारखंड बिहार एक था महोदय । वर्ष 2001 का अगर आर0बी0आई डेटा देखें तो सड़क निर्माण के लिए बिहार को मात्र 369 करोड़, बिहार की जो आबादी थी यानी प्रति व्यक्ति मात्र 44 रूपये होता है जबकि आंध्र प्रदेश को मिला महोदय, एक हजार 210 करोड़ मिला, जो कि प्रति व्यक्ति 160 रूपये होता है । महोदय, गुजरात को 902 करोड़ मिला, जबकि प्रति व्यक्ति आय 179 रूपये होता है, तमिलनाडु को 640 करोड़ मिला, 104 रूपया प्रति व्यक्ति होता है, वहीं वेस्ट बंगाल को 932 करोड़ मिला, जो प्रति व्यक्ति आय 116 है यानी उसमें भी बिहार को प्रति व्यक्ति मात्र

44 रूपया मात्र लगभग 370 के आस पास मिला महोदय । इस प्रकार से जो है सौतेला व्यवहार होता रहा और उस समय हमको याद है, हम होश में थे, डेढ़ दर्जन बिहार के केंद्र में मंत्री थे, क्या किया उन केंद्र के मंत्रियों ने ? जवाब तो उनसे पूछना चाहिए तो महोदय वित्त मंत्री जी काफी शायराना अंदाज में थे, तो हम भी जो हैं कुछ शायरी हम भी पढ़ दें ।

अध्यक्ष : जरूर, जरूर ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल :

''मुझमें हजार खामियां हैं माफ कीजिए,

पर अपने आईने को भी तो कभी साफ कीजिए ।''

महोदय, इसमें अब एक और डेटा हम लाते हैं महोदय । अब हम प्रति व्यक्ति आय जो लोग कहते हैं इतना मिला, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी या बिहार सरकार के लोगों ने, कभी बताया कि बिहार पर बोझ और कितना कर्ज बढ़ गया प्रति व्यक्ति, यह भी नहीं बताया, तो छुपा-छुपी नहीं चलेगा न महोदय । अब हम हमलोग प्रयास करें एक्स, वाई, जेड का, एक्स, वाई, जेड होते ही पता नहीं कहां चले जायेंगे लोग इसलिए महोदय यह जो हम बताना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि जी0डी0पी0 जो है बढ़ा है, अरे जब जी0डी0पी0 बढ़ा, तो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट न करना चाहिए, आपके राजस्व को दिखना न चाहिए कि कितना राजस्व है, आपका तो 2 परसेंट घट गया, आपका जो खुद का है, उसमें तो घट गया, तो जी0डी0पी0 बढ़ गया, अरे भाई कैसे बढ़ गया ? बढ़ता तो बेरोजगारी इतनी नहीं होती, क्या कारखाना उद्योग लगा, नहीं लगा, तो जी0डी0पी0 कैसे बढ़ गया, किस हिसाब से बढ़ गया ? पर्यटन बढ़ा, नहीं बढ़ा, तो कैसे जी0डी0पी0 बढ़ गया, तो किस हिसाब से बढ़ा भाई ? कहां बढ़ा रहे हैं आप, अभी आंकड़ा देखिएगा महोदय, देश में प्रति व्यक्ति औसत बता रहे हैं, प्रति व्यक्ति औसत जी0डी0पी0 देश में सबसे कम है, देश में सबसे कम है, सबसे नीचे बिहार का रैंक है, यह हकीकत है । ये मेरा आंकड़ा नहीं है, इन्हीं लोगों का आंकड़ा है । महोदय, वर्ष 2005 में बिहार का परकैपिटा इन्कम एप्रोक्सीमेटली 8 हजार था, भारत का लगभग जो था 26 हजार था, 8 हजार था वर्ष 2005 में बिहार का और भारत का नेशनल जो था वह 26 हजार था । वर्ष 2020 में यह बढ़कर परकैपिटा इन्कम जो है 46 हजार 664 हो गया और भारत का लगभग 1 लाख 51 हजार 111 हो गया। अब आप कहते हैं कि हम इतना बढ़ा दिये, इतना बढ़ा दिये, अब हम आपको एक ही

स्टेट का उदाहरण दे देते हैं, उड़ीसा । उड़ीसा का वर्ष 2005 में 18,194 था और वर्ष 2020 में हो गया महोदय यह तकरीबन, आप देखिएगा, 1 लाख 7 हजार हो गया और बिहार का 46 हजार, उड़ीसा जैसा राज्य, तो जिस हिसाब से उड़ीसा ने तरक्की की, उस हिसाब से तो आपने कुछ नहीं किया, खाली ढकोसला है महोदय यह और सरकार बताये वर्ष 2005 में प्रति व्यक्ति कर्ज क्या था, आप जिक्र करते हैं, बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री जी, जरा प्रति व्यक्ति क्या कर्ज था वर्ष 2005 में, जरा यह भी बताइये ? वर्ष 2005 में बिहार का कुल कर्ज का कितना भार था, आप यह भी बताइये और आज का कुल भार कितना है, यह भी बताइये, यह तो आप बताते नहीं हैं महोदय । अब हमलोग बिजली की अगर बात करें, तो मुख्यमंत्री जी ने तो उसी दिन स्वीकार किया है कि बिहार में बिजली सबसे महंगा है, बिजली उत्पादन होता नहीं है, प्रोडक्शन है नहीं और सबसे महंगा बिजली का जो दर है, वह बिहार में ही है, यह तो किसी से छुपा नहीं है, यह तो इस बात को भी कह रहे हैं । हमने उस समय भी टोका था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी वर्ष 2003 में जब इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 का बना, उस समय तो आप कैबिनेट में थे, आप तो पास करवाये और आज कह रहे हैं 'वन नेशन वन रेट' तो यह तो डुअल स्टैंडर्ड है महोदय, आप करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, यह तो धोखा देने वाली बात है । अब अगर बात किया जाय परकैपिटा कंजप्शन का, मुख्यमंत्री जी ने कंजप्शन के बारे में नहीं बताया, बिजली कितना कंज्यूम करती है बिहार ? कंजप्शन क्या है हमारा ? भारत का वर्ष 2005 में 500 था महोदय किलोवॉट, वह वर्ष 2020 में हो गया 1250, बिहार का किलोवॉट 2005 में 90 था, अब हो गया 310 महोदय, उत्तर प्रदेश का 265 था वर्ष 2005 में, वर्ष 2020 में 610, बंगाल का वर्ष 2005 में 405 किलोवॉट था और अब हो गया 1650, उड़ीसा का 500 था वर्ष 2005 में, अब वर्ष 2020 में 1250 हो गया, तो आप सबसे पीछे हैं, 310 ही किलोवॉट है महोदय, सबसे पीछे यानी सबसे कम कंज्यूम हम करते हैं । मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम हर घर बिजली दे दिये और बिहार की आबादी इतना है, तो कंजप्शन कैसे कम है ? आप सबसे ज्यादा कंज्यूम कहां किए ? आप तो सबसे पीछे हैं इसका बात बताना चाहिए । इस तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है महोदय कि पूरे भारत में बिहार की मासूम जनता सबसे महंगे दर पर जो है, वह बिजली खरीद रही है और सबसे कम इसके उपभोक्ता हैं महोदय । यह सारी बातें, तो सरकार ने तो छुपाने का काम किया महोदय और हम आंकड़ा दे दें महोदय, लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की । एक योजना है वित्तीय वर्ष 2020-21 का हम बता दें, यह योजना है उद्यमी योजना । यह उद्योग विभाग की योजना है, युवाओं से, रोजगार से संबंधित है । ये लोग कहते हैं कि 20 लाख रोजगार देंगे, व्यवस्था करायेंगे, अभी आप देखिए, रोजगार हेतु

प्राप्त आवेदन 45 हजार 621, चयनित लाभुकों की संख्या 4 हजार 800, वास्तविक लाभुकों की संख्या 3600, ध्यान से सबलोग सुनें, 45 हजार 631 लोगों ने आवेदन किया, उसमें से जो चयनित किए गए पहले वह पहले मात्र 4 हजार, 45 हजार में से मात्र 4 हजार आप चयनित करते हैं, फिर आप घटाकर के फिर चयनित करते हैं, जिसको वास्तविक में चयन किया गया, वह लाभुकों की संख्या केवल 3 हजार 641 है । ..क्रमशः..

टर्न-15/सत्येन्द्र/25-2-21

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल(क्रमशः) फिर आप घटाकर के चयनित करते हैं, जिसको वास्तविक में चयनित किया गया वैसे लाभुकों की संख्या है वह केवल 3641 है । आप जो है इनको रोजगार नहीं दे सकते हैं बल्कि आप घटाते जा रहे हैं और आपने टोटल वितरित राशि का खर्च हुआ मात्र 93 करोड़, यानी 3641 लोगों पर आपलोगों ने खर्च किया मात्र 93 करोड़ रू0 महोदय । बताइए, इस हिसाब से आप कैसे 20 लाख को रोजगार दीजियेगा और पूरा इंडस्ट्री का बजट आप देखिये 1285 करोड़ रू0 है । मात्र 1285 करोड़ रू0 और आप बीस लाख लोगों को कैसे रोजगार दे सकते हैं, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए । मुख्यमंत्री जी, हमलोग सब लोग हाउस, हमलोगों ने पारित किया कि भाई जो अनुसूचित जाति, जनजाति या, एक कास्ट सेंसेस होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए। आप भी थे महोदय सदन में, मुख्यमंत्री जी कहते हैं होना चाहिए, खाली कहते है, यह होना क्यों चाहिए, हम क्यों चाहते हैं कि कास्ट सेंसेस हो यह इसलिए हो ताकि हमको पता चल जाय कि कौन से तबके गरीब हैं, कमजोर हैं । उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, बजट में प्रावधान करेंगे । एस0सी0 भाइयों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, एस0टी0 भाइयों के लिए, अति पिछड़ा भाइयों, पिछड़ा भाइयों के लिए या और जो लोग हैं सवर्ण जाति के जो हमारे भाई है सबका बजट में उसी हिसाब से जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से हम बजट में आवंटन करेंगे । आपकी यहां सरकार है महोदय, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । हकीकत देख लीजिए तो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का बजट जो मंत्री जी ने पेश किया है, वित्त मंत्री जी ने वह बजट पूरे बजट का मात्र 0.78 प्रतिशत है । 1749 करोड़ एस-सी0, एस-टी0वर्ग का है 0.83 प्रतिशत कुल बजट का यानी 1803 करोड, अल्पसंख्यक विभाग को मात्र 562 करोड़ जो कि पूरे बजट का 0.26 प्रतिशत है । महोदय, अगर इन सभी वर्गों की आबादी निकाली जाय तो लगभग 70 से 80 फीसदी और 70 से 80 फीसदी के लिए बजट बना रहे हैं 0.78 प्रतिशत का, 0.83 एक प्रतिशत में भी नहीं आया और इनकी इतनी बड़ी आबादी और आप कहते हैं कि जातीय जनगणना हो सके ।

महोदय डिप्टी सी0एम0 जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं, देख लीजिये उनके लिए 0.78 प्रतिशत का ही कुल बजट है महोदय । ये तो शर्मनाक हैं महोदय, अल्पसंख्यकों के लिए मात्र मंत्रालय में 0.26 प्रतिशत कुल बजट का, लगभग 16 प्रतिशत 17 प्रतिशत आबादी है महोदय और क्या बात कर रहे हैं महोदय, मुख्यमंत्री जी, लोन दे रहे हैं, छात्र लोग को लोन दे रहे हैं । पहले हमलोग देते थे, हमलोग ग्रांट देते थे हमलोग जो देते थे छात्रवृत्ति वगैरह चलता था, अब क्या हो गया है महोदय, बैंक की स्थिति तो कंगाल हो गयी है पूरे देश में, अच्छे अच्छे जो बिहार में जो कारोबारी है उनको लोन नहीं मिल रहा है छात्रों को लोन मिलेगा । यह स्थिति बनी हुई है, क्या मजाक बना लिया है महोदय, ये बजटीय आंकड़े इसलिए महोदय कह रहे थे जनता सब देख रही है तो हम इसी पर एक और शायर हम कहेंगे महोदय:–

''तू कर ले हिसाब
अपने हिसाब से।
जनता हिसाब लेगी
अपने हिसाब से ।''

महोदय, ये मजाक बना दिया गया है, बिहार गजट को पढ़ा जाय तो महोदय बिहार के गजट में 2 लाख 95 हजार तालाब थे और अभी जल जीवन हरियाली, महोदय 26 हजार करोड़ का है न, लगभग 24 हजार करोड़ 22 हजार करोड़ जो भी हो, तालाब की संख्या बिहार के गजट में 2 लाख 95 हजार तालाब थे, आज मात्र 95 हजार तालाब दिखते हैं । राजधानी पटना में महोदय तालाबों का शहर कहा जाता था महोदय, अकेले पटना राजधानी में 1050 तालाब थे । विगत वर्षों में तालाबों की हत्या कर दी गयी, 80 प्रतिशत सब्सिडी निजी तालाबों के निर्माण के लिए दी जाती है जो गहरे भ्रष्टाचार का प्रतीक है महोदय । ये बाकी में यही स्थिति है और आप बात करते हैं जल जीवन हरियाली की, यह पूरा खाली घोटाला का ही सेंटर है, कैसे तालाब खत्म हुआ है, यह बिहार के गजट में देखियेगा तो 2 लाख 95 हजार तालाब लिखा हुआ है, पटना जो है उसको तालाबों की राजधानी बोली जाती थी । हम तो ज्यादा कुछ महोदय, बहुत कुछ हम कहना चाहते थे लेकिन एक चीज देखा जाय महोदय तो बी0जे0पी0 के मंत्रियों की संख्या जो है भारी है, ज्यादा है जद(यू0)से, अब एक अखबार छपा कि भाजपा के मुकाबले जद(यू0) के मंत्रियों के पास दोगुना बजट । लगता है लड़ाई आप लोग ठीक से लड़े ही नहीं, संख्या में मंत्री ही भले ही ज्यादा है लेकिन आपके पास जितना बजट बनाने का है उससे दोगुना से भी ज्यादा मुख्यमंत्री अपने पास रख लिये हैं । आप लोग...

(व्यवधान)

पता नहीं आपको मुकेश जी, सुन लीजिये, आप तो रिचार्ज कूपन हैं आपका फिर रिचार्ज हो पायेगा ? कहां फंस जाते हैं, बैठे रहें अरे बैठिये न, काम कीजिये, काम कीजियेगा नहीं बोलेंगे । अध्यक्ष महोदय आज दो दो उप मुख्यमंत्री है...

अध्यक्षः आपस में बातचीत न करें । नेता प्रतिपक्ष आप इधर देखें, उधर भटक क्यों जाते हैं ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः एक बात बतलाइए बिहार ने आजतक देखा है कि दो उप मुख्यमंत्री हुए हों, पहली बार न देख रहे हैं ।

अध्यक्षः बहुत चीज पहली बार देखियेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः हम तो इन्हीं के हित की बात कह रहे हैं । हमलोग तो बोल रहे हैं कि आपलोग नये नये हैं, थोड़ा चालाकी को समझिये नहीं तो जो सुशील मोदी जी का हश्र हुआ है, वही आपलोगों के साथ न हो जाये ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः बैठे बैठे नहीं बोलिये । आप पुराने सदस्य हैं खड़ा होकर बोलिये । बोलिये, क्या बोलना है?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, ये मुख्य प्रवक्ता हैं । अब आप देखिये, मुख्यमंत्री जी हमसे पूछे रहे थे कि 18 महीने में आपका अनुभव कैसा रहा तो हमने तो ईमानदारी से काम किया, उनको भी बताना चाहिए कि 18 महीना मेरे साथ काम करते हुए आपका कैसा अनुभव रहा, कितना हमने हस्तक्षेप किया । क्या वह आज हो रहा है, हम तो अपने डिपार्टमेंट में काम करते थे । आज तो खर्च नहीं हो रहा है जब हम डिपटी सी0एम0, पथ निर्माण मंत्री के, जरा फाईल मंगवाइयेगा उस समय 5 हजार करोड़ का बजट था, 5 हजार करोड़ के अतिरिक्त भी लेकर हमने खर्च किया और यहां खर्च हो ही नहीं रहा है तो जरा उनको अनुभव मेरा बताना चाहिए। हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव लेकर गये, अभी मंत्री जी ई0ओ0टी0 का फाइल, भेरियेशन का फाइल, स्टीमेट का फाइल साईन मत कीजियेगा । सरकार बदलेगी तो कब कौन एजेंसी पीछे लग जायेगा समझ जाइए क्योंकि हम आपको इसलिए बतला रहे हैं चूंकि आपका वर्किंग डिपार्टमेंट में आप नोडल डिपार्टमेंट हैं, हैं कि नहीं ?

अध्यक्षः आप मंत्री की ओर मुखातिब हैं, इधर आसन को नहीं देख रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विराधी दलः हम वाजिब बात कर रहे हैं महोदय।

अध्यक्षः तो उनको सावधान करेंगे, सब अनुभव अलग से भी शेयर कर लीजियेगा न । आप मंत्री की ओर मुखातिब हैं, इधर आसन की ओर....

टर्न-16/पुलकित-सुरज/ 25.02.2021

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हम बजट पर बात कर रहे हैं, महोदय ।

अध्यक्ष : उनको सावधान करेंगे, सब अनुभव हो, अलग से भी शेयर कर लीजिएगा न ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, छोटे भाई को पहले अनुभव हो गया तो बड़े भाई को बता रहे हैं ।

अध्यक्ष : ये सब अनुभव अलग से शेयर करिएगा । इधर मुखातिब होइए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हमने केबिनेट में ये प्रस्ताव लेकर के भ्रष्टाचार । अब बताइए कोई संवेदक अगर काम नहीं कर रहा है समय पर तो उसके टाइम को बढ़ाने के लिए हम साइन करेंगे । कितनी बिल्डिंग में ईंट, छड़, लोहा-लक्कड़ लग रहा है वह हम तय करेंगे । समय के साथ चीजों का पैसा बढ़ता रहता है, कीमतें बढ़ती रहती हैं सामानों का ।

अध्यक्ष : अब उधर कोई संवेदक नहीं है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : लोहे की कीमत बढ़ी, पेट्रोल का दाम बढ़ा तो हम साइन करेंगे यह तो इंजीनियर का काम है न । हमारा, मंत्रियों का काम होता है, पॉलिसी मेकिंग ।

अध्यक्ष : अब शांति बनाए रखिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम ये कैबिनेट लेकर के गए थे ।

अध्यक्ष : आप इधर-उधर ताकेंगे, सभी को बोलने का मौका देते हैं । आप इधर ताकते रहिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम तो प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं महोदय ।

अध्यक्ष : इधर-उधर मत देखिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : एंटी करप्शन जो काम हम किए हैं उसका विवरणी दे रहे हैं महोदय ।

अध्यक्ष : अब शांति बनाए रखिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हमने प्रधान सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाई मंत्री को क्या लेना-देना भैया ? अब जो पथ निर्माण तय कर देगा वही इरिगेशन, ग्रामीण कार्य, बिल्डिंग के जितने कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको उसी लॉ से चलना पड़ेगा अब पता नहीं ये पलट गया कि नहीं पलट गया । मतलब संवेदक देगा मंत्री जी थोड़ा टाइम दिलवा दीजिए, ले लीजिए । इसलिए न फाइल आता था । मंत्री जी, थोड़ा इस्टीमेट बढ़वा दीजिए । अनुभव बढ़वा दीजिए । समझे ।

(व्यवधान)

आपको एक बात समझना पड़ेगा इतने कम समय में अनुभव हो गया कि आपकी सरकार चोरी कैसे कराती है ।

बात समझिए । अब मंत्री जी भले ही बताएंगे जब भाषण देंगे अपनी मांग पर तो जरूर इसका जिक्र कीजिएगा कि अभी भी स्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैबिनेट का डिसीजन, ये होना चाहिए । तो महोदय हम ज्यादा कुछ न कहते हुए मुख्यमंत्री जी बार-बार सी, थ्री सी, थ्री सी की बात करते हैं महोदय तो वही सी का इन्होंने कम्परमाइज करके सी ग्रेड की पार्टी बनकर कर रह गए महोदय । ट्रिपल सी, ट्रिपल सी । वही सी से कम्परमाइज करके सी ग्रेड की पार्टी बन गई, उसी सी से कॉन्सपिरेसी करके हार गए । बोले थे न मुख्यमंत्री जी, जब उन लोगों का मंथन चल रहा था दफ्तर में..

अध्यक्ष : आप फिर इधर देखिए । उधर किससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, इधर देखिए न । इधर देखिए, उधर मत देखिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, देख रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं ।

अध्यक्ष : चलिए बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : कान भी है महोदय सुन लेते हैं तो इधर भी चला जाता है।

अध्यक्ष : ठीक है, चलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा था न हमको कॉन्सपिरेसी किया गया है । उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बोले न कॉन्सपिरेसी से हमको कम सीटें आई हैं तो वही सी से कॉन्सपिरेसी से हार गए और खुद कह रहे थे महोदय अब सिटीजेन वही सी के सिटीजेन की नजर में इनके कॉमेंट की कोई क्रेडिब्लिटी नहीं रह गई है महोदय, मुख्यमत्री जी की ।

15 साल में 65 घोटाले हुए हैं महोदय । आज बजट पर हमलोग चर्चा कर रहे हैं। 65 घोटाले हुए हैं महोदय जिसमें बिहार का लगभग 40 हजार करोड़ रूपए की लूट की गई । बजट में इसका कोई जिक्र नहीं कि वह पैसा हम कैसे रिकवर करेंगे । ये पैसा आपका-मेरा नहीं था महोदय । ये बिहार के आमजनों का पैसा था । क्या सरकार ने कार्रवाई की ? क्या अधिकारियों को, मंत्रियों को या जो घोटालेबाज हैं जिन्होंने घोटाला किया, उनपर कार्रवाई की गई ।

दूसरा कि ये 40 हजार करोड़ रुपया जो बिहार के खजाने का जो चोरी किया गया उसके रिकवरी के लिए क्या किया गया ? अब आप देखिएगा रिकवरी के लिए तो कुछ नहीं किया गया 40 हजार करोड़ गया तो गया रिकवरी नहीं किजिएगा । करना न पड़ता है महोदय । दंडित कीजिएगा तब न । अभी तो आप देखिएगा शराबबंदी चल रही है जैसे लोग

कहते हैं या शराब जब तक चालू था तो राज्य को राजस्व में 4 हजार करोड़ का फायदा होता था । चलो कोई नहीं । लेकिन शराबबंदी में तो हमलोगों ने साथ दिया था, सहयोग किए थे हमलोग । हम सबलोगों ने इसी सदन में ओथ लिया था । तो महोदय शराबबंदी, 7-निश्चय सब तो हम ही लोगों के समय में हुआ । ये बात अलग है कि हमलोगों के जाने के बाद ढिलाई हो गई । अब तो ढिलाई हो गई न । अब ढिलाई होने से क्या नुकसान हुआ महोदय शराबबंदी का एक पैरलल ब्लॉक मार्केट बन गया है महोदय । एक एकॉनमी ब्लैक एकॉनमी बन गई है महोदय पैरलल ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : तो लगभग जो 2 सौ रूपए का बिकता था दारू आज 15 सौ में बिक रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आप लोग बैठे-बैठे मत बोलिए । बैठे-बैठे मत बोलिए । आप बैठ जाइए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष, ये सदन गवाह है, मैं प्रतिपक्ष में था और मैंने प्रस्ताव किया था सबके संकल्प के लिये और सभी सदस्यों ने संकल्प लिया था शराब मुक्त बिहार का । बहुत सारे सदस्य आए हैं, इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है, चलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, मेरा यह कहने का तात्पर्य था कि अब लगभग मान लीजिए, जो 200 रुपये की चीज मिलती थी, ब्लैक मार्केट में अब जो है 1500 रुपए में मिल रही है, 1000 रुपए में मिल रही, पहले लोग जाकर खरीदते थे, अब होम डिलीवरी हो रही है, यही अंतर हो गया है, यह सच्चाई है महोदय । यह तो हमें कहना नहीं चाहिए आप बताइये वही तस्कर लोग जो थे, थानेदार को गोली मार देते हैं, क्या लॉ एंड आर्डर है? किस हिसाब से आप चला रहे है, तो इसलिए महोदय जो इक्नॉमी जो बनी है, पैरलली । इसमें तो किसी को ध्यान नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । हम किसी को यह नहीं कह रहे हैं कि जब आपने कानून बनाया लेकिन इस बजट में उप मुख्यमंत्री जी बताइये न क्या नया पढ़े हैं, टूरिज्म के लिए क्या है ? टूरिज्म के लिए कुछ किया नहीं लेकिन जी0डी0पी0 को आप बढ़ा दिये, खेलकूद के लिए कुछ किया नहीं लेकिन आप जी0डी0पी0 को बढ़ा दिये । आपने इंडस्ट्री कारखाने नहीं लगाये, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, मक्के के लिए,

सुगरकेन के लिए, लीची के लिए, मखाना के लिए जो फॉक्स नट्स कहलाता है, अमेरिका में भारी डिमांड है उसके लिए आपलोग क्या कर रहे हैं ? तो आपका जी0डी0पी0 बढ़ा कैसे? यही तो हम कहना चाह रहे हैं महोदय कि ये जितना बजट का जो भाषण था, ये असत्य के सिवाय और कुछ नहीं था और छुपाये गये सारे आंकड़े, आज जो हमने तथ्यों के साथ, जो आंकड़ों के साथ जो हमने रखा है । हम तो महोदय, चाहेंगे कि उसी आंकड़े पर बात करें, आप जो हैं 2005 में कितना कर्ज था, वह नहीं बताते हैं, 1990 में हमारे पास क्या था ? जब 1990 में आये तो गांधी मैदान गिरवी था कि नहीं था ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब बैठे-बैठे मत बोलिये । देखिये, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, बैठे-बैठे मत बोलिये । आप लोग .....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, गांधी मैदान गिरवी था ।

अध्यक्ष: वह बैठे-बैठे बोल दिये । अब आप भी खड़े हो गये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, हमारा कहने का मतलब ये बजट के आकार का जो ढिंढोरा पीटते हैं, हमारी सरकार जब थी, तब भी आठ गुना बढ़ा 1990 से 2005 । अभी भी जो है वह भी आठ गुना बढ़ा, भारत सरकार का भी देखा जाय तो आठ ही गुना बढ़ा, आपने किया क्या है ? और लोग जो हैं, मेज थपथपा रहे, थपथपा रहे, वाह! वाह! वाह! आपका तो माइनेस 2 परसेंट हो गया राजस्व का, राज्य का और हम लोग जब थे तो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होता था, कर माफ किया जाता था, जल कर माफ किया जाता था, टैरिफ, टैक्स माफ किया जाता था, पट्रोल-डीजल का टैक्स इतना नहीं था तब हम इतना आगे लेकर के चले गये तो अगर महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मूल्यांकन अगर ढंग से अगर करें तथ्यों के आधार पर, तो एक चीज हम जरूर कहना चाहते हैं कि गवर्नेन्स नाम की कोई चीज बिहार में नहीं रह गई है ।

महोदय-

''मेरे लिए फख्त आसमां है, उड़ने के लिए
मेरे पास जमीं है, साफ करके चलने के लिए ।''

अध्यक्ष: इतना अच्छा शायरी सुनाते हैं, ताली तो जोरदार बजाइये । अब थोड़ा कंक्लूड करिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, अब कंक्लूड ही कर रहे हैं, एक मिनट में हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं ।

अध्यक्ष: लेकिन कंक्लूड के साथ-साथ आपको लोग बड़े ध्यान से सुने हैं । आप भी सबको ध्यान से सुनियेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, इसलिए .....

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अबतक ध्यान से सुने हैं तो सुनिये ।

टर्न–17/मधुप/25.02.2021

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमने सारे आंकड़े, सारे तथ्य, जमीनी हकीकत, सच्चाई ईमानदारी से हमने रखा है । अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उत्तर देने में, चाहे कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, हमने प्रयास किया है कि सारे क्षेत्रों को हमलोग कवर करें ।

महोदय, बजट का मेन क्या होता है– रेवेन्यु और एक्सपेंडिचर । यही है बजट। लेकिन भारत सरकार में रेलवे का बजट पहले होता था, खतम हो गया । अब बजट में कहॉ से पैसा आया, कहॉ गया, कुछ पता ही नहीं चल पाता है । जो सच्चाई है। हमलोग तो जानना चाहेंगे, आप इन आंकड़ों के साथ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आज डबल इंजन की सरकार हैं, आप ही की सरकार केन्द्र में है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का क्या होगा ? बिहार के विशेष पैकेज का क्या होगा ? कोई भी विशेष पैकेज अगर मिला है तो आप सामने रखिये पटल पर, पता होगा सभी माननीय सदस्यों को कि बिहार को क्या विशेष पैकेज मिला । हमने तो पहले भी कहा कि लालू जी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में रेल मंत्री थे तो केन्द्र से 1 लाख 44 हजार करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया और लालू जी जब भी रेल बजट पेश करते थे, उनको तो मैनेजमेंट गुरू से नवाजा गया, हावर्ड से लेकर कई यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ने आते थे, हर बजट में किराया कम होता था, गरीब रथ जैसे ट्रेन चले ताकि गरीब भी ए0सी0 का सफर कर सके, इसके लिए गरीब रथ ट्रेन चलाया गया । बिहार को रेलवे के 4–4 कारखाने दिए गए । अभी जो भारत का बजट पेश हुआ, बिहार को क्या मिला ? हम तो चैलेन्ज करते हैं, बता दें एक कारखाना मिला हो बता दें, लालू जी ने तो 4–4 कारखाना दिया । लालू जी ने 1 लाख 44 हजार करोड़ का पैकेज दिलवाया, रेलवे का किराया घटाया । आज क्या हो रहा है ? जब आपलोग सरकार में थे, जब डेढ़–डेढ़ दर्जन मंत्री थे तो आपने सौतेला व्यवहार किया, वह भी आंकड़े हमने आपके सामने रख दिया । मानते हैं कि हमको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, हम इकोनोमिस्ट नहीं हैं, सब सब्जेक्ट्स में अच्छे थे, मैथ्स थोड़ा कमजोर था लेकिन इतने भी कमजोर नहीं थे कि इतनी साफ चीजें ना समझ में आयें और इतनी साफ चीजें, कितने दिनों से बिहार के लोगों को धूल, अंधेरे में रखा गया था । तो वही न महोदय, झूठ का बादल तो छंटेगा ही न महोदय....

अध्यक्ष : पूरा शेर पढ़िए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : शेर वह नहीं है ।

सूर्य का उजाला तो रौशन होगा ही, महोदय । इसलिए हम यह कहना चाह रहे थे कि झूठ का जो बादल इन लोगों ने बनाकर रखा है, एक प्रोपगेंडा, एक परसेप्शन, उसके लिए सूर्य की जो रोशनी होती है वह हमने कम से कम कोशिश की है कि बादल को छांट करके वह रोशनी आपलोगों के समक्ष रखें ।

अध्यक्ष : चलिए, अब हो गया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, आसन को हम धन्यवाद देते हैं, हमारी तो जिम्मेदारी है अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता हैं, लोगों की उम्मीदें रहती हैं, लोगों को तो सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है लेकिन हमको आप लोगों से बड़ी उम्मीद है, आकांक्षा है और हम लोग चाहेंगे कि जिस प्रकार से सत्र चल रहा है, सवाल-जवाब हो रहे हैं, वह होते रहना चाहिए । साथ-ही-साथ, हम यह भी चाहेंगे कि सरकार के लोग कोई चीज में कमी न रखें, जो परम्परागत तरीके से चलता रहा है, वह चलते रहना चाहिए, उत्तर माँगने से क्या होगा ? यहाँ भी लिखा हुआ है कहीं कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं ।

अध्यक्ष : सत्य है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हम तो प्रकाश डाल रहे हैं और हम इतना चाहेंगे कि सरकार कोई चीज से भागे ना, सकारात्मक बहस करे, तुलनात्मक आंकड़ों के साथ.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप धैर्य रखिए । आज नेता प्रतिपक्ष सुनेंगे आप लोगों को ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : लेकिन इधर-उधर की बात होने लगती है । हमने उसी पर पहले एक कहानी सुनाई कि आपलोग घंटी की बात करने लगते हैं ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, अब आप बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, आपको और पूरे सदन को हम धन्यवाद देते हैं, ठीक है कि टीका-टिप्पणी चलता है तो थोड़ा हाउस गरम रहता है ।

अध्यक्ष : वह लोकतंत्र की खूबसूरती है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : लोग जागे हुए रहते हैं, नहीं तो कल हमलोग चले गए तो हमने बाद में क्लिप देखा मुख्यमंत्री जी का तो बाकी सब पीछे सोये हुए हैं । हमलोग थे तो सबलोग जागे हुए थे । हमलोग तो जगाने का काम कर रहे हैं, महोदय ।

अध्यक्ष : आपके शेर ने लोगों को जगाये रखा । बैठिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, आपको धन्यवाद देते हैं और हम चाहेंगे कि सरकार उत्तर दे तो इन तथ्यों पर भी प्रकाश डाले । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी द्वारा लाये गये बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, बिहार के आय-व्ययक की जो विवरणी है, उसको ठीक प्रकार से समझने के लिए बिहार के 30 वर्षों का अध्ययन करना होगा । सन् 1974 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो क्रांति हुई और उस क्रांति से जो छात्र नेता निकलकर आए, 30 वर्षों तक कहीं न कहीं इस बिहार की राजनीति में उन्हीं का नेतृत्व रहा, उसमें 15 साल राष्ट्रीय जनता दल का और 15 साल मोटा-मोटी एन0डी0ए0 का और इस दो हिस्से में बाँटकर बिहार के विकास को और बजट को देखना होगा । महोदय, जब 2005 से पहले के बिहार को हम देखते हैं तो बिहार में न कहीं सड़क थी, न कहीं पुल था और केवल उड़नखटोला से लोग घूमते थे और आज 5 घंटे में, 6 घंटे में, 4 घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना राजधानी पहुंचा जा सकता है । यह हुआ है इस 15 साल में और इस 15 साल के पहले, माननीय नेता प्रतिपक्ष बहुत सारे आंकड़ों में उलझा रहे थे, कभी वे आजादी के पहले का आंकड़ा लेते थे और कभी 2005 के आंकड़ा को ले आते थे, 2004 के आंकड़ा को लाते थे, अगर तुलना करना है तो पूरा-पूरी 15 साल आर0जे0डी0 के शासन और 15 साल जो एन0डी0ए0 का शासन हुआ, उसकी तुलना कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी इस बजट में आपको दिखेगा लेकिन देखने के लिए हिम्मत चाहिए । देखने के लिए आपको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा अपने-आप का और अपने को भी ठीक प्रकार से आईना दिखाना होगा और आईने में देखना होगा ।

महोदय, जो बजट शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वह फ्रेंच भाषा के बुजेट से हुई है जिस समय उसको चमड़े का एक थैला होता था उसको जब खोलकर रखा गया तो बजट उसी को कहा जाने लगा मोटे तौर पर जो पहले हमलोगों का आय-व्ययक का विवरणी होता था । बजट शब्द वहीं से प्रचलन में आया । इसके पीछे एक रोचक किस्सा है, महोदय । इंगलैंड के पूर्व वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल से जुड़ा है, 1773 ई0 का है, ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित कागजात सदन के सामने पेश करने के लिए एक चमड़े का थैला खोला था । कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल का कि बजट खुल गया, नाम की एक पुस्तिका भी प्रकाशित हुई, बस उसी समय से सरकार के वार्षिक आय-व्ययक के विवरणी के लिए बजट शब्द का

प्रयोग शुरू हुआ । धीरे-धीरे यह शब्द ब्रिटेन के सभी उप निवेश में फैला । आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का पहला केन्द्रीय बजट 26 नवम्बर, 1947 को भूतपूर्व वित्त मंत्री आर0के0 शन्मुखम शेट्टी की तरफ से पेश किया गया था । संविधान लागू होने के बाद 28 फरवरी, 1950 को पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था ।

(व्यवधान)

टर्न-18/अभिनीत/अंजली/25.02.2021

(व्यवधान)

श्री अरूण शंकर प्रसाद: मैं बजट पर ही आ रहा हूँ, धीरज रखिए । आदरणीय तारकिशोर जी द्वारा जो बजट लाया गया है उसकी कई मुख्य बातें हैं । 2,18,303 करोड़ का यह बजट है । महोदय, 2004-05 में राष्ट्रीय जनता दल का अंतिम बजट आया था और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीया श्रीमती राबड़ी देवी जी ने उस बजट को पेश करते हुए 3490 करोड़ का बजट पेश किया था । आज जब हम इस सदन में खड़े हैं और 2021-22 का जो बजट पेश हो रहा है, 2 लाख 18 हजार करोड़ का बजट पेश हो रहा है, कोई तुलना नहीं है । उस समय राबड़ी जी ने विद्युत पर, विद्युत की बहुत चर्चा हो रही थी, मात्र 300 करोड़ रूपये खर्च का प्रावधान किया था । सिंचाई, कृषि, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण विकास सबको मिलाकर मात्र 1984 करोड़ रूपये का बजट था और आज कितना है यह भी नेता प्रतिपक्ष को देखना चाहिए । उस समय जो बजट हुआ, महोदय गिलोटीन में होता था, कभी तो पूरा बजट भी नहीं आता था, जिसको लेकर ये आज चर्चा कर रहे थे । 2004-05 का बजट देखेंगे तो वह गिलोटीन में था, सारा अनुदान मांग एक साथ गिलोटीन में पास हुआ था और आज संपूर्ण बजट आना शुरू हुआ है । महोदय, इतना ही नहीं बल्कि समय-समय पर अलग-अलग प्रकार के बजट भी इस बिहार में आते रहे हैं । जो प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है इस बजट में कि उच्च शिक्षा के लिए इंटर पास महिलाओं को 25 हजार, ग्रेजुएट पास महिलाओं को 50 हजार तथा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण देगी सरकार, इसका इस बजट में प्रावधान है ।

महोदय, सभी गांवों में, गांव के विकास पर, जब तक गांव, गरीब और किसान का विकास नहीं होगा तब तक इस बिहार का भला नहीं होगा और इसलिए हर गांव को रोशनी से जगमगाने के लिए सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का इस बजट में ऐलान किया गया है । ग्रामीण इलाकों में लिंक रोड के निर्माण के लिए 250 करोड़ रूपये दिए गये

हैं और लिंक रोड जितने हैं इससे उसका काम पूरा किया जायेगा । आज बिहार की सरकार 250 आबादी तक के बसावटों को वन साईड कनेक्टिविटी देने का काम की है जो आजतक नहीं हुआ था, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक हजार तक की आबादी को कनेक्टिविटी देने का काम किया और जब आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने 500 आबादी वाले बसावटों को मुख्य सड़क से, बारहमासी सड़क से जोड़ने का काम किया । आज 250 आबादी तक हम पहुंच गये हैं और शायद ही कोई गांव छूटा हुआ है, ऐसा कोई बसावट 100 परिवार से अधिक का जिसके पास सड़क नहीं है, छूट गया हो यह विरले ही खोजने से मिलेगा । हमारे बजट का विकास यहां तक गया है, बजट की रोशनी वहां तक गयी है, इस परिप्रेक्ष्य में हमारे बजट को देखना चाहिये । वर्ष 2005 तक वृद्धाश्रम का विषय कभी होता नहीं था उस विषय को भी निकालकर लाया गया है । मानव सूचकांक कैसे बढ़ेगा यह एक महत्वपूर्ण विषय होता है देश और दुनिया के सामने । केवल पैसे होने से नहीं होता है हमारा मानव सूचकांक भी बढ़ना चाहिये और मानव सूचकांक तभी बढ़ता है जब सभी विषयों पर समीचीन रूप से काम होता है । महोदय, वृद्धाश्रम के लिए 90 करोड़ रूपये का आवंटन इसमें किया गया है । ऐसी माताएं, ऐसी महिलाएं जो आज अनाथ हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है उनको भी देखने के लिए नीतीश कुमार, तारकिशोर जी और रेणु जी की सरकार ने बिहार के अंदर उनकी देख-रेख करने की जिम्मेवारी भी अपने कंधों पर उठाया है । सरकार ने स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 1,15,116 एप्लीकेशन स्वीकृत किये हैं, जिनको ऋण देने का प्रावधान है । बजट में पशुपालन, पहले कहीं वैक्सिन नहीं रहता था, हमने भी 1990 से कार्यकाल देखा है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, गांव, गली-गलियारों को हमने भी देखा है । पशुपालन को तो छोड़ दीजिए, मनुष्य के जो अस्पताल होते थे उसमें भी पशु के अलावे कोई आदमी नहीं दिखता था । पशुपालन की बात को तो जाने दीजिए, आज पशुपालन में और मछली पालन में बिहार कहां खड़ा है जरा आंकड़ा निकाल कर के देख लीजिए कि हम कितने आगे बढ़े हैं । हमलोग मिथिला के लिए हुजूर कहते थे कि-

''पग-पग पोखर माछ मखान,
शरस बोल मुस्की मुख पान ।
विद्या वैभव शांतिक प्रतीक,
हम वही मिथिलाक वासी छिक ।''

ललित नगरी मिथिला में आज फिर से माछ, पान, मखान और शहद की खेती को उन्नत किया जा रहा है । महोदय, उस मिथिलांचल को एक बार फिर से वह अवसर मिला है कि वह विकास करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है । महोदय, मिथिलांचल के लिए इस बजट में प्रावधन किया गया है । महोदय, राजगीर में, इतना ही नहीं खेल की दुनिया में बिहार फिसड्डी राज्य हुआ करता था 2005 तक और आज खेल की दुनिया में भी...

अध्यक्ष: अब बैठ जाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, दो मिनट मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । मैं जानता हूं काफी समय चला गया है । राजगीर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जायगी, इसका भी इस बजट में प्रावधान किया गया है । राज्य में नये इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 110 करोड़ रुपये दिये गये हैं । राज्य में तीन नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं । इस कारोबारी साल में 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा, इसके लिए 200 करोड़ रुपये दिये जायेंगे । महोदय, इधर-उधर की कोई ऐसी बात नहीं है, उद्यमिता का विकास किया जायेगा । महोदय, हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों में पांच सौ करोड़ रुपये दिये जायेंगे और बेसहारा लोगों के लिए बहुमंजिला भवन बनाया जायेगा...

अध्यक्ष: अब बैठ जाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: महोदय, मैं बस एक मिनट और आपसे चाहूंगा । महोदय, मैं चंद बातें कहकर समाप्त करूंगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष अल्पसंख्यकों की बात कह रहे थे, अतिपिछड़ों की बात, पिछड़ों की बात, दलितों की बात तो महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बजट के हर प्रावधन में अल्पसंख्यक लाभान्वित होगा । कृषि के लिए काम होगा बजट में क्या वहां अल्पसंख्यक नहीं है क्या....

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: वहां अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं क्या ? महोदय, अंत में मैं बताना चाहता हूं कि राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वह 50,735 रुपये का है जो 10.5 परसेंट का ग्रोथ रेट है और राष्ट्रीय औसत 4.2 फीसदी है । महोदय इस प्रकार से बिहार ने तरक्की किया है । महोदय और अंत में...

अध्यक्ष: कुछ गुनगुनाइयेगा अंत में । बैठ जाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: एक शायरी कहकर मैं खत्म करता हूं । महोदय, बहुत शायरी हो रही थी ।

''नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं'' ।

इसलिए महोदय, विपक्ष को भी अपनी निगाह और नजर को बदलने की जरूरत है ।

अध्यक्षः चलिये ठीक है । श्री राजेश कुमार । गागर में सागर भरना है कुछ लास्ट में गुनगुनाना है तो आप भी गुनगुना दीजियेगा । इससे सकारात्मक माहौल बनता है ।

श्री राजेश कुमारः सम्मानित सभाध्यक्ष जी, आज इस बजट के शुरुआत में मैं यह कहूंगा कि यह बजट से, कोरोना काल था और सरकार से एक जनप्रतिनिधि के नाते और एक जनता के नाते दोनों अपेक्षाएं हमलोगों की थीं कि कोरोना काल में बजट सरकार ऐसा लायेगी, जो प्रवासी मजदूर हमारे बिहार के भाई जो दूसरे जगह कामकाज के लिए गए थे, लगभग 35 लाख हैं, बाहर जो काम करते थे अन्य राज्य में वह वापस आयें और बजट देखकर, जब माननीय वित्त मंत्री जी का बजट अभिभाषण चल रहा था बड़ी ही चेष्टा और बहुत ही संजीदगी से मैं देख रहा था ।

...क्रमशः...

टर्न–19/आजाद/24.02.2021

..... क्रमशः .....

श्री राजेश कुमार : जो संदर्भ था, जो आशा थी, जो आकांक्षा थी जनता की और हमारी जो आकांक्षा थी, उस आकांक्षा पर सरकार खड़ी नहीं उतरी । 2020 के बजट के प्रावधान में जो आंकड़ा है, सरकार द्वारा कहा गया कि अब तक जितने भी बजट पेश किये गये हैं, उस बजट से यह बहुत बड़े बजट का आकार हैं । मसलन जो 2020–21 का बजट था 2,11,761 करोड़, जो 2021–22 के बजट में 2,18,303 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 यदि हम आंकड़ा को घटायेंगे तो इसमें मात्र 6,542 करोड़ रू0 का इजाफा बजट में हुआ है और यहां हमलोग, सरकार के लोग, सरकारी पक्ष तालियां ठोक रहे हैं, मेज थपथपा रहे हैं । अन्त में, मैं यही कहूंगा बजट के संदर्भ में कि यह वैसा ही लगा जैसे पानी बीच मथानी मारी । पानी बीच मथानी मारने से इसमें क्रीम नहीं निकलता है, पानी में क्रीम नहीं होता है इसलिए यह बजट जो है, स्पष्ट रूप से पानी बीच मथानी मारने जैसा है ।

आप जानते हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से हमारे लोग अपने रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं और आप एक ऐप के माध्यम से, आपने एक ऐप लाया और यह हो सकता है कि सरकार की यह अच्छी सोच हो और अच्छी पहल हो और आपने सारे पदाधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर के आपने राज्यों में डिप्युट किया, बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत ही निराशा भरी आशा से, मैं बोल रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय कि उस राज्य में जो भी कोऑडिनेटर नियुक्त किये गये हैं पदाधिकारी, एक भी कोऑडिनेटर का फोन नहीं लगता था और हमलोगों के पास जो प्रवासी मजदूर थे, वे

बार-बार फोन करते थे, हमलोग भी नम्बर शेयर करते थे लेकिन उधर से दोबारा जो फंसे हुए दिहाड़ी मजदूर फोन करते थे कि फोन नहीं लग रहा है सर । ऐप का भी करीब-करीब वही हाल था, कहने का तात्पर्य महोदय, स्पष्ट है । अध्यक्ष महोदय, इसमें बजट के प्रावधानों में प्रवासी मजदूर जो राज्य में लौटे हैं, आये हैं उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । हम जानते हैं कि सरकार का कई बार वक्तव्य आया कि हम आर0डब्लू0डी0 में, जो काम हम कोविड लॉकडाऊन के बाद शुरू करेंगे तो इसमें आर0डब्लू0डी0 में उन प्रवासी मजदूरों को काम देंगे । हम जो है, मनरेगा में काम देंगे । बहुत ही खेद और निराशाजनक रहा कि आज तक यह आंकड़ा सरकार के द्वारा पेश करना चाहिए था कि लॉकडाऊन के बाद हम कितने प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके, उनको काम दिया है और आर0डब्लू0डी0 में कितना काम दिया है । दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इसे मनरेगा के कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए लेकिन इस बजट के अभिभाषण में कोई भी प्रावधान नहीं है कि हम इस हिसाब से करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, लाल बत्ती जल गयी है, इसलिए हम जो है, दो-चार मिनट आपका समय लेंगे क्योंकि जो मुख्य बात है, अपने शिड्यूल के हिसाब से कहकर के रख दूँगा .....

अध्यक्ष : आप एक मिनट के अन्दर समाप्त करें ।

श्री राजेश कुमार : अन्त में यह जरूर कहूंगा कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकार बहुत चिन्ता करती है लेकिन सरकार यदि चिन्ता करती है तो हम कुछ आंकड़े को, जो सदन में रखा गया, उस आंकड़े को मैं रखना चाहता हूँ, यह हमारा आंकड़ा नहीं है....

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए, श्री मनोज मंजिल ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, कुल जो वर्ष 2015 में दलितों के मामले में जो अत्याचार 10228, 2016 में.

अध्यक्ष : श्री मनोज मंजिल ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, 2017 में 11028 हुए हैं, 2018 में 12514 हुए हैं, जुलाई, 2019 में अब जो है.....

अध्यक्ष : आप शुरू कीजिए, आपका समय 5-6 मिनट ही है । राजेश जी, आप बैठ जाइए, शुरू कीजिए ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, यह बिहार के नौजवानों के सपनों को तोड़ने वाला बजट है । 19 लाख रोजगार के बारे में इसमें कहीं कोई बात नहीं है । आप जानते हैं कि आजकल रेलवे बेची जा रही हैं, बैंक, एल0आई0सी0 का निजीकरण हो रहा है, हवाईअड्डों, बन्दरगाहों को बेचा जा रहा है । XXX

ऐसे समय में बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर कम हुए हैं और तब नाईन्थ और टेन्थ क्लास के, प्लस टू क्लास की स्टेट द्वारा जो परीक्षा ली गयी है, 37335 अभ्यर्थियों का अभी तक रिजल्ट सरकार ने जारी नहीं किया है । प्रारंभिक शिक्षकों के 94700 हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है और 30020 माध्यमिक शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है । इस तरीके से 437310 बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं । 60 प्रतिशत असिसटेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं । 61 प्रतिशत डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं । 66 प्रतिशत इंजीनियरों के पद खाली पड़े हैं । आधा ब्लॉक खाली है । एक-एक कर्मचारी पॉच-पॉच पंचायतों को देख रहा है । पुलिसकर्मियों के 60 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और रोजगार के नाम पर लोन की बात इस बजट में की गई है । रोजगार के पहले ही बिहार के नौजवान कर्जदार हो जायेंगे । महोदय, इसलिए जिस तरीके से देश में किसानों ने आत्महत्या किया है कर्ज में फंसकर के, उसी दिशा में बिहार के नौजवानों को धकेला जा रहा है । इसीलिए लोन, ठेका मानदेय हमारे लिए यह 19 लाख रोजगार का मतलब नहीं है ।

हमारे लिए रोजगार का मतलब 19 लाख सरकारी नौकरी से है और इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने नारा दिया था कि ''नीतीश कुमार नये बिहार '' लेकिन हम कहना चाहते हैं कि नये बिहार का तीन आधार है, महोदय यह सरकार न समझे कि एक सी0एम0 और दो डिप्टी सी0एम0 .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त होने जा रहा है ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, तीन आधार का मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार.....

अध्यक्ष : गागर में सागर भरिए, आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री मनोज मंजिल : इसलिए बिहार में 7 घंटी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, बिहार में शिक्षक नहीं हैं । सरकार कहती है कि कुछ किताब ले लो, खिचड़ी खा लो, पैसे ले लो, साईकिल ले लो, लेकिन शिक्षा मत लो .....

अध्यक्ष : चलिए, हो गया बैठिए ।

श्री मनोज मंजिल : इसीलिए शिक्षा के निजीकरण की दिशा में एक बार फिर से बिहार के मजदूर, किसान, दलितों, गरीबों, खेत-खलिहान के संतानों से शिक्षा को छिनने की साजिश है और भारतीय संविधान का उल्लंघन है । बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर के सपनों के खिलाफ यह सरकार काम कर रही है । इससे शिक्षा रोजगार नहीं देकर के यह सरकार गरीब दलित, अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करना चाहती है और सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती है ....

अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, आज सदन में शायरी कहने का मौका मिल रहा है .....

अध्यक्ष : इसको तो पहले ही कहना चाहिए था न । अब आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान ।

( व्यवधान )

बोलिये, माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान जी, आपका 2 ही मिनट समय है ।

टर्न-20/यानपति-धिरेन्द्र/25.02.2021

श्री अखतरूल ईमानः अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार सरकार द्वारा पेश वर्ष 2021-22 के बजट पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः प्रोसिडिंग में ऐसे कोई भी शब्द नहीं जायेंगे । अभी नये सदस्य हैं, आप बैठ जाइये । उनका दो मिनट समय है ।

---

XXX - आसन के आदेशानुसार इस अंश को विलोपित किया गया ।

---

श्री अखतरूल ईमानः महोदय, 2 लाख 18 हजार करोड़ का बजट बिहार की जनता के खून-पसीने और गाढ़े कमाई का हिस्सा है और इसको उनके हक में खर्च किया जाना चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है । मैं समझता हूँ कि इस बजट को पेश करते वक्त समाज के सबसे दबे और कुचले कोरोना से मुतासिर उन मजदूरों को, कोरोना काल में हमें बिहार के मजदूरों की असल हालत को देखने का मौका मिला । बाहर से वापसी पर उनकी कोई शुद्ध लेने वाला नहीं था और उनके परिवार को बहुत परेशान होना पड़ा । इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान किया जाता कि आईन्दा कभी इस तरह की कोई महामारी हो तो इन गरीबों को इतना परेशान न होना पड़े, उसकी कोई झलक नहीं मिली है । मौका हो तो उसके बारे में सोचना चाहिए। बजट के साथ हमेशा दावा किया गया है कि इंसाफ के साथ तरक्की । यकीनन है कि अगर इंसाफ के साथ तरक्की की बात कोई भी करता है तो ऐसे लोगों को मुबारकबाद देना चाहिए। सीमांचल का वह हिस्सा जिसके बारे में बहुत सारे रिपोर्ट और आंकड़े बताते हैं कि वह हिस्सा अतिपिछड़ा रह गया है । उसके लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की तकदीर बदलने के लिये, मरकज से अगर विशेष राज्य के दर्जे की प्राप्ति का हक मांगते हैं तो सीमांचल के लोगों का भी हक है कि उनको इसका

हिस्सा दिया जाय । जनाबेआली, मेरा वक्त 3 मिनट का है, आपने दिया है और सब पर कर्म किये हैं, मुझ पर भी कर्म कीजियेगा । मैं यह कह रहा हूँ कि सीमांचल को अगर आप उठाना चाहते हैं और सीमांचल के बगैर बिहार की तरक्की नहीं हो सकती । महोदय, तो बिहार के विशेष राज्य की लड़ाई भी लड़नी चाहिए और सीमांचल को हक भी देना चाहिए। कटाव से ग्रस्त है, स्कूलों की कमी है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए । महामहिम तालिम और रोजगार के सिलसिले में बहुत सारे मवाके नहीं हैं, हर चंद के, इसमें एजुकेशन के बजट का आकार बहुत बड़ा है । मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री, इस वक्त टीचरों की बहाली पर तवज्जो देंगे । उर्दू के जो टी0ई0टी0 पास किये हैं, उनकी बहाली होगी । टी0ई0टी0 वाले टीचारों की बहाली के रास्ते को नहीं रोका जायेगा । तालिमी मरकज के टीचरों को हटाने के सिलसिले में अदालत में पेश किये गये अपने मुकदमात को वापस लेने की सरकार कोशिश करेगी । उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी जबान की हैसियत दी गई है और उर्दू के कोटे में पैसा नहीं बढ़ा है, उर्दू को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, यह सरकारी जिम्मेदारी है । अकलियतों की हालत सबसे खराब है और अकलियतों की हालत को बेहतर बनाने के लिये उनके बच्चों को कर्ज, उनके बस्तियों में स्कूल का कोई प्रोग्राम नहीं है । महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से गुजारिश करूंगा कि सरकार इन मामलातों पर तबज्जो दे। हम सिर्फ तनकीब नहीं करना चाहते, हम सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि बिहार का विकास सीमांचल के बगैर नहीं होगा और सीमांचल बिहार के हिस्से का 10वां हिस्सा है, मोहतरम । अगर कुछ भी हमारे साथ मुरव्वत मत कीजिये । तो टैक्स में 10वां हिस्सा हमारा होता है, उसी को दे दीजिये । आपने दावा किया है इंसाफ का, हम आपसे भीख नहीं, इंसाफ मांगते हैं, भीख मुझे मत दीजिये, मेरा हक दे दीजिये । दावा अगर इंसाफ का किया है तो मेरे साथ इंसाफ कर दीजिये । बहुत-बहुत शुक्रिया ।

अध्यक्षः बैठ जाइये । श्रीमती ज्योति देवी ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । वर्ष 2021-22 के आय-व्यय पर सामान्य विमर्श हेतु अपनी बातों को रखने का समय दिया । इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । साथ ही, हमारे माननीय नेता, श्री जीतन राम मांझी जी को भी आभार है कि इस विषय पर हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेकुलर) के प्रतिनिधि के तौर पर मुझे बोलने का समय दिया गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही हमारी सरकार के विकास का एक ऐसा पैमाना है, जो दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस किया जाता है । श्री नीतीश कुमार जी के दृढ़संकल्प का ही असर है कि मैं जिस क्षेत्र बाराचट्टी से आती हूँ । वर्ष 2005 तक वहां की स्थिति ऐसी थी कि शाम में तो छोड़ दीजिये, दिन में

भी लोगों को घर से निकलने में डर लगता था लेकिन आज एक समय ऐसा भी आया है, जब उस क्षेत्र की प्रतिनिधि 4 घंटे में बाराचट्टी जैसे सुदूर इलाके से विधान सभा पहुँच कर वित्तीय मामले पर अपनी बातों को रख रही हूँ । दलित टोलों में जाकर सिर्फ दलित बच्चों का बाल काट देने से, उनका विकास नहीं हो जाता । विकास के लिये यह जरूरी है कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाय, रोजगार की समस्या का समाधान किया जाय, खेत-खलिहानों में पानी की व्यवस्था की जाय । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 का बिहार और वर्ष 2021 के बिहार में अंतर साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा । वित्तीय वर्ष 2005-06 में, बिहार की योजना का आकार 4,379 करोड़ रुपया था जो आज कई गुनी बढ़ गयी है । बिहार में सिर्फ योजना का आकार ही नहीं बढ़ा बल्कि कुल बजट में योजना का खर्च भी बढ़ा है ।

अध्यक्ष: अब शांति से सुनिये । अच्छी-अच्छी बातें बोल रही हैं, सुनिये ।

श्रीमती ज्योति देवी: अब मुझे बताना है कि राज्य में नये निर्माण कार्य पर कुल बजट का अधिक खर्च किया जा रहा है, यह विकास की जरूरत भी है । वर्ष 2005-06 में कुल बजट का 31.71 फीसदी राशि योजना मद में रखी गयी थी, जो इस बार कई फीसदी बढ़ा दी गयी है । महोदय, चुनाव के वक्त कुछ लोग बेरोजगार-रोजगार को मुद्दा बना रहे थे, वे लोग भूल गये कि वर्ष 2005 के पहले, बिहार की स्थिति क्या थी ? पलायन दर कितना था ? हम बिहारियों की स्थिति दूसरे राज्यों में क्या थी ? बिहारी एक गाली शब्द बनकर रह गया था । अब स्थिति बदल गयी है, हमारी सरकार ने यह तय किया है कि इस बार 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, साथ ही महिलाओं, पशुधन, कृषि और उद्योगों को आत्मनिर्भर बनायेंगे ।

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्रीमती ज्योति देवी: अध्यक्ष महोदय, 2,18,303 करोड़ रुपये का बजट, बिहार में विकास को नयी गति देगा । कोरोना काल में राज्य ने काफी मुश्किलों का सामना किया है लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने जनता पर कोई नई टैक्स नहीं लगायी । फिर भी, हम बजट के आकार को बढ़ाकर राज्य के विकास के लिए तत्पर हैं । इस वर्ष हमारी सरकार योजना मद में 1 लाख 51 हजार 881 करोड़ रुपये खर्च करेगी ।

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्रीमती ज्योति देवी: कान खोलकर सुन लें, हल्ला करनेवाले लोग, आपका योजना आकार था और आज खुशहाली योजना का आकार है । यहां एक परिवार नहीं, हर गरीब परिवार की चिंता होती है । कुछ लोग इस फिराक में हैं कि बिहार को फिर उसी जंगलराज की तरफ ले जाना है लेकिन जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जैसे जन-जन के नेता होंगे, वहां

जंगलराज कैसे आयेगा । अब देखिये, किसानों के नाम पर नौटंकी चल रही है और हमलोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि पंचायत स्तर पर पशु अस्पताल की स्थापना होगी, हर घर पहुंचकर चिकित्सा....

अध्यक्ष: अब माननीय सदस्या बैठ जायं ।

श्रीमती ज्योति देवी: अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा । महिला हैं, महिला को थोड़ा ज्यादा समय दिया जाय, सर ।

घर पहुँचकर इलाज करेगी । देशी गायों के संरक्षण के लिये गौवंश अस्पताल की स्थापना की जायेगी, इन योजनाओं के लिए 5 सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । अध्यक्ष महोदय, गांवों के विकास का आधार पशु एवं कृषि ही है । बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि गांव बिना गरीब के विकास के, देश का विकास संभव नहीं है । इसलिए ग्रामीणों और किसानों की आय में बढ़ोतरी हेतु आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर गौ पालन, मछली पालन का विकास किया जायेगा । महोदय, हमारा एक सपना भी है कि देश के हर राज्यों में बिहार की मछलियां जायं, हर खेत को पानी पहुंचाये....

अध्यक्ष: चलिये बहुत अच्छा, बैठिये ।

श्रीमती ज्योति देवी: इसके लिये पांच सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे किसान भाइयों को कोई समस्या न हो । इससे भी कुछ लोगों का पेट दर्द होगा ।

अध्यक्ष: श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

अब आप बैठ जाइये । आप बैठ जायं, बैठ जायं ।

श्रीमती ज्योति देवी: सर, थोड़ा-सा । बिहार के विकास के लिये....

अध्यक्ष: आपका समय महिला को ही दे रहे हैं ।

श्रीमती ज्योति देवी: सर, कुछ सुझाव है ।

अध्यक्ष: अब समाप्त करें । सदन पटल पर रख दीजिए ।

श्रीमती ज्योति देवी: अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा सुन लीजिए । राज्य के विकास को और गति देने के लिए, मेरे कुछ निम्न सुझाव हैं । मगध में, जिस प्रकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह फिल्म उद्योग को भी प्रोत्साहित किया जाय ताकि हजारों युवाओं को अपनी कला और प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: सारा आपका लिखा हुआ, पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा, रख दीजिये अब ।

श्रीमती ज्योति देवी: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

अध्यक्ष: श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

श्रीमती स्वर्णा सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े हर्ष के साथ कहना चाहूंगी कि माननीय उपमुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री महोदय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें राज्य के सभी लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है । सुशासन के अगले पांच वर्षों के लिये, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 योजना को शुरू किया गया है, इसके लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 4671 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । महोदय, शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिये एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय, एक चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिये राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय खोलने का सत्ताहासीन निर्णय लिया गया है जोकि पूरे क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लायेगा । श्रीमान्, 'सशक्त महिला, सक्षम महिला' के उत्थान हेतु बिहार सरकार ने रोजगार में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है । उद्योग स्थापित करनेवाली महिलाओं को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम पांच लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण पर देने का भी प्रावधान किया गया है । इससे हमारी बहनों को अपने पैरों पर खड़े होने एवं आत्मनिर्भर होने में बहुत बल मिलेगा ।

क्रमशः

टर्न-21/शंभु/25.02.21

श्रीमती स्वर्णा सिंह : (क्रमशः) महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं और इसके लिए किसानों की आय दुगुनी करने के उद्देश्य से हर संभव माध्यम से हर खेत पर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है । इसके लिए बजट में कुल 550 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिससे सभी किसान खुशहाल होंगे । महोदय, सभी गांव की गलियों एवं सड़कों पर सोलर लाइट लगायी जायेगी जिससे सभी गलियों एवं सड़क अनवरत प्रकाशमय रहेगी । महोदय, मछली पालन, मुर्गी पालन एवं दुग्ध उत्पादन जैसे व्यवसाय करनेवालों के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बजट में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिससे रोजगार के माध्यम से अत्यधिक लोगों को लाभ होगा । श्रीमान् शहर में जल-जमाव की समस्या को दूर करने एवं सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत् शवदाह गृह एवं मोक्षधाम का निर्माण किया जायेगा । प्रत्येक शहर में वृद्धजनों के लिए वृद्धगृह बनाने की योजना है जिसमें वृद्ध लोग आनन्दपूर्वक रहेंगे । महोदय, हर गांव में मुख्य सड़क, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय एवं महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ने हेतु नयी सड़कों का निर्माण कराया जायेगा । सरकार की और महत्वाकांक्षी योजना है कि राज्य से किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना आया जा सके ।

महोदय, मानव समुदाय अपने समुचित इलाज हेतु टेली मेडिसीन, लोकल कॉल सेंटर और फोन करके अथवा मोबाइल ऐप द्वारा...

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : महोदय, अंत में दो मिनट । अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि बिहार की खुशहाली एवं बेहतर समाज के लिए आप खुद बदलिये इससे समाज बदलेगा और बिहार खुशहाल होगा । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री सत्येन्द्र यादव, एक मिनट का समय है, गागर में सागर, एक मिनट में भरिये ।

श्री सत्येन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार के वित्त मंत्री ने वर्ष-2021-22 का जो बजट प्रस्तुत किया है 2 लाख 18 हजार 303 करोड़ का उस बजट को पढ़ने और निष्कर्ष पर पहुंचने पर यह महसूस होता है कि बजट आंकड़े और शब्दों के आकर्षक प्रस्तुति के सिवाय कुछ नहीं है । बल्कि बजट के अंदर, बिहार की जनता के समक्ष जो खड़ी चुनौती है उस चुनौती से निपटने के लिए बजट बनाया जाता है । आज बिहार के अंदर गंभीर चुनौती है कृषि और रोजगार का । कृषि के अंदर लागत खर्च रोज बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बीज के दाम बढ़े हैं, उर्वरक के दाम बढ़े हैं । खेती अब घाटे के सौदा हो गयी है, किसान खेती से जो लाभकारी मूल्य हासिल करना चाहता है वह लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं मिल रहे हैं । आज खेती दम तोड़ रही है, बजट खेती पर खामोश है, कृषि की तरक्की पर खामोश है । वहीं दूसरी तरफ उद्योग पर जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गयी है बिहार के अंदर कोई उद्योग खड़ा करने का बजट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है, कोई दिशा निदेश नहीं है । बिहार में सबलोग जानते हैं कि यहां पढ़ने लिखने वाले सबसे ज्यादा युवा हैं, वे कोटा के अंदर भी जाकर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, इलाहाबाद, दिल्ली और पटना के अंदर करोड़ों नौजवान सरकारी सर्विसेज के लिए तैयारी करता है, लेकिन बिहार के अंदर सरकारी सर्विसेज का कोई स्थान नहीं है, उसके लिए कोई संभावना नहीं है । बिहार के अंदर जो चुनौती है वह रोजगार का और यह रोजगार तब मिलेगा जब कृषि के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये ।

श्री सत्येन्द्र यादव : यह रोजगार तब मिलेगा जब बिहार के अंदर कल-कारखाने लगेंगे ।

अध्यक्ष : अब सत्येन्द्र जी, आप बैठ जाइये, दो मिनट से ज्यादा हो गये, तीन मिनट हो गये ।

श्री सत्येन्द्र यादव : लेकिन बिहार की सरकार द्वारा जो दावा किया गया है मैं साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि बिहार आत्मनिर्भर बिहार नहीं और अन्याय के साथ लूट का बजट है और बिहार लकवाग्रस्त हो जायेगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर जो चुनौती है उस

चुनौती का मुकाबला करने के लिए कृषि में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उद्योग को दुरुस्त करने की जरूरत है ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये । श्री सुर्यकान्त पासवान, प्रारंभ करें । एक मिनट का समय आपका भी है।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उससे काफी उम्मीद थी, लेकिन हम तमाम बिहारवासियों, हमारी समस्याओं के निदान और अवाम के सपनों को पूरा करने की बात करेंगे । मगर यह बजट हम 12 करोड़ बिहार वासियों के साथ महज एक मजाक है । महोदय, शिक्षा राज्य के विकास का मूल तत्व है, मगर हमारे राज्य में शिक्षा की हालत ऐसी है कि स्कूल तो हैं मगर उन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं । महोदय, मूल संसाधन का घोर अभाव है । प्रतियोगिता परीक्षाओं की हालत ऐसी है कि परीक्षा होने से पहले ही प्रश्न लीक हो जाता है । एन0आइ0आर0एफ0 की 2020 की रैंकिंग में देश के 100 टॉप विश्वविद्यालयों में बिहार का विश्वविद्यालय शामिल नहीं है । महोदय, बिहार के सरकारी स्कूलों में देशभर की तुलना में सबसे अधिक पद रिक्त हैं । यहां 6 लाख 88 हजार 157 पद के विरूद्ध 2 लाख 77 हजार 255 पद खाली हैं ।

अध्यक्ष : भाषण संक्षिप्त करें ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, अपराध का ग्राफ बिहार के अंदर बढ़ता जा रहा है । महोदय, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं । बेगुसराय जिला के अंदर बिशनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया की हत्या बीते दिनों हो गयी, लेकिन आज तक पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने में विफल रही । महोदय, शराब बन्दी के नाम पर सरकार ने अच्छा कदम उठाया था, स्वागत योग्य था, लेकिन आज बिहार के अंदर शराब होम डिलीवरी हो रहा है ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, स्वास्थ्य का हाल जानिए, जर्जर पी0एच0सी0, सदर अस्पतालों में डाक्टर, उपस्कर और दवाओं का घोर अभाव है । महोदय, राज्य के अनुमंडल अस्पतालों में पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण मृत शरीर को 50 से 70 कि0मी0 दूर ले जाना पड़ता है । महोदय, रोजगार की बात करें तो....

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये । श्री हरिभूषण ठाकुर प्रारंभ करें ।

श्री हरिभूषण ठाकुर : हुजूर, आज जो आय-व्यय की व्यवस्था है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये माननीय सदस्य ।

श्री हरिभूषण ठाकुर : हुजूर, बजट पर जो मेरी पार्टी ने और आपने...

अध्यक्ष : लिखा हुआ आप सदन पटल पर रख दें ।

श्री हरिभूषण ठाकुर : इस धरती से विश्व के सबसे बड़े जो अर्थशास्त्री थे, मुझे बोलने का जो मौका दिया है मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ । अभी नेता प्रतिपक्ष ने एक कहानी कहा है । मैं भी अपनी बात कहानी से शुरू करता हूँ । एक किसान घोड़ा बेचने जा रहा था तो रास्ते में उसको एक चोर मिल गया और किसान से चोर ठग लिया घोड़ा, मेला में पहुंचा और चोर तो हावभाव से ही बुझा जाता है । घोड़ा का दाम था 2 रूपया कहता था 20 रूपया । एक सरदार चोर था वह हुक्का पीकर देख रहा था वह कहा कि भाई यह घोड़ा कितना में बेचोगे? उसने कहा ठीक है थोड़ा चाल देखते हैं घोड़ा का तो वह घोड़ा पर बैठा और हाथ में हुक्का था और कुछ दूर चला तो कहा कि भाई हुक्का रखो हम घोड़े का लगाम दोनों हाथ से पकड़ेंगे और वह घोड़ा लेकर भाग गया । कुछ देर के बाद वह मेला में हुक्का लेकर घूम रहा था तो किसी ने पूछा कि घोड़ा बिका तुम्हारा तो उसने कहा कि बिक गया तो पूछा कि किस भाव में तो उसने कहा कि जिस भाव में खरीदे थे उसी भाव में उसने पूछा लाभ हुआ कुछ कि नहीं तो बोला कि हुक्का लाभ हुआ है । हुजूर, वही हुक्का लेकर घूमने वाली बात हो रही है । बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार की स्थिति पर गीत बना था कि मिश्री मलाई खैलूं, कैलूं तन बुलंद, अलग भेल झारखण्ड अब खैहा शकरकन्द, अलग भईल झारखण्ड । वहां से माननीय नीतीश जी, माननीय सुशील मोदी जी के द्वारा....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी पूरी बात तो सुने नहीं । आप बैठिए-बैठिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : यह सरकार हुक्का लेकर घूम रही है ।

श्री हरिभूषण ठाकुर : विपक्ष हुक्का लेकर घूम रहा है ।

क्रमशः

टर्न-22/हेमंत-राहुल/25.02.2021

श्री हरिभूषण ठाकुर(क्रमशः): सड़क की क्या स्थिति थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, सड़क की स्थिति तो ये थी कि जब 2005 में हम भी विधायक बन कर आए थे तब सात घंटे में पटना आते थे अब दो घंटे में पटना आते हैं । शिक्षा की स्थिति क्या थी, चरवाहा विद्यालय खोला गया था, वृक्ष के नीचे पढ़ाई होती थी, कहीं भी विद्यालय भवन नहीं था...

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप बिना अनुमति के क्यों खड़े हो रहे हैं, आप बैठिए । आप बैठिए सुनील जी, बिना अनुमति के नहीं बोलिए, बैठ जाइए ।

श्री हरिभूषण ठाकुरः अध्यक्ष जी, कहीं विद्यालय भवन नहीं था । हम लोगों को सबसे ज्यादा...

(व्यवधान)

अध्यक्षः गागर में सागर भरिये, समय समाप्त हो रहा है ।

श्री हरिभूषण ठाकुरः महोदय, तनिक हम पर भी ध्यान दीजिए । अध्यक्ष जी, शिक्षा की वही स्थिति थी, स्वास्थ्य की वही स्थिति थी । महीने में जितने लोग जाते थे उससे ज्यादा लोग एक दिन में जा रहे हैं । दुनिया में क्या था, यह सही ही कहा हमसे पहले बोलने वाले वक्ता कि 30 साल की बात है, 15 साल उधर का शासन था, 15 साल हमने शासन किया । पहले क्या था इस देश में, केवल रोटी, कपड़ा और मकान की चिन्ता की जाती थी लेकिन जब से हमारी सरकार, माननीय नीतीश जी की सरकार बनी, माननीय सुशील मोदी जी और आज तारकिशोर प्रसाद नेता हैं, हमने रोटी, कपड़ा और मकान से स्वास्थ्य उसमें जोड़ा, उसमें शिक्षा को जोड़ा, उसमें संचार जोड़ा, उसमें बिजली जोड़ी, लोग कहते थे कि चिराग और अब लालटेन लेकर घूमते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप बार-बार क्यों खड़े होते हैं, बैठिए आप ।

श्री हरिभूषण ठाकुरः अब घर-घर एल0ई0डी0 बल्ब आ गया...

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप अपनी चिन्ता कीजिए, क्यों इधर-उधर जाते हैं । माननीय सदस्य बोलिए ।

श्री हरिभूषण ठाकुरः महोदय, घर-घर एल0ई0डी0 बल्ब आ गया । हुजूर संचार की व्यवस्था हुई, यहां अनुसूचित जाति की बात हुई, यहां पिछड़ी जाति की बात हुई हई है । 20-20 साल तक पंचायत का चुनाव नहीं हुआ...

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप बैठिए ।

श्री हरिभूषण ठाकुरः माननीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर गरीब-गुरबा, जिसको लोग पास बैठने नहीं देते थे, उसको मुखिया बनाया...

अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिये ।

श्री हरिभूषण ठाकुरः महोदय, कन्क्लूड कर रहे हैं, अन्त में हम यही कहेंगे कि कालीकट अधिवेशन में भारतीय जनसंघ ने जो कहा था कि हर हाथ को काम देंगे, हर खेत को पानी देंगे । यह बजट हर हाथ को काम देने वाला बजट है, हर खेत को पानी देने वाला बजट है...

अध्यक्षः ठीक है, बैठ जाइए ।

श्री हरिभूषण ठाकुरः 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला बजट है, बिहार की 12 करोड़ जनता के सपनों का बजट है, अन्त में...

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप बोलते रहिए ।

श्री हरिभूषण ठाकुरः हम भी कहना चाहते हैं...

अध्यक्षः ठीक है अब समाप्त कीजिए ।

श्री हरिभूषण ठाकुरः हम भी कहना चाहते हैं कि-

''आंखों में सुख वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो,
राष्ट्रभक्ति का ज्वार न थमता, आयी जिस-जिस में हिम्मत हो ।''

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्षः श्री रत्नेश सादा जी ।

माननीय सदस्यगण आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

श्री रत्नेश सादाः अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2021-22...

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप बैठ जाइए, एक ही बात बार-बार, पुराना कैसेट अलापने में आपको आनन्द आता है? बैठिए ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए, आप पर भी कमेंट करेंगे तो फिर अशांति होगी, बैठिए ।

श्री रत्नेश सादाः मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया जो बजट है यह बजट है 'विकास की सवारी और सबकी हिस्सेदारी' । महोदय, इस बजट में बिहार के विकास में सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का विकास छिपा हुआ है । महोदय, सभी विभागों का विकास छिपा हुआ है । महोदय, हमारी सरकार ने किसान को दोगुनी उपज के लिए उत्तम किस्म के बीज, उर्वरा शक्ति और नये तरीके की मशीन को उपलब्ध कराया है । महोदय, बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए पशुपालकों को, कहें तो पशु बिहार का दूसरा विकास का जरिया है । पशु के जरिये बकरीपालन, मधुमक्खीपालन, मछलीपालन, मुर्गीपालन इसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन करने का काम किया है । महोदय, जो छात्र पढ़ने-लिखने के लिए असमर्थ रहते थे, उनको चार लाख रुपये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन देने का काम किया है । महोदय, गांव में बेरोजगार, अतिपिछड़ा और महादलित के

पिछड़े हुए और बेरोजगार जो बच्चे थे, उनको पंचायत स्तर पर महादलित के लिए 3 टेम्पो की व्यवस्था और 2 अतिपिछड़ा बेरोजगार युवकों के लिए व्यवस्था करने का काम किया है। महोदय, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें नौकरी में भागीदारी दिलाने का काम किया है और इतना ही नहीं जीविका के माध्यम से डीलर बनाने का काम किया है । महोदय, आजकल जितने भी हॉस्पिटल में अनुबंध पर खाना रसोईया का काम होगा वह जीविका की दीदियों के माध्यम से बनेगा । महोदय, इनके समय में जो बजट था, वह बजट था । आज हमारे समय में बजट है विकास का, इनके समय में बजट था लूट का, अपहरण का, हत्या का, घोटाले का, इस तरह का बजट पास करते थे । महोदय, हमारे महादलित को, इनके समय में झूठ का पुलिंदा बांधते थे, केस कटवा देते थे, बाल धुला देते थे और हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार जब आये हैं तो एकल पद पर आरक्षण देकर के मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद और प्रमुख बनाने का काम किया है । महोदय, इतना ही नहीं बेरोजगार युवकों के लिए टोला स्वयं सेवक की बहाली की है, विकास मित्र की बहाली की है और इनके समय में साबुन से लेकर के काक्रोच बेचने वाला, चूहा मारने वाला सबकी भलाई होगी, झूठ का पुलिंदा बांध-बांधकर के 15 साल राज करने का काम किया। उस राज को तोड़ने के काम के लिए माननीय मुखिया नीतीश कुमार ने कबीर के रूप में पैदा होकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया । पहले अगर बिहारी बिहार से बाहर जाते थे....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइये ।

श्री रत्नेश सादा : महोदय, पहले अगर बिहारी बिहार से बाहर जाते थे, तो लोग नीच की दृष्टि से देखते थे लेकिन आज बिहारी कहलवाना अपमान नहीं सम्मान की बात है । इन्हें अगर सम्मान दिया है तो माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने दिया है ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये ।

श्री रत्नेश सादा : इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-23 एवं 24/ राजेश-संगीता-मुकुल/ 25.02.2021

अध्यक्ष : माननीय श्री राजकुमार सिंह, आपका एक मिनट का समय है ।

श्री राजकुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका कोटिश: आभार व्यक्त करता हूं । मेरा मानना है कि यह बजट कोरोना महामारी से आहत बिहार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम हो सकता है।

अगर इस पर बहस सार्थक हो और हमारे सभी साथी सदस्य की इस पर जो आलोचना है या उनका समर्थन है, उसका कोई आधार हो । हम सभी लोग यहां पर बिहार की महान जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और बिहार की महान जनता हम सभी लोगों की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और इसी निमित्त हमको यहां भेजा भी गया है कि उनकी तमाम आशाएं, अपेक्षाएं हमारे माध्यम से इस सदन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से पल्लवित और पुष्पित हों न कि उनकी अपेक्षाएं हमारे आचरण से, हमारे कार्यकलाप से उनकी आशाएं इसी सदन पर हम लोगों के द्वारा उन्हीं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से दम तोड़ दें । बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों का जहां समर्थन होना चाहिए मेरा मानना है कि निश्चित रूप से होना चाहिए । शिक्षा के क्षेत्र में मेरा मानना है कि शिक्षित बिहार ही विकसित बिहार की नींव रख सकता है । लेकिन इस मामले में एक बार मैं जरूर कहूंगा मैं जिस विधानसभा से आ रहा हूं वहां पर विगत 15 सालों से सत्ताधारी दल का ही प्रतिनिधित्व रहा लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मटिहानी विधानसभा में आज तक एक भी डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई । सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दे क्योंकि शिक्षा पर इस बार काफी जोर दिया गया है और खासकर महिलाओं एवं वंचित वर्ग के लोगों को । शिक्षा तभी हासिल होगा, उच्चतर शिक्षा तभी हासिल होगा जब वहां डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी । स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा एक सजेशन है कि अगर वहां पर मोबाइल क्लिनिक्स और मोबाइल लैब्स की व्यवस्था की जाय तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की व्यवस्था से लोगों को अच्छी तरह से आच्छादित किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कन्क्लूड करें ।

श्री राजकुमार सिंह: अंत में इतना कहूंगा कि हमारे आचरण इस प्रकार हों कि बिहार की महान जनता का लोकतंत्र में उनकी आस्था मजबूत हो और यही उनकी अपेक्षा भी है । हमारी तरफ से और सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को निराश न होना पड़े और लोग यह न कहें कि

''मकतल में आते हैं वो खंजर बदल बदल कर
या रब कहां से लाऊं मैं सर बदल बदल कर ।''

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श पर अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

## सरकार का उत्तर

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय,

''सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है,
उधर ही ले चलो किश्ती जहां तूफान आया है ।''

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से दिनांक 22.02.2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य का बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 का पुनरीक्षित बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया । अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के प्रमुख साथियों ने आज बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और हमारा प्रयास रहेगा कि जो उनके बहुमूल्य सुझाव हैं आने वाले दिनों में जो अच्छे सुझाव हैं, वह दिखेंगे, लेकिन पहले मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर जी, माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी, माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल जी, माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान जी, सम्मानीय बहन ज्योति देवी जी, बहन स्वर्णा सिंह जी, माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र यादव जी, माननीय सदस्य श्री सुर्यकान्त पासवान जी, माननीय सदस्य श्री हरिभूषण ठाकुर जी, माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा जी एवं माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं । महोदय, मेरी अपेक्षा थी कि राज्य के विकास के लिए समर्पित बजट 2021-22 पर इस सम्मानित सदन में विस्तृत एवं गंभीर चर्चा होती तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों से इस पर और अधिक से अधिक बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होते, लेकिन कल सदन का समय यूं ही जाया हो गया और उनके बहुमूल्य सुझाव को हम न सुन सके और न आत्मसात कर सके ।

महोदय, मैंने अपने अभिभाषण में वर्ष 2005 और 15 साल बनाम 15 साल वाले आंकड़ों पर चर्चा नहीं की थी क्योंकि इस बजट में भविष्य के आत्मनिर्भर बिहार की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, किन्तु नेता प्रतिपक्ष ने 15 साल बनाम 15 साल आंकड़ों का आईना दिखाकर मुझे 15 साल बनाम 15 साल के आंकड़ों को इस सदन में प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया है । महोदय, जब हम आईना की बात करते हैं जिसकी चर्चा नेता प्रतिपक्ष ने की है तो आपके आईने में जर्जर सड़कें थीं, आपके आईने में सदर अस्पताल के बेड पर जानवर सोया करते थे, आपके आईने में नदी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय सदस्य, बैठिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : आपके आईने में पुलों की जगह चचरी थी लेकिन महोदय, मैं कुछ और पीछे चलना चाहता हूं । मैं तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय की ओर प्रारंभ करने की इच्छा है लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने कुछ चीजों का जवाब भी मांगा है । सरकार का दायित्व है और जब प्रतिपक्ष सरकार का अंग होता है तो मुझे उस अंग को भी देखना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा । वर्ष 2005-06 में गैर योजना मद में 17 हजार 669 करोड़ रूपया था । राज्य योजना मद में 4 हजार 379 करोड़ रूपये और कुल योजना मद में 4 हजार 898 करोड़ रूपया था जबकि कुल बजट का आकार 22 हजार 568 करोड़ रूपया था । महोदय, यदि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो राज्य योजना कुल बजट का 19 प्रतिशत एवं योजना आकार का कुल बजट का 21 प्रतिशत था । किसी भी राज्य के विकास का योजना मद में प्रावधानिक राशि से होता है और केवल 21 प्रतिशत योजना मद में रखा जाय तो राज्य का क्या विकास होगा, यह सदन और हमारे पुराने साथी अच्छी तरह जानते हैं । अगर यही आंकड़ा वर्तमान बजट के बारे में हम इस सदन के सामने प्रस्तुत करें तो 2020-21 में राज्य योजना 1 लाख 5 हजार 262 करोड़ रूपया है । गैर योजना मद में 1 लाख 5 हजार 995 करोड़ रूपया है । कुल योजना आकार 1 लाख 5 हजार 766 करोड़ रूपया एवं कुल बजट आकार 2 लाख 11 हजार 761 करोड़ रूपया है । यदि योजना मद का बजट का प्रतिशत निकाला जाय तो यह कुल बजट का 50 प्रतिशत होता है । इस सदन को 50 प्रतिशत बनाम 21 प्रतिशत करनी चाहिए न कि आंकड़ों का जंजाल प्रस्तुत करके राज्य के विकास पर संदेह व्यक्त करना चाहिए । जहां तक परकैपिटा लोन की बात है राज्य सरकार लोन अपने जी0एस0डी0पी0 के आधार पर लेती है जिसकी सीमा एफ0आर0बी0एम0 एक्ट से निर्धारित है यह नेता प्रतिपक्ष भलीभांति जानते हैं लेकिन उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया । जहां तक फरवरी माह का एक्सपेंडिचर है, अभी तक अद्यतन व्यय 1 लाख 41 हजार करोड़ रूपया हो गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर होने वाले व्यय के संबंध में जो आंकड़ा दिया, वर्ष 1983 का जो आंकड़ा दिया, वह पूर्णरूप से भ्रामक है, यह सदन को गुमराह करने वाला है । सभी विभागों के बजटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राशि कर्णांकित की गई है । जो उस विभाग का 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए और 1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमानतः 16 प्रतिशत और 1 प्रतिशत होता है । अतः नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़ों का जंजाल पेश कर इस सदन को भ्रमित करने की कोशिश की है । जहां तक महिलाओं एवं नौजवानों एवं बेरोजगारी की बात है अब इस बात को हम विस्तार से भी रखना चाहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण एक तरफ जहां वर्ष 2020 में राजस्व प्राप्तियों में कमी आई, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण तत्काल आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोक व्यय में वृद्धि की गई है । वर्तमान परिस्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार द्वारा इस बजट के माध्यम से बिहार की आर्थिक व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जाये और जिस गौरवशाली विकास पथ पर बिहार चल रहा था, उसी पथ को पुनः पकड़ने का प्रयास किया गया है । अध्यक्ष महोदय, बिहार के सतत् विकास के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना प्रारंभ की गयी थी । इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य- आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली-नलियां, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़ें, ऐसे निर्धारित किए गए थे । 7 निश्चय योजना के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों को मैंने आपके माध्यम से सदन के समक्ष अपने अभिभाषण में रखा है । इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन कार्यों को पूर्ण किया जाना है और सृजित परिसंपत्तियों का रख-रखाव भी किया जाना है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों के लिए हमने आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय-2 के अंतर्गत 7 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसकी चर्चा मैंने अपने बजट भाषण में की है । युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त सुविधा । महोदय, यह अचानक नहीं हुआ है । हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल एवं सबल नेतृत्व में आज हम यहां तक पहुंचे हैं ।

''मंजिल यूं नहीं मिलती राही को,
जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है ।
पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है,
चिड़िया बोली तिनका-तिनका उठाना पड़ता है ।''

यह विगत 15 वर्षों की दास्तां है,

''दिवाली यूं ही नहीं मन गई,
दीया को रातभर जलना पड़ा है ।''

ये 15 वर्ष लगातार हम अपने कुशल नेतृत्व में और अपने साथियों के कुशल नेतृत्व में बिहार को ऐसे पायदान पर लाया है कि आज विकासशील बिहार से हम विकसित बिहार के करीब पहुंच चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, युवा हमारे लिए राज्य की बहुमूल्य पूंजी

है। अतः राज्य के युवाओं के लिए इस बजट में अनेक कार्यक्रम हम सबों ने निर्धारित किया, युवाओं की शिक्षा, प्रशिक्षुता और युवा उद्यमिता विकास पर हमारा विशेष ध्यान है ताकि हम युवा बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक तकनीक वाले रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ सके । युवाओं के लिए अब बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण, आधुनिक और गुणवत्ता वाले तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं आधुनिक यंत्रों एवं टूल्स पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी । जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें । महोदय, हमारे अपने युवा केवल रोजगार की तलाश में रहें, ऐसा नहीं है हम चाहते हैं कि वे रोजगार के सृजनकर्ता भी बनें । इसलिए युवाओं को सफल उद्यमी बनाने हेतु युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है बल्कि अपने उद्यम, व्यवसाय को खड़ा करने के लिए उन्हें पूर्व में अपने अभिभाषण में भी विस्तार से जिक्र किया था उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि इन कार्यक्रमों से युवाओं के स्किल का अपग्रेडेशन होगा तथा उनमें उद्यमिता की भावना भी उत्पन्न होगी । इसके लिए राज्य की, इससे न केवल राज्य की, अपने राष्ट्र की उन्नति में भी इनका योगदान होगा, क्योंकि बिहार बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा इस परिकल्पना को हम लेकर चलना चाहते हैं । हम बिहार को और ऊंचाई पर ले जाकर भारत की जो गरिमामयी एक छवि बनी है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि जब हमारे नेता बिहार को इस मुकाम पर पहुंचा रहे हैं और करीब हैं, एक विकसित राज्य की परिकल्पना जो हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने की थी वह परिकल्पना आने वाले पांच वर्षों में साकार होने वाली है । हम जो सपना देखते हैं उन सपनों को साकार रूप करते हैं । हम बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, बोलकर उन्हें ऐसे सपने दिखाकर उनके विकास को अवरुद्ध नहीं करते हैं । हमारी सरकार ने समाज के सभी तबकों के लिए चाहे वह समाज का कमजोर वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे महिलाएं हों, सबों के लिए जो कार्यक्रम तय किया है उसी का यह परिणाम है । हमारी मुनिया साइकिल टुन-टुना कर स्कूल जाती है यह एक दिन में नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमारे नेता ने परिश्रम किया है । हमारे जो साथी बैठे हैं उन्होंने परिश्रम किया है । आज मुनिया वैसे साइकिल टुन-टुना कर नहीं जाती है, घंटी टुन-टुना के, पहले बच्चियां पांचवीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ती थीं, आज ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां इंटरमीडिएट पास कर रही हैं, ग्रेजुएशन पास कर रही हैं, यह है बिहार का आने वाला भविष्य और तकदीर । महोदय, राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने के बाद क्षेत्रीय प्रशासन ने...

(व्यवधान)

पुलिस थाना प्रखंड और मंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप समानुपातिक रूप से महिलाओं की संख्या बढ़ाएगी ।

(व्यवधान जारी)

स्थानीय निकायों में पहली बार महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद राज्य सरकार ने सात निश्चय-1 में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित किया है । पूरे भारत में बिहार ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो मुकाम बनाया है, आज पूरा भारतवर्ष उसका अनुसरण कर रहा है ।

(व्यवधान जारी)

इसी प्रकार अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को उनके द्वारा लगाये गये उद्यमों में...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: उप मुख्यमंत्री जी, एक मिनट । आप सब लोग बैठें । आसन देख रहा है, आप सब लोग बैठिए। आप सब लोग बैठिए, आसन देख रहा है । मौका नेता प्रतिपक्ष को मिलेगा, यह अच्छी स्थिति नहीं है । आसन देख रहा है, फिर आप लोग आसन को प्रभावित करेंगे । ये उचित नहीं है । नेता प्रतिपक्ष आप 1 मिनट में बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, हमने जो आंकड़ा दिया, पिछड़ा विभाग का, अति पिछड़ा विभाग का, एस0सी0/एस0टी0 विभाग का, माइनोरिटी विभाग का । हमने आंकड़ा जो हम पर आरोप लगाया डिप्टी सी0एम0 साहब ने, वित्त मंत्री ने हम सबूत लाए हैं । यह आप ही का बजट का वर्ष 2021-22 का है महोदय । ये आप खोलकर के देखें तो अति पिछड़ा विभाग का महोदय 0.80 बजट प्रतिशत है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अब आप इसे देखकर क्या कीजिएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अब उनके आंकड़ों को देखकर बिहार कब तक आगे बढ़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप अगर जो बार-बार उठेंगे तो आसन फिर आपके प्रति सोचेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ही बजट पेश किया है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, अब तो सरकार के आंकड़े बिहार को आगे बढ़ायेंगे, नेता प्रतिपक्ष के आंकड़े बिहार को आगे नहीं बढ़ायेंगे, इस बात को समझने की जरूरत है पूरे सदन को ।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, पेपर में देखिए, छपा हुआ है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय,

''जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का ।
फिर देखना फिजूल है कद आसमान का ।।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जहां एक ओर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन किया गया, वहीं दूसरी ओर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कई कार्यक्रम प्रारंभ किये गये । काष्ठ से संबंधित क्षेत्र में भी अनेक कार्यक्रम आरंभ किये गये जिनका कार्यान्वयन पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा संचालित किया जायेगा । सरकार की मंशा है कि उद्योग के साथ कृषि एवं मत्स्य संसाधन, वन विभाग के साथ अन्य सभी विभाग मिलकर अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कागजात देना चाहता हूं ।

अध्यक्षः ठीक है, आप इसे सचिव साहब को दे दें ।

(व्यवधान जारी)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सरकार का वक्तव्य हो रहा है नेता प्रतिपक्ष बिहार के विकास से काफी घबराये हुए हैं । नेता प्रतिपक्ष बिहार के विकास से घबराये हुए हैं । उन्होंने वर्ष 2005 के पूर्व के बिहार की याद दिलाकर बिहार की दुखती रग को छेड़ने का काम किया और आज यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है । वर्ष 2005 के पहले का अगर बखान शुरू करें तो 2-3 घंटे लग जायेंगे, वर्ष 2005 के पहले का बिहार क्या था ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-25/सत्येन्द्र/25-2-21

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री(क्रमशः) अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जहां एक ओर काष्ठ से संबंधित क्षेत्र में भी अनेक कार्यक्रम आरम्भ किये गये जिनका कार्यान्वयन पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा संचालित किया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, सरकार का बजट है, सरकार पढ़ रही है, नेता प्रतिपक्ष के नाते, नेता प्रतिपक्ष को जो पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया और ...

अध्यक्षः हाँ, अब आप पढ़िये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: और बिहार को गढ़ने का काम हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, पहले सुन लें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, बिहार के विकास को गढ़ने का काम किया है नीतीश कुमार ने, आंकड़ों के खेल में बिहार का विकास नहीं होगा बिहार का विकास संकल्प से सिद्धि की ओर होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: एक मिनट उप मुख्यमंत्री जी । माननीय सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष जितना समय चाहे बोले, सबने ध्यान से सुना है। सदन की गरिमा इसी में बढ़ती है कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की बात को सुनें और जब नेता बोल रहे हैं (व्यवधान) आप लोग एक चीज पहले तय कर लीजिये कि आपके नेता बोलेंगे या आप लोग बोलियेगा ? आप बैठ जाइये । गरिमा सदन की रहने दीजिये, बीच बीच में जो सदस्य उठेंगे, हम चिन्हित करवा रहे हैं, अभी प्रारंभिक दौर है। बार-बार संकेत कर रहे हैं, ऐसी आदत मत बनाइये। नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, सदन नेता बोलते हैं, ध्यान से सुनिये । बोलिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के साथ-साथ आम आदमी की भी अपेक्षा है कि राज्य में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित हों ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आश्वासन दिखवा लिया जायेगा, बैठ जाइये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, मेरी आशा है कि उपर्युक्त प्रयासों से वर्ष 2020-2025 में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नये अवसर सृजित किये जायेंगे । राज्य में कृषि उत्पाद में वृद्धि एवं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रत्येक खेत में किसी न किसी एक माध्यम से सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी । समाज के कमजोर वर्गों के लिए दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन, मछलीपालन जैसे व्यवसाय गांवों में रोजगार के साधन होते हैं, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होती है । आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गीपालन, मछलीपालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

राज्य में स्थिर चौर क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जाएगा । मछली उत्पादन को इतना बढ़ायेंगे कि बिहार की मछली दूसरे राज्यों में जायेगी । प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था करने जा रहे हैं । पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण,

कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था हमारी सरकार करने जा रही है । टेली मेडिसीन के माध्यम से भी पशु अस्पताल से जुड़ेंगे जिससे कि चिकित्सा परामर्श दिया जा सकेगा । आवश्यकतानुसार मोबाईल यूनिट्स के माध्यम से पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा लोगों के घरों में पहुंचकर पशु चिकित्सा एवं अन्य सेवाएं देने का हमने संकल्प लिया है । पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्साएं नि:शुल्क की जायेगी जिससे ग्रामीण अर्थव्यस्था में एक गुणात्मक परिवर्तन आयें । देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना हमारी सरकार करेगी । गांव की गलियां एवं सड़कें शहरों की तरह जगमग करती रहे इसलिए सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने एवं लगाये गये सोलर स्ट्रीट लाईट के नियमित अनुरक्षण की व्यवस्था की योजना हमारी सरकार ने प्रारंभ ने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरों से विभिन्न प्रकार के ठोस और तरल अपशिष्ट । असल में, आपकी हमारी पहले की बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए दोहराना पड़ रहा है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी,आसन को देखें, आसन को देखकर बोलें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरों से विभिन्न प्रकार के ठोस और तरल अपशिष्ट निकलते हैं। ग्रामीण स्तर पर इससे एक तरफ जहां बीमारी का खतरा बना रहता है।

(व्यवधान)

वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है । इसलिए गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जायेगी । घनी आबादी के कारण शहरी घरों से ठोस और तरल अपशिष्ट बड़ी मात्रा में निकलते हैं, जिनसे बीमारी और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं इसलिए बिहार के सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से की जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: क्या कह रहे हैं आप ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: राज्य सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन योजनाओं के अंतर्गत शहर में रह रहे बेघर, भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बनाकर आवासन उपलब्ध कराया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृहों सहित मोक्षधाम का निर्माण कराया जायगा जिससे दाह संस्कार हेतु जरूरी सुविधाएं मिल सके ।

(व्यवधान)

सभी शहरों में स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जायेगा जिससे कि जल-जमाव की कोई समस्या नहीं हो । अध्यक्ष महोदय, हम राज्य के वृद्धजनों का सम्मान करते हैं । सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण योजना के अंतर्गत वृद्धजनों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जायेगा । इससे बेहतर प्रबंधन और संचालन की व्यवस्था की जायेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ संपर्कता योजना के अंतर्गत आस-पास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थानों अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं यथा बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक सम्पर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य वेल में आ गये)

शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण हम करने जा रहे हैं ।

स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी तथा इन्हें टेलीमेडिसीन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ा जायेगा और लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

(व्यवधान जारी)

डायबिटीज, उच्च रक्तचाप तथा मोतियाबिंद आदि बीमारियों हेतु स्क्रीनिंग की जाएगी एवं गंभीर बीमारी के मामलों को रेफर किया जाएगा । इसके साथ ही पैथोलॉजिकल जांच हेतु सेम्पल एकत्र कर उनकी जांच की भी व्यवस्था की जाएगी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और भी बेहतर एवं विस्तारित किया जाएगा ।

(व्यवधान जारी)

राज्य सरकार के द्वारा बिहार के विकास एवं लोगों के कल्याण हेतु पूर्व से संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को वर्ष 2021-22 में और सुदृढ़ करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, दिनांक 22.02.2021 को मैंने राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा स्कीम व्यय मद में प्रस्तावित बजट की विवरणी, इस सदन के पटल पर रखा था । इस महान सदन के सम्मानित सदस्यों द्वारा विभिन्न विभागों

के अनुदानों की मांग पर विचार विमर्श किया जायेगा एवं सर्वसम्मति से लिये गये निर्णयों पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विभागवार अनुदानों की मांग पर विचार विमर्श हेतु हम इस सदन के माननीय सदस्यों को आमंत्रित करते हैं । अध्यक्ष महोदय, अंत में –

''विरासत से तय नहीं होंगे, सियासत के फैसले,
उड़ान तय करेगी कि ये आसमां किसका है ।''

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

बैठिये आप लोग, आसन को गाईड मत करिये ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 51 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....